

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

10 मार्च, 1981

खण्ड 1, अंक 2

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मंगलवार, 10 मार्च, 1981

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(2)1
तारांकित प्र न संख्या 1972 पर आधे घंटे की चर्चा की मांग	(2)24
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(2)25
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(2)27
श्री रण सिंह मान, एम0एल0ए0 की रिहाई संबंधी	(2)36
वाक आउट	(2)38
ध्यानाकर्षण सूचना— बिजली की कमी तथा चोरी के परिणामस्वरूप जनता को असुविधा होने तथा इसका अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव पड़ने संबंधी	(2)40
सदन की मेज पर रखे गये कागज—पत्र	(2)43
बिलज (इन्ट्रीड्यूसड—सदन की अनुमति से)	

(i) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फैसिलिटीज टू मैम्बर्ज) अमेंडमेंट बिल, 1981	(2)44
(ii) दि हरियाणा स्टेट लैजिस्लेचर (प्रिवैन् इन आफ डिस्कवालिफिके इन) अमेंडमेंट बिल, 1981	(2)44
(iii) दि हरियाणा एसैनि टायल सर्विसिज मैटिनेंस (अमेंडमेंट) बिल, 1981	(2)46
वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 के एक्सैस डिमांड्ज ओवर ग्रांटस एंड एंड एप्रोप्रिए ांज प्रस्तुत करना	(2)49
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा	(2)49

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 10 मार्च, 1981

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चन्डीगढ़ में प्रातः 9:30 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

Veterinary and Stockmen Centres

***1937. Shri Gulzar Singh:** Will the Minister for Jails and Dairy Development be pleased to state the number of Veterinary Health Centres and Stockmen Centres opened in Rajound constituency during the year 1980-81?

जेल तथा डेरी विकास मंत्री (चौधरी ि तव राम वर्मा):
वर्ष 1980-81 में राजौंद गांव क्षेत्र में कोई प डु
औशधालय/प डुधन केंद्र नहीं खोला गया है।

श्री गुलजार सिंह: क्या मिनिस्टर साहब यह बताने का
कश्ट करेंगे कि राजौंद हल्के में बीस से ज्यादा गांव ऐसे है

जिनकी आबादी 15,000 से भी ऊपर की है, वहां पर न कोई पंजु हस्पताल है और न ही कोई पंजुधन केंद्र है जबकि नीलोखेड़ी में हरेक छोटे-छोटे गांवों में स्टाकमैन सैंटर्ज खोले हुए, इसका क्या कारण है? (पेम्-पेम् की आवाजें)

चौधरी विठ्ठल राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह बिल्कुल गलत कहा कि नीलोखेड़ी में हरेक गांव में इस तरह के स्टाकमैन सैंटर्ज खोले हुए हैं। हमारे पास यह इनफर्मेसन कांस्टीच्युएन्सी-वाइज तो रिकार्ड नहीं होती, तहसील-वाइज होती हैं फिर भी हमने इस बात की कोशिश की है कि यह इनफर्मेसन इक्वटी की जाये कि कांस्टीच्युएन्सी वाइज कितने खोले गये हैं। किसी जगह न खुलने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि वहां से कोई से कोई..... ही न आयी हो, या जरूरत न समझी गयी हो, या सरकार के पास धन अवेलेबल न हो या फैक्टर्ज अवेलेबल न हों। इस तरह से कई कारण हो सकते हैं, इन्हीं कारणों से इनकी कांस्टीच्युएन्सी के गांव रह गये होंगे।

श्री अध्यक्ष: एक बात की तो मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वैस्ट करूंगा कि मांग आने से कोई जरूरत नहीं होनी चाहिये।

मुख्य मंत्री(चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, रजौंद हल्कें में 13 हस्पताल आलरेडी है लेकिन वहां की जरूरत के मुताबिक 14 चाहिये। एक अगले साल में खोल दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री गुलजार सिंह जी, आपके यहां 13 तो आलरेडी खुले हुए हैं।

श्री गुलजार सिंह: सर, 15,000 से ऊपर आबादी के गांव हैं, जिनमें अभी जरूरत है।

श्री अध्यक्ष: 13 तो आलरेडी हैं और मुख्य मंत्री जी ने यह आवासन दिया है कि एक और खोल दिया जायेगा।

श्री बीरेंद्र सिंह: मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि नीलोखेड़ी कांस्टीच्युएन्सी में पिछले दो सालों में कितने स्टाकमैन सैंटर्ज खोले गए हैं?

Mr. Speaker: Chaudhri Sahib, this question is about Rajound constituency and not about Nilokheri. (Interruptions).

चौधरी िव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, इस प्र न का मेन प्र न से कोई संबंध नहीं है।

श्री अध्यक्ष: वैसे मैं यह सोच रहा था कि कोई फिर यह पूछेगा कि आपने अपने हल्के नारनोंद में कितने बनवाये थे। (हंसी)

श्री बीरेंद्र सिंह: जी जरूर पूछिये। (व्यवधान व भाोर)

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मेरे हल्के में सौलदा गांव में दो साल से चौपाड़ में नींव पत्थर पड़ा हुआ है।

जब चीफ मिनिस्टर भजन लाल जी के पास यह डिपार्टमेंट होता था, उस वक्त का यह रखा हुआ है। वह गांव फ्लड इफैक्टिड एरिया में आता है। मैंने इस बारे में मुख्य मंत्री, मंत्री व डायरेक्टर साहब को भी चिट्ठियां लिखी है लेकिन अब तक वहां पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। क्या सरकार वहां पर जल्दी ही हस्पताल बनाने का कश्ट करेंगी?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, अगर कहीं पर भी ऐसा पत्थर पड़ा हुआ है तो हम वहां पर जरूर हस्पताल बनवायेंगे।.....(व्यवधान व भाोर)

चौधरी िव राम वर्मा: स्पीकर साहब, वैसे चौधरी उदय सिंह दलाल साहब के प्र न का इस मेन सवाल से संबंध नहीं है लेकिन फिर भी मुख्य मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया है।

श्री सुरेंद्र सिंह: स्पीकर साहब, जो इलाके अकाल पीड़ित है, जहां पर गरीब लोग रहते है.....

Mr. Speaker: Chaudhri Sahib, the question is about Rajound.

Shri Surender Singh: But, Sir my question is about the same department and it is a very relevant question. I think you would also appreciate it. ऐसे गांव जिनकी आबादी 15-20 हजार तक की है लेकिन वे इतने गरीब है कि अपनी बिल्डिंग बनाकर नहीं दे सकते, क्या सरकार वहां पर भी अपनी

तरफ से बिल्डिंग बनाकर कोई हस्पताल/स्टाकमैन सेंटर खोलने का कष्ट करेगी?

चौधरी विठ्ठल राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, बिल्डिंग बनाने के लिये सरकार के पास धन नहीं हैं। लेकिन जहां पर कोई गांव हमें बिल्डिंग और दूसरी अकोमोडेशन दे देता है, हम वहां पर हस्पताल या स्टाकमैन वगैरह कुछ न कुछ खोल देते हैं, बस तर्क कि वहां पर जरूरत हो और वहां की मांग हो। (व्यवधान व भाोर)

चौधरी राजेंद्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जैसे हमारे यहां कानफैड वालों की एक स्कीम चलायी गयी है कि 2,000 की आबादी वाले गांवों में वे अपने सेंटर/डिपो खोल देंगे। क्या उसी तरह फ्लड इफैक्टिड एरियाज में जहां पर लोग बहुत गरीब हैं, कोई हस्पताल या स्टाकमैन सेंटर खोलने का सरकार का विचार है?

Mr. Speaker: Chaudhri Rajinder Singh Ji, this has got nothing to do with the main question.

चौधरी राजेंद्र सिंह: मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जो गांव हरियाणा में 2,000 की आबादी या इससे ज्यादा के हैं, क्या वहां पर स्टाकमैन सेंटर खोलने की सरकार की अपनी तरफ से कोई प्रोजेक्ट है?

चौधरी विठ्ठल राम वर्मा: हमारी सरकार के मन में तो ऐसी बात है। पहले तो ऐसा नहीं था जब चौधरी बीरेंद्र सिंह जी

की सरकार थी। इन्होंने तो 20 से 21 हस्पताल नहीं बनाये थे लेकिन हमारी सरकार ने पिछले साल 20 की बजाये 100 डिस्पेंसरियां और 100 स्टाकमैन सेंटज खोले है। इस साल 20 की बजाये 50 डिस्पेंसरिया खोली है। पिछले साल बीस हस्पताल अपग्रेड किये थे और इस साल 50 अपग्रेड कर रहे है। हम को ि ि कर रहे है लेकिन हरेक गांव में तो भायद अभी सम्भव नहीं होगा क्योंकि यह धन की और डाक्टरों की उपलब्धि पर निर्भर करता है। फिर भी हम ज्यादा से ज्यादा और नजदीक से नजदीक स्थान पर प ़ुओं के इलाज की सुविधायें देने का प्रयत्न कर रहे है।

चौधरी हरस्वरूप बूरा: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन गांवों ने बिल्डिंग बनाकर दे दी है, क्या वहां पर जल्दी ही डिस्पेंसरियां खोल दी जायेगी? मेरे हल्के में कई ऐसे गांव है जहां पर बिल्डिंगें बनकर तैयार हो गयी है।

चौधरी ि िव राम वर्मा: सब के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन हम को ि ि करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे गांवों में हस्पताल/डिस्पेंसरियां खोलें जिन्होंने हमें बिल्डिंगें बनाकर दे दी है। फिर भी सरकार इस बारे में विचार करेगी।

श्री कंवल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर साहब ने यह कहा है कि गांव वाले बिल्डिंग बना कर दें तो हम वहां पर डिस्पेंसरी खोल देंगे। स्पीकर साहब, यह गलत बात है कि गांव

वाले बिल्डिंग बना कर देंगे तो वहां पर डिस्पेंसरी खोलेंगे। गवर्नमेंट भाहरों में तो हस्पताल की बिल्डिंग भी खुद बनाती है और हस्पताल या डिस्पेंसरी भी खुद खोलती है?

श्री अध्यक्ष: क्या यही तरीका है कि बिल्डिंग गांव वालों को बनानी पड़ती है?

चौधरी शिव राम वर्मा: सर, इस बारे में कोई हार्ट एंड फास्ट रूलज तो नहीं है लेकिन कोशिश की जाती है कि जहां से मांग आये और जहां पर जरूरत हो क्योंकि बगैर जरूरत के मांग नहीं आती, उस मांग पर विचार करते हैं और विचार करते समय सरकार के साधनों को भी ध्यान में रखा जाता है। यह भी सोचा जाता है कि धन और डाक्टर जिनकी जरूरत पड़ेगी, क्या वह अवेलेबल होंगे?

श्री अध्यक्ष: अगर कहीं से मांग आये तो क्या किसी को कोई पैसा भी जमा करवाना पड़ता है?

चौधरी शिव राम वर्मा: सर, पैसा तो जमा नहीं करवाना पड़ता लेकिन उनको बिल्डिंग, चार दीवारी और स्टाफ के रहने के लिये कुछ क्वार्टर्ज बनाकर देने पड़ते हैं।

Telephone connection in the Canal Rest House at Yamuna Nagar

***1936. Chaudhri Har Swarup Bura:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether there is a permanent telephone connection in the Canal Rest House at Yamuna Nagar; if so, since when, if not, the reason therefor;

(b) the details of the temporary connections taken by the Department for the use of the V.I.Ps who visited and stayed in the said Rest House since June, 1977 to-date together with the total amount of expenditure incurred thereon during the same period; and

(c) the approximate expenditure likely to be incurred on the installation of the phone on permanent basis in the said Canal Rest House?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(सरदार तारा सिंह):

(ए): नहीं। तथापि यह विषय सरकार के विचाराधीन है।

(बी) अनेकों अवसरों पर वी०आई०पी० यमुनानगर विश्रामगृह में ठहरे हैं और जून, 1977 से अब तक अस्थाई टेलीफोन लगाने के लिये कुल रूपये 3270 की राशि का भुगतान टेलीफोन प्राधिकारी को किया गया है।

(सी) ओ०वाई०टी० स्कीम अधीन स्थाई टेलीफोन की स्थापना का अनुमानित व्यय रूपये 5010/- होगा तथा 22000/- रूपये का प्रति वर्ष आवर्तक खर्च होने की आशा है।

चौधरी हरस्वरूप बूरा: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि रैकरिंग खर्चा प्रति वर्ष बाईस हजार रूपया आयेगा। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने बाईस हजार

का खर्चा किस आधार पर ऐण्टीसिपेट किया है जबकि टेलीफोन की इंस्टालेशन पर केवल पांच हजार रूपया खर्च आता है?

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, दो होल टाइम अटैंडेंट लगाने पड़ते हैं, उसके बाद डेली काल्ज और ट्रंक काल्ज होती है। इस तरह से हमने अन्दाजा लगाया है कि बाईस हजार रूपया सालाना खर्च आएगा।

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, जब यह महकमा राठी साहब के पास था तो ये कैनाल रैस्ट हाउस सोहना गए थे और इन्होंने यह एलान किया था कि यहां पर टेलीफोन लगाया जाएगा। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर कब तक टेलीफोन लगा दिया जाएगा? वह डिप्टी स्पीकर साहब की कांस्टीच्युएंसी है।

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, हमें डिप्टी स्पीकर साहब का पूरा अहतराम है। जब ये कहेंगे तभी हम लगा देंगे।

श्री मूलचंद मंगला: स्पीकर साहब, रैस्ट हाउसिज में वी० आई० पी० आते हैं और उनकी प्राईवेट काल्ज होती है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उनकी प्राईवेट काल्ज का खर्चा गवर्नमेंट बर्दास्त करती है या उनसे चार्ज किया जाता है अगर उनसे चार्ज किया जाता है तो उनके जिम्मे कितना बकाया पड़ा है?

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, वी० आई० पी० का टेलीफोन का खर्चा सरकार बर्दा त करती है। वहां पर चीफ मिनिस्टर साहब भी जाते है, गवर्नर साहब भी जाते है। जब तक प्राईवेट काल की एन्टरी न हो तब तक डिट्रमिन नहीं किया जा सकता कि काल प्राईवेट है या औफि रियल है।

श्री अध्यक्ष: मुझे यकीन है कि जो वी० आई० पी० रैस्ट हाउस में ठहरते है और अगर वे प्राईवेट काल्ज करते है तो प्राईवेट काल्ज का खर्चा तो वे खुद देते है?

श्री लहरी सिंह मेहरा: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री महोदय जब पिछली बार दौरे पर यमुना नगर गए थे तो वहां पर इनसे पब्लिक मिली थी। उस समय मुख्य मंत्री महोदय ने ऐलान किया था कि यमुना नगर कैनाल रैस्ट हाउस में जल्दी से जल्दी टेलीफोन लगवा दिया जाएगा। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर कब तक टेलीफोन लगा दिया जाएगा?

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, इस बारे में डिपार्टमेंट ने दो बार लिखा है। सरकार विचार कर रही है आया इतना खर्चा बर्दा त करना चाहिए या नहीं।

Steps taken to prevent floods in Hassangarh Consituency

***2058. Chaduhri Sant Kanwar:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether the Government has taken any steps to save the Hassangarh Constituency from floods; if so, the details of the measures taken so far; and

(b) the expenditure so far incurred for the purpose referred to above during the period from 15th June, 1977 to 1st November, 1980?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(सरदार तारा सिंह):

(क) हां, क्षेत्र को तत्काल राहत देने के लिये वर्तमान मुख्य ड्रेनों की क्षमता अढ़ाई गुणा से चार गुणा बढ़ा दी गई है। स्थानीय पानी इक्ठ्ठा होने के स्थानों/निचानों का पानी निकालने के लिये लिंक ड्रेनों का निर्माण कर दिया गया है। जो गांव बाढ़ के दौरान धिर जाते है और अधिक रूप से बाढ़ ग्रस्त होते थे, उनको ईर्द-गिर्द रिंग बांध बना दिये गये है।

(ख) 15-6-1977 से 1-11-80 तक कुल 80.05 लाख रूपये का खर्च किया गया है।

श्री बीरेंद्र सिंह: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ड्रेज की कैपेसिटी अढ़ाई गुणा से चार गुणा किस साल में की है?

श्री अध्यक्ष: भायद जब आप मिनिस्टर होंगे तभी हुई होगी।

सरदार तारा सिंह: मैं यह मान लेता हूँ कि आपकी सरकार ने बढ़ाई है। स्पीकर साहब, सरकार का मतलब सरकार है चाहे वह कोई भी सरकार हो।

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, ड्रेज की कैपेसिटी तो चार गुणा हमारी सरकार के समय में बढ़ा दी गई थी लेकिन मेरे हल्के में मोरखेड़ी, समयाना, पाकस्मा, बलियाना और सांपला में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी खड़ा रहता है क्योंकि इस जमीन का लैवल ड्रेन के लैवल से नीचे है। इसलिए क्या मंत्री जी परमानेंट पम्प हाउस बना कर पानी निकालने का प्रबंध करेंगे?

श्री अध्यक्ष: यह तो इनके (श्री बीरेंद्र सिंह) समय में बढ़ाई गई है। इसका जवाब तो ये भायद ज्यादा अच्छा देंगे।

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, हमने ड्रेन्ज के अलावा रिंग बाध बनवाए हैं और नीची जगह पर पम्प लगाकर पानी खींचा है। स्पीकर साहब, नीची जगह पर पम्प लगाकर पानी खींचने पर हमने 24 लाख रूपया खर्च किया है।

चौधरी बीरेंद्र सिंह: स्पीकर साहब, जब चौधरी देवी लाल की सरकार थी उस समय फ्लडज के लिए 138 करोड़ रूपए का मास्टर प्लान तैयार किया गया था और यह आ वासन दिया गया था कि दो साल के अन्दर मास्टर प्लान का सारा काम पूरा हो जाएगा। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिस रफ्तार से यह काम हो रहा है जैसे पंद्रह या बारह करोड़ रूपया

इस हैड में दिया जा रहा है और जो फल्ट कंट्रोल मैयर्ज इन हैड है चाहे वे जींद में है या कहीं और है, अगली बारि 1 आने से पहले पूरे हो जाएंगे?

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, मेरे फाजिल दोस्त ने जो सवाल पूछा है वह इस क्वै चन में नहीं आता है। इस वक्त मेरे पास मास्टर प्लान तथा दूसरी डिटेल्ज नहीं है।

चौधरी हरि चंद हुड्डा: स्पीकर साहब, चाहे हसनगढ़ कांस्टीच्युएं पी हो या और कोई कांस्टीच्युएंसी हो, जब से यह सरकार आई है इस ने न तो कोई बांध बनाया है और न ही कोई नाला खोदा है। इस सरकार ने कोई ड्रेन नहीं बनाई है।
(व्यवधान)

मुख्य मंत्री(चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, मैं सदन के सामने कुछ आंकड़ें रखना चाहता हूं जिससे पता लग सके कि इस सरकार ने कितना काम किया है और कितना काम नहीं किया है। (व्यवधान)

चौधरी संत कंवर: स्पीकर स्पीकर साहब, मैं चैलेंज करता हूं कि इस सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया है।
(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इसमें कोई चैलेंज वाली बात नहीं है। यह चैलेंज आवर नहीं है यह क्वै चन आवर है।

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, मैं आंकड़े बता रहा हूँ कि 138 करोड़ रूपए को किस तरह से खर्च कर रहे हैं। स्पीकर साहब, 1975-76 में 133 लाख रूपया, 1976-77 में 3 करोड़ 49 लाख रूपया, 1977-78 में 24 करोड़ 90 लाख रूपया, 1978-79 में 20 करोड़ 16 लाख रूपया, 1979-80 में 19 करोड़ 55 लाख रूपया और 1980-81 में 17 करोड़ 50 लाख रूपया खर्च किया है। स्पीकर साहब, मैं हाउस को वि वास दिलाना चाहता हूँ कि 80 प्रति ात लोगों को बाढ़ से बचाने का काम मुकम्मल हो चुका है। 20 प्रति ात काम बाकी है। हमारी पूरी को ि ा है कि अगली बरसात तक सब जगह बांध बना दिए जाएं और बाढ़ का इंतजाम कर दिया जाए।

Compensation for the land acquired for the construction of Canals in District Bhiwani

***1946. Shri Surender Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the total amount of compensation to be paid for the land acquired for the construction of canals and other distributaries, minors and sub-minors in Bhiwani Distt. as at present; and

(b) the time by which the payment of compensation referred to above to the land owners is likely to be made?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(सरदार तारा सिंह):

(क) जिला भिवानी में नहरों, डिस्ट्रीब्यूटरी, माईनर तथा सब माईनर के लिए जो भूमि अधिग्रहण की गई है, उसका कुल मुआवजा रूपये 47.80 लाख अदा किया जाना है।

(ख): भू-स्वामियों को भूमि का मुआवजा वर्ष 1981-82 में अदा किये जाने की संभावना है।

श्री सुरेंद्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, 10 महीने पहले इसी सदन में चीफ मिनिस्टर साहब ने यह आ वासन दिया था कि जल्दी से जल्दी सारा मुआवजा किसानों को दे दिया जाएगा। उसके बाद पिछले सै। न में भी इसी बात को दोहराया गया था और आज मिनिस्टर साहब ने इस के लिये एक साल कह दिया है। मैं आपके जरिये सरकार से यह जानना चाहता हूं कि मुआवजा देने की बात को कब तक एक्सपीडाइट कर दिया जाएगा जबकि जमीन आलरेडी एक्वायर की जा चुकी है। उसका मुआवजा 47.80 लाख रूपये के करीब बनता है। क्या सरकार दो तीन महीनों में मुआवजे की राशि दे देने की कोशिश करेगी?

मुख्य मंत्री(चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, पिदले सै। न में माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया था और हमने कहा था कि हम छः महीने के अंदर किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा दे देंगे। नहरें बनाने का कायदा यह होता है कि पहले मुआवजा दिया जाए, फिर नहरें बनायीं जायें। जब इनके पिता जी मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने जमीन एक्वायर कर ली और पैसे पहले

नहीं दिये। मैं इस बात को बुरा नहीं मानता कि उन्होंने गलत काम किया हो क्योंकि नहरें बनानी ज्यादा जरूरी थी लेकिन आज की सरकार ने.....(गोर)

आवाजें: स्पीकर साहब, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के पिता जी तो यहां पा है नहीं (गोर)

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, इस वक्त मुख्य मंत्री महोदय बोल रहे हैं, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा।

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, माननीय सदस्य के पिता जी का नाम यहां पर लिया जा रहा है। क्या वे इस हाउस में हैं? यह उनके ऊपर रिफ्लेक्शन है। (गोर)

आवाजें: यह चौधरी बंसी लाल जी के ऊपर रिफ्लेक्शन है। (गोर)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, ये जरा सुनने की कोशिश करें तो मैं इनको बताऊं। अध्यक्ष महोदय, हमने फरवरी के महीने में 70 हजार रुपये का मुआवजा दिया है और सित्तंबर के बाद अप्रैल में 14 लाख 70 हजार रुपये की राशि किसानों को और दे देंगे। मैं यहां हाउस में विदास दिलाता हूँ कि 1980-81 में हम यह काम ज्यादा से ज्यादा काम करने की पूरी कोशिश करेंगे।

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने आनरेबल मैम्बर श्री सुरेंद्र सिंह जी के पूरक प्र न के उत्तर में यह बताया कि उनके बुजुर्ग पिता चौधरी बंसी लाल जी ने जमीन पहले एक्वायर कर ली थी और मुआवजा दिया ही नहीं था। मैं आपके द्वारा चीफ मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहूंगा कि उनके पिता जी ने तो गलती की है जैसे कि वे फरमा रहे थे लेकिन आपने क्या किया? (गोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, मैं गलती नहीं कहता। जनहित में उन्हें नहरें जल्दी बनानी पड़ी। (गोर)

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, सब से पहले तो मेरी अर्ज यह है कि जैसे मुख्य मंत्री महोदय ने फरमाया कि पहले पैसा देना चाहिये था फिर जमीन लेनी चाहिये थी लेकिन ऐसा किया नहीं गया। मैंने तो केवल उन्हीं के भाबदों में इररैगुलेरीटीज की बात कही है। उन्होंने कहा कि फरवरी के महीने में 70 हजार रुपये की राशि किसानों को मुआवजों के रूप में दी है और अप्रैल में 14 लाख 70 हजार के करीब देने जा रहे हैं जबकि कुल मुआवजे की राशि 47.80 लाख रुपये निर्धारित की गयी है। मैं आपके द्वारा उनसे यह जानना चाहता हूँ कि उन गरीब किसानों की जमीन कब एक्वायर की गयी थी और कब से यह मामला सरकार के पास लटक रहा है?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, मैं एक बात और क्लियर कर दूँ। जिस वक्त यह जमीन एक्वायर की गयी थी, उस वक्त चौधरी बंसी लाल जी मुख्य मंत्री थे। हमने माना है कि उस वक्त नहरें जल्दी बनाने की जरूरत थी, इसलिये मुआवजा जल्दी नहीं दिया गया। फिर भी डाक्टर मंगल सैन किस प्वायंट को पुट करना चाहते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आया? (गोर) स्पीकर साहब, यह मुआवजा देने की बात 6-7 सालों से चली आ रही है।

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, हमें डेफ़ीनिडेट चाहिये कि किस डेट तक सरकार गरीब किसानों को मुआवजा दे देगी?

Mr. Speaker: I think it is very difficult to give a definite date off hand. It is a matter of record.

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, जूई कैनल, लौहारू कैनल और सिवानी कैनल जब बनी थी, यह कोई लगभग 5-7 सालों की बात है (गोर) मैं तो कहता हूँ कि यह मामला पांच सात सालों से लटक रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डाक्टर साहब भी उसके बाद करीब दो साल मिनिस्टर रहे, इन्होंने क्या किया, जो आज हमें इसके लिये कह रहे हैं। हमने तो कुछ मुआवजा दिया है और अप्रैल में 15 लाख के करीब मुआवजों की रकम किसानों को और देने की कोशिश कर रहे हैं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, इस पर काफी डिस्कशन हो चुकी है। मैं इस बारे में एक बात क्लियर करना चाहता हूँ।

जो मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि जब स्टेट में कोई डिवैल्पमेंट का कैं I प्रोग्राम चलता है तो I think is no harm in acquiring the land and paying compensation later. What the Hon. Chief Minister has stated should be clearly understood. However, a number of cases have come to my notice जहां पर कि कंपंसे I न देने में अनडयूली डिले हो रही है। जिससे किसानों को काफी हार्डि I प फेस करनी पड़ रही है। मैं गवर्नमेंट से रिक्वैस्ट करूंगा कि इस हार्डि I प को दूर करने के लिए वह जल्द से जल्द कंपंसे I न देने की कोि I I करे।

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, आपने ठीक फरमाया है। हम इस बारे में जल्दी ही कार्यवाही कर रहे हैं। हमने स्पै I ल एल0ए0ओज0 वहां लगाए हैं। असल बात यह है कि पहले जिस अधिकारी को एल0ए0ओ0 प्रो0 लगाते थे, वह अपनी ट्रांसफर करवाने की कोि I I करवाता था जिस वजह से सियासी आदमियों पर दबाव डाला जाता था। अब हमने इस पोस्ट के लिए 200 रूपये स्पै I ल पे देने का फैसला किया है ताकि इस काम पर अधिकारी लगे। सब जगहों पर हमने एल0ए0ओज0 लगा दिये हैं। आपके जिले में भी इसी तरह की कार्यवाही की गयी है। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी भी मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी अगर कोई मुआवजा दिया हो, तो वे बता दें।

श्री बीरेंद्र सिंह: स्पीकर साहब, यह रिकार्ड उनसे मुझे दिलवा दें तो मैं जवाब दे दूंगा। (गोर)

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, क्या मुख्य मंत्री महोदय यह आ वासन देंगे कि किसानों को मुआवजा दो साल के अन्दर दिया जाएगा?

Mr. Speaker: I think, it is unreasonable to spring such as sudden question on the Chief Minister. If proper notice had been given, he could have checked it up whether the compensation could be paid within two years.

तारांकित प्र न संख्या 1942

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, श्री हीरा नंद आर्य, इस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।

Digging work of Canal from Village Chandi to Khidwali

***2055. Chaudhri Hari Chand Hooda:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to start digging work of canal from village Chandi to Khidwali in District Rohtak; and

(b) if so, time by which the aforesaid work is likely to be started and completed?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (सरदार तारा सिंह):

(क) हां जी।

(ख) किसानों ने अब सरकार द्वारा स्वीकृत एलाइनमेंट में परिवर्तन की मांग की हैं। दूसरी (आल्टरनेटिव) एलाइनमेंट निरीक्षाधीन है।

चौधरी हरि चंद हुड्डा: क्या मंत्री जी बताएंगे कि उनके नाटिस में यह बात है (10.00बजे) कि चीफ इंजीनियर ने इसे खुद कैंसिल किया है और लोगों ने ऐसी मांग नहीं की थी?

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, यह बात बिल्कुल गलत है।

श्री बीरेंद्र सिंह: स्पीकर साहब, हुड्डा साहब, यह जानना चाहते हैं कि जो एलाइनमेंट चेंज करने की बात है वह लोगों की तरफ से कोई डिमांड नहीं आई थी बल्कि चीफ इंजीनियर खुद अपनी मर्जी से चेंज कर रहे हैं। क्या यह बात सही है?

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, लोगों ने मांग की है कि यह एलाइनमेंट चेंज की जाए।

चौधरी सतबीर सिंह मलिक: क्या मंत्री महोदय, बताएंगे कि पहली एलाइनमेंट में क्या खामी थी जिसकी वजह से अब चेंज करनी पड़ रही है?

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, इसमें असल बात यह है कि पहले पहले जब यह स्कीम बनी थी तो उस वक्त

बैनिफि रीज ने यह कहा था कि हम जमीन मुफ्त देंगे। उस वक्त सारा खर्चा 92,000/- रू0 बना था। बाद में लोगों ने यह कहा कि यह पैसा तथा और खर्चा लगा कर सारा खर्चा 2 लाख 92 हजार रू0 हो गया। अब तीसरी बार उन्होंने फिर कहा है कि यह एलाइनमेंट गलत है, इसको चेंज किया जाए। अब उस पर 2 लाख 92 हजार रू0 की बजाए 5 लाख 72 हजार रू0 खर्चा आ रहा है। अब कुछ रकबा भी बढ़ रहा है और कुछ एलाइनमेंट भी बढ़ रही है इसलिये यह देरी हुई।

चौधरी संत कंवर: मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह जो एलाइनमेंट चेंज की जा रही है क्या इस बारे में गांव वालों की तरफ से कोई मांग पत्र आया था? यह जो 2 लाख की बजाए 5 लाख की रकम बढ़ी है कहीं यह तो नहीं कि अफसरों ने रकम बढ़ाने के लिये ऐसा किया हो?

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, जो मैंने जवाब दिया है उसे आदमी भी समझ सकता है। आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि जब सरकार का काम दो लाख रूपये में चलता था तो सरकार को पांच लाख रूपए खर्च करने की क्या जरूरत थी।

Mr. Speaker: The question is very specific. He is asking whether a change in alignment is being done on some demand by the villagers.

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, मैंने पहले यही कहा था कि लोगों की मांग पर ही एलाइनमेंट चेंज करने से पहले उस

गांव की पंचायत की कंसल्ट किया गया है कि यह चेंज होनी चाहिए या नहीं?

सरदार तारा सिंह: स्पीकर साहब, यह कोई नया सवाल नहीं है बल्कि जो बाकी लोगों ने पूछा था वैसा ही है। हमें जो सूचना अफसरों ने लिख कर भेजी है उस पर हमें वि वास करना पड़ेगा। लोग अगर कहेंगे कि इससे हमें सुविधा नहीं है, इसे चेंज किया जाए तो सरकार को वैसा ही करना पड़ेगा।

Mr. Speaker: I would request the Government that before the change in alignment is finalised another consultation should be done by the Government with the local people to see whether they are in need of change.

सरदार तारा सिंह: बहुत अच्छा जी, कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल, श्री रण सिंह मान। वे सदन में उपस्थित नहीं है।

I take up the next question.

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, यह सवाल बहुत ही इम्पार्टेंट है इसका जवाब बिला अथोराइजे इन के भी आ जाना चाहिए। मुझे रूल 52 (3) के तहत रिक्वेस्ट करने का अधिकार है। वह आदमी जेल में है इसलिये न तो वह यहां हाउस में उपस्थित हो सकता था और न ही किसी को अथोराइज कर

सकता था। रूल 52 (3) बहुत स्पैसिफिक रूल है, इसमें लिखा है—

“.....The Speaker, at the request of any member, may direct taht the answer to it be given.”

and I am requesting you under this provision to let the Minister give the answer to this question.

Mr. Speaker: First of all, I must congratulate the hon. Member that she has studied the rule very carefully and according to rule 52 (3) I allow the question. But, at the same time, I must make a remark that the member concerned has been released and he should have been present in the House.

Creation of Sub-Tehsils, and Sub-divisions in the State

***1958. @Shri Ran Singh Mann.** Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) the total number of sub-tehsils, tehsils and sub-divisions created in the State during the years 1979-80 and 1980-81 toghetheriwth the criteria adopted for their creation; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to give the status of tehsil to the Badhra Block?

राजस्व मंत्री (चौधरी भोर सिंह):

(ए) 1979-80 तथा 1980-81 में राज्य में पंद्रह सब-तहसीलें, छः तहसीलें तथा तीन उप मण्डल बनाए गए हैं। इन इकाईयों को बनाते समय लोगों की मांग, यातायात की सुविधाएं, प्रासंगिक सुविधा तथा क्षेत्र की समीप्ता आदि को ध्यान में रखा गया।

(बी) नहीं।

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो सब-तहसील, तहसीलों और उप-मण्डलों के आंकड़ें दिये हैं क्या वे उन जगहों के नाम बताएंगे जहां-जहां ये बनाए गए हैं? दूसरा सवाल मेरा यह है कि क्या किसी अपोजी इन के मैम्बर के हल्कों में भी कोई सब-तहसील, तहसील या उप-मंडल बनाया गया है? (विधन)

चौधरी भोर सिंह: अपोजी इन के हल्कों में से एक संढ़ौरा में सब-तहसील बनाई गई है और एक कालावाली में बनाई गई है। (विधन)

श्री सुरेंद्र सिंह: मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लोहारू सब-डिवीजन को तोड़ने का क्या कारण है?

चौधरी भोर सिंह: लोगों की मांग पर लोहारू की जगह सिवानी को सब-डिवीजन बनाया गया है?

श्री भले राम: क्या मंत्री जी बताएंगे कि जो 15 सब-तहसीलें बनाई गई हैं, इनको बनाने का क्या काइटेरिया है?

चौधरी भोर सिंह: काइटेरिया तो मैंने पहले ही बता दिया है कि सब-तहसीलें, तहसीलें और सब-डिवीजन लोगों की यातायात की सुविधाएं प्रशासनिक सुविधाएं, क्षेत्र की समीप्ता और लोगों की मांग को ध्यान में रखकर बनाये गये हैं। (व्यवधान)

श्री मूल चंद जैन: स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब से पूछा गया था कि अपोजी इन मैम्बरज के हल्कों में कितनी तहसीलें, सब-तहसीलें और सब-डिवीजन खोले गये हैं। मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया है कि 15 सब तहसील, 6 तहसील और 3 सब डिवीजन खोले गये हैं जिनका टोटल 24 बनता है। इन 24 में से अपोजी इन मैम्बरज के हल्कों में केवल 2 सब-तहसीलें खोली गई हैं। क्या मुख्य मंत्री महोदय बतायेंगे कि 24 में से दो खोलना न्यायसंगत है, क्या आप इस न्याय पर गौरव करते हैं?

मुख्य मंत्री(चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, तहसील, सब-तहसील और सब-डिवीजन बनाने के लिए किसी हल्के की बात नहीं हुआ करती, इसमें यह देखा जाता है कि लोगों को कहां से सुविधाएं मिल सकती हैं। लोगों की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए हमने तहसील, सब-तहसील और सब-डिवीजन बनाये हैं। इनको बनाते समय, हमारे अपोजी इन के जो एम0एल0एज0

है, उनके हल्कों के जो देहात हैं, जिनसे ये वोटें लेकर एम0एल0एज0 बने हैं, उन्होंने यह मांग की है कि उनको हल्कों को तहसील, सब-तहसील और सब-डिवीजन में शामिल कर लिया जाए और इनकी मांग को देखते हुए ही ये बनाये गये हैं।

श्री जयनारायण वर्मा: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि यातायात की सुविधाएँ, प्रशासकीय सुविधा तथा क्षेत्र की समीप्ता ये तीन किस्म के आधार लेकर तहसील, सब-तहसील और सब-डिवीजन बनाये गये हैं। क्या इस क्राइटेरिया के मुताबिक बरवाला को जो 50 साल पहले तहसील हुआ करती थी, तहसील नहीं बनाया जा सकता था? इसी प्रकार क्या उकलाना को तहसील नहीं बनाया जा सकता था? क्या ये दोनों जगहें इस क्राइटेरिये को पूरा नहीं करती थीं?

चौधरी भोर सिंह: अपोजि उन के जो भाई यह महसूस करते हैं कि उनके हल्कों में नहीं बनाये गये हैं, उन्होंने कभी अपने हल्के का जिक्र नहीं किया कि वहाँ तहसील, सब-तहसील और सब-डिवीजन बनाये जाए। बाबू मूल चंद जैन ने चिट्ठी लिख कर कहा था कि सम्भालखा में तहसील बनाई जाए और हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं। वर्मा साहब ने अपने हल्कों के बारे में कभी कोई जिक्र नहीं किया।

चौधरी बीरेंद्र सिंह: स्पीकर साहब, जो भी सब-तहसीलें, तहसीलें और सब-डिवीजन्ज प्रशासनिक सुविधाओं

को मद्देनजर रखते हुए बनाये गये है, इनमें सब-ट्रेजरीज नहीं है। सब-ट्रेजरीज न होने की वजह से रैवेन्यू स्टैम्प पे पर वगैरह लेने में असुविधा होती है। क्या सरकार इन जगहों पर सब-ट्रेजरीज खोलेगी?

चौधरी भोर सिंह: इन जगहों पर सब-ट्रेजरीज खोल देंगे।

Arrears of Sales Tax

***1972. Chaudhri Ude Singh Dalal:** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state-

(a) the total amount likely to be recovered up to 31-3-1980 as arrears of Sales Tax; and

(b) the names and address of the parties who owe to the Government over rupees one lac as arrears of Sales Tax?

Excise and Taxation Minister (Chaudhri Mehar Singh Rathee):

(a) Since the period for recovery of sales tax has not been indicated, it is not possible to give the amount recovered up to 31-3-1980. However, the total arrears of sales tax as on 31-3-1980 is Rs. 11,13,75,928.

(b) A statement showing the names and addresses of the parties who owe to the Government over one lac as arrears of sales tax on 31-1-1981 is placed on the Table of the House.

STATEMENT

**Showing the names & addresses of the dealers
who owe to the Government over rupees one lac as arrears
of Sales Tax as on 31-1-1981**

Sr. No.	Name and address of the firm	Haryana General Sales Tax Act, 1973	Central Sales Tax Act, 1956.
District Ambala			
1	M/s Haryana Roadways, Ambala	2,40,548	-
District Bhiwani			
1	M/s Anti Ram Nand Kishor, Bhiwani.	2,70,036	20,093
2	M/s Dalmia Dadri Cement Factory, Dadri.	41,35,636	19,55,337
3	M/s Kiran Vegetable Products, Bhiwani	9,24,412	-
4	M/s Haryana Dairy Development Corporation, Bhiwani	-	2,33,638
District Faridabad			
1	M/s Eastern Electronics, Faridabad.	-	1,96,966

2	M/s D.G.L. Ltd. Faridabad.	11,115	1,38,747
3	M/s Rackmen Costkin, Faridabad.	1,06,403	2,086
4	M/s J.N. Sharma and Sons, Faridabad.	1,86,870	2,90,383
5	M/s Rama Trader Co., Faridabad.	1,15,709	-
6	M/s Laxmi Trading Co., Fardiabad.	5,58,810	-
7	M/s Ganesh Packing Company, Faridabad.	92,917	1,52,042
8	M/s Associated Inds., Faridabad.	11,06,000	-
9	M/s Napco Bovel Gears Pvt. Ltd., Faridabad	13,774	1,38,896
10	M/s Gansha Pipe Industries, Faridabad.	49,744	1,10,602
11	M/s Liquor Traders Private Limited, Faridabad	1,15,127	2,782
12	M/s Haryana Footwear Corporation, Faridabad.	1,31,429	2,15,494

13	M/s Rackmen Auto Private Limited, Faridabad	5,44,265	5,50,131
14	M/s Prestolight of India Ltd., Faridabad	2,89,803	44,29,700
15	M/s Laxmi Rattan Engineering Works Limited, Faridabad	5,62,589	8,69,632
16	M/s Associated Steel Industries, Faridabad.	1,91,865	36,318
17	M/s Emerson Paul Plastic, Faridabad	3,470	5,61,913
18	M/s Sehgal Puri Pvt. Limited, Faridabad	-	1,61,667
19	M/s Brake Lineing Limited, Faridabad.	-	6,36,136
20	M/s Globe Motors Works, Faridabad.	3,53,171	1,06,486
21	M/s Auto Steel Industries Limited, Faridabad.	86,957	6,03,208
22	M/s New India Motor, Faridabad.	15,88,378	1,47,265
23	M/s Pearl Cycle	1,39,341	13,38,104

	Industries, Faridabad.		
24	M/s Top Style Apparel Private Limited, Faridabad	-	3,4,587
25	M/s Globe Steel, Faridabad.	10,13,502	9,38,282
26	M/s Excelsion Plant, Faridabad.	15,293	4,27,586
27	M/s Wearwell Cycle Company, Faridabad	5,41,262	15,56,052
28	M/s Usha Forgings and Stamping Private Limited, Faridabad.	1,06,63	1,08,780
29	M/s Bertan Scot Industries, Faridabad	26,763	1,17,842
30	M/s Hada Steel Products, Faridabad.	-	3,85,022
31	M/s Associated Steel India, Faridabad.	1,97,643	11,164
32	M/s Hindustan Milk Food Manufacturing, Faridabad.	-	1,91,551
33	M/s Partap Steel Industries, Faridabad.	-	3,38,396

34	M/s Hindustan Brown Boveri, Faridabad.	-	18,00,096
35	M/s Northern India and Steel Company, Faridabad	12,080	5,36,884
36	M/s Prestolite of India, Faridabad.	16,371	11,56,242
37	M/s Crown Caps India Pvt. Ltd., Faridabad	11,162	5,16,725
38	M/s Suraj Lamps Industries, Faridabad.	29,933	6,46,341
39	M/s Associated Steel Limited, Faridabad.	6,73,760	1,73,812
40	M/s Appliances Mfg. Co., Faridabad	1,68,369	27,365
41	M/s Luxmi Rattan Engg. Works, Faridabad	73,552	2,22,801
42	M/s India Jute Supply Company, Faridabad.	-	1,45,000
43	M/s Auto Pins India (Regd.), Faridabad.	-	29,17,348
44	M/s Hindustan Brown Boveri, Faridabad.	2,41,350	66,64,401

45	M/s Hindustan Milk food Mfg. Co., Faridabad.	85,093	2,01,550
46	Fritz and Singh, Faridabad.	-	1,37,629
47	M/s Bengal National Textile, Faridabad	38,086	30,73,079
48	M/s Reneo Vickers, Faridabad.	12,428	1,17,392
49	M/s Emulsion Products, Faridabad.	39,844	1,44,798
50	M/s Haryana Sales Corporation, Faridabad.	1,35,306	-
51	M/s Bharat Carpets Limited, Faridabad.	10,71,000	15,00,000
52	M/s Telesound India, FARIDABAD.	31,426	2,41,153
53	M/s U.K. Builders Pvt. Ltd. Faridabad	7,931	4,25,861
District Gurgaon			
1	M/s Eggo Metal Works, Gurgaon.	26,648	1,51,331
2	M/s Bags and Cartons,	-	4,71,594

	Gurgaons.		
3	M/s Maruti Limited., Gurgaon	11,75,591	33,49,675
4	M/s Manohar Lal Hira Lal, Tauru.	1,11,257	11,120
5	M/s Haryana Roadways, gurgaon.	1,44,142	-
6	M/s Director General Supplies and Disposals, Delhi, Gurgaon.	2,55,000	-
District Hissar			
1	M/s Birla Cotton and Ginning and Pressing Mills, Fatehabad, Hissar.	3,88,339	-
2	M/s J.C. Mills Factory, Fatehabad, Hissar	2,84,971	-
3	M/s Shiv Dutt Rai, Fateh Chand, Hissar	1,40,000	-
4	M/s Mangat Rai Ram Avtar, Hissar.	1,10,576	-
5	M/s Mittal Pipe Factory, Hissar.	1,26,700	-

6	M/s Haryana Roadways, Hissar	1,23,560	-
7	M/s Plant Protection Inspector, Hissar	1,49,729	-
District Jagadhri			
1	M/s United Timber Works, Yamunanagar.	1,27,813	-
2	M/s Assistant Controller of Stores, Jagadhari	4,33,349	-
3	M/s Lachmi Singh Sohan Singh, Yamuna Nagar	1,14,155	-
District Karnal			
1	M/s Government Medical Store, Depot, Karnal	41,95,148	1,86,77,898
2	M/s Khosla Sales Corporation, Karnal	1,48,732	-
3	M/s Haryana Tourism, Karnal.	3,61,623	-
4	M/s Haryana Roadways, Karnal	2,34,941	-

5	M/s Jain Traders, Panipat	1,10,408	-
District Kurukshetra			
1	M/s Sant Lal Tek Chand, Kaithal.	1,31,455	-
2	M/s D.F.S.C., Kurukshetra.	4,59,243	-
3	M/s Haryana Roadwyas, Kaithal	1,13,899	-
District Narnaul			
1	M/s Chhote Lal Chiranji Lal, Narnaul	1,97,622	-
2	M/s Ram Kishan Sheo Chand Rai, Narnaul	3,95,245	-
3	M/s Sarabhi Machinery Bombay, Narnaul	14,31,850	-
District Rohtak			
1	M/s Pahwa Bottle Supply, Co., Rohtak	-	1,46,377
2	M/s Royal Body Builders, Rohtak	3,05,278	1,60,649
3	M/s Finochem Laboratories,	-	1,40,000

	Bahadurgarh		
4	M/s Suresh Oil & Cotton Mills, Meham	1,60,000	-
5	M/s Haryana Roadways, Rohtak	1,05,825	-
6	M/s Suresh Oil & Cotton Mill, Meham	1,03,769	-
District Sonapat			
1	M/s Haryana Rice & General Mills, Gohana	1,04,280	-
2	M/s Haryana Conductors Pvt. Ltd. Kundli	-	2,86,690
3	M/s Ashoka Motor Stores, Sonapat	4,83,550	-
4	M/s Depro Food, Rai, Sonapat	-	3,12,406
5	M/s E.CE. Sonapat	-	3,80,710
District Sirsa			
1	M/s Bhakra Cotton & General Mills, Sirsa	1,55,460	-
2	M/s Beni gopal mahabir	1,28,755	-

	Parshad, Sirsa		
3	M/s Sirsa Industries, Sirsa	2,97,768	-
4	M/s Padmawati Raje Cotton ginning Factory, Sirsa	1,35,044	-
5	M/s Gupta Cotton & General Mill, Sirsa	3,28,283	-
6	M/s Harji Ram Balwant Singh, Sirsa.	1,64,586	-
7	M/s Bharat Cotton Factroy, Sirsa	1,62,138	1,17,498
8	M/s Surja Ram Cotton Factory, Kalanwali	1,57,731	-
9	M/s Chaudhry Cotton Ginning and Pressing Factory, Sirsa.	1,70,878	-
10	M/s Gopi Chand Textile Mills, Sirsa	3,22,066	4,38,642

चौधरी उदय सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने एरियर्ज आफ सेल्ज टैक्स की टोटल रकम 11,13,75,928 रूपये बताई है लेकिन बहुत सी ऐसी फर्म्ज भी है जिनके नाम पर काफी रकम बकाया है और उनके नाम इस स्टेटमेंट में भामिल नहीं है। दूसरी ओर अगर किसी जमींदार की तरफ पांच रूपये भी बकाया

है तो उनको तहसीलदार या एस0डी0ओ0 की मारफत बुलवाकर थाने में बंद कर दिया जाता है। हांसी में पांच सौ रूपयें की वसूली करने के लिए जमींदार को जाने से मार दिया गया। आप देखें मिनिस्टर साहब के जवाब के मुताबिक 11,13,75,928 रूपया से सेल्ज टैक्स का वसूली के लिये बकाया पड़ा हुआ है जिसकी वजह से सारी स्टेट की तरक्की रूकी हुई हैं। क्या मंत्री महोदय हाउस को वि वास दिलायेंगे कि यह रूपया कब तक वसूल हो सकेगा?

चौधरी मेहर सिंह राठी: ये 1980 की फिगर्ज है। इसमें से बहंत सी रकम वसूल हो चुकी है और 4,54,40,470 रूपये की वसूली कोर्ट द्वारा स्टे हो चुकी है। इस में कुद रकम ऐसी है जो वसूल ही नहीं हो सकती क्योंकि कुछ फर्मों ने अपना दिवालिया दिखा दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप पहले मिनिस्टर साहब का जवाब सुन लीजिए। (व्यवधान)

चौधरी मेहर सिंह राठी: कुछ फर्मों के केसिज लिक्विडे तन के लिये गये हुए है और 2,22,51,761 रूपये हम वसूल कर पायें है। (व्यवधान)

डा0 मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, आबकारी तथा कराधान मंत्री ने अभी बताया कि 11,13,75,928 रूपया सेल्ज टैक्स के रूप में बकाया है। जवाब के (ख) भाग में कहा है कि जानकारी सदन

के पटल पर रखी जाती है। जानकारी तो इन्होंने दे दी लेकिन स्टेटमेंट के पृष्ठ 3 पर मारुति लिमिटेड गुड़गांव के अगेंस्ट हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स का 11,75,591 रूपया और सेंद्रल सेल्ज टैक्स का 33,49,675 रूपया बकाया है। स्पीकर साहब, पिछले दिनों वित्त मंत्री श्री तायल और चौधरी भजन लाल जी का एक फ़ैक्ट्री के बारे में विवाद चला था और वह है मैसर्ज आटों पिंज इंडिया लिमिटेड, जिसके मालिक सरदार अवतार सिंह जी है। इनकी तरफ करोड़ों रूपया बकाया है लेकिन इस स्टेटमेंट में इस फ़ैक्ट्री के बारे में जिक्र नहीं है। दूसरी ओर अगर किसी गरीब आदमी की तरफ थोड़ा सा रूपया भी बकाया हो तो उसको तहसील में बंद कर दिया जाता है और उनकी मौतें हो रही है। स्पीकर साहब, लैंड रैवेन्यू कलैक्ट करने के लिये हमने एक्ट पास किया हुआ है। इस एक्ट के तहत मारुति लिमिटेड से रिकवरी क्यों नहीं करते? (व्यवधान) स्पीकर साहब, 1976 में बेचारे हरिजनों को पकड़-पकड़ कर उनकी नसबंदी की थी और उनकी सेहत बनाने के लिये पांच पांच सौ रूपया दिया था, आज थोड़ी सी रिकवरी के लिये उनको तहसील में क्यों बंद किया जा रहा है। मैं मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस रूपये को एज लैंड रैवेन्यू रिकवर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये है?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, डा० मंगल सैन ने बड़ी लम्बी चौड़ी स्पीच में सवाल किया है। ये जो सवाल पूछना चाहते थे वह तो भूल गये, स्पीच देने लग पड़े। मैं

आनरेबल मैम्बर्ज को, खास तौर पर डा0 मंगल सैन जी को बताना चाहता हूँ कि 11,13,75,928 रूपये की जो राशि बकाया है, इसको वसूल करने के लिए इस सदन में हमने कानून पास किया था ये उसमें शामिल नहीं थे। (व्यवधान)

डा0 मंगल सैन: हम शामिल थे, आप रिकार्ड देखकर बताया करें स्पीकर साहब, इनको हाउस को मिसलीड करने की आदत है। (व्यवधान)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, रिकार्ड की बात है, उस समय मुख्य मंत्री मैं ही था। (व्यवधान)

डा0 मंगल सैन: आप भी थे, हम भी यहीं पर थे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बीच में इंटरफीयरेंस न करें। (व्यवधान)

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, उस वक्त कानून पास किया था कि जिस तरह किसान से बकाया राशि एज एरियर्ज आफ लैंड रैवेन्यू वसूल करते हैं, उसी तरह इंडस्ट्रियलिस्ट्स की तरफ जो बकाया राशि है वह भी एज एरियर्ज आफ लैंड रैवेन्यू ट्रीट की जाए और किसानों की तरह वसूल की जाए। इस कानून के तहत हम कार्यवाही कर रहे हैं लेकिन कुछ फर्मों ने अदालत से स्टे ले लिया है। आप जानते हैं

कि कोर्ट से स्टे लेने के बाद हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते, सरकार मजबूर है।

एक सदस्य: मारुति लिमिटेड से वसूली करने के बारे में क्या किया? (व्यवधान)

चौधरी भजन लाल: मारुति लिमिटेड की तो थोड़ी सी रकम है। (व्यवधान)

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, पांच सौ रूपया अगर किसी हरिजन से लेना हो तो उसको जेल में बंद कर दिया जाता है और मारुति के बारे में कह रहे हैं कि थोड़ी रकम है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सवाल का जवाब सुनें। मारुति से ज्यादा बड़ी बड़ी रकमें कई दूसरी फर्म की हैं। (गोर)

डा० मंगल सैन: 33 लाख रूपया हैं यह कोई छोटी रकम नहीं है। (गोर) I have gone through each and every item. (Interruptions).

श्री अध्यक्ष: यह सैंट्रल सेल्ज टैक्स है। इसे सैंटर ने लेना होता है। (गोर)

चौधरी गंगा राम: अध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख की बात है कि 33 लाख रूपये को तो ये छोटी सी रकम बताते हैं लेकिन

किसान से दो सौ रूपया लेने के लिए उसे गोली से मार रहे है ।
(गोर)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, यह केस कोर्ट में था और उसने सारी प्रोसिडिंग्स स्टे की हुई थी। उसके बाद भारत सरकार ने इसे टेक ओवर कर लिया। हम सेंटर से बातचीत कर रहे है कि हमारा जो पैसा बकाया है उसे दिया जाए और हमें पूरा भरोसा हे कि वह हमें मिलेगा। कितने ही बड़े आदमी का या कितनी ही बड़ी फ़ैक्ट्री का केस क्यों न हो किसी को माफ़ करने का सवाल नहीं है। जिस तरह की सख्ती किसान के साथ की जाती है उससे ज्यादा सख्ती हम इन लोगों के साथ करते है। (गोर)

चौधरी उदय सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्य मंत्री जी यह बताएंगे कि कानून बनने के बाद आज तक कितने फ़ैक्टरी वाले इन्होंने जेल में बंद करवाए है? (गोर)

(इस प्र न का उत्तर नहीं दिया गया)

चौधरी हुक्म सिंह: क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि इतनी भारी रकम वसूल करने में क्या अड़चन है और आज तक कौन कौन सी फ़र्ज के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई है?

श्री अध्यक्ष: यह तो पहले ही बता दिया गया है।

चौधरी राम लाल वधवा: अध्यक्ष महोदय, इस पर हाफ एन आवर डिस्कशन होनी चाहिए। (गोर)

श्री अध्यक्ष: बाबू मूल चंद जैन। (गोर एवं विघ्न) आप लोग बैठिए। मैं लीडर आफ दि अपोजीशन को सप्लीमेंटरी पूछने का मौका दे रहा हूँ लेकिन आप उनको बोलने हीं नहीं दे रहे हैं।

श्री मूल चंद जैन: स्पीकर साहब, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने हाउस को बड़ी गलत इंफर्मेशन दी है। इन्होंने कहा कि इनकी सरकार ने इंडस्ट्रियलिस्ट्स से बिक्री टैक्स मालगुजारी के रूप में वसूल करने के लिए कोई कानून बनाया है लेकिन यह गलत बात है। इस तरह का कानून तो सन् 1948 से जारी है।

चौधरी भजन लाल: इस कानून में कुछ कमी थी जिसको अमेंडमेंट करके हमने पूरा किया है।

श्री मूल चंद जैन: स्पीकर साहब, सवाल मेरा यह है कि क्या चीफ मिनिस्टर साहब या इनके मंत्री राठी साहब यह बताएंगे कि बिक्री कर की बकाया राशि को मालगुजारी के रूप में वसूल करने के लिए इन्होंने कोई एक भी वारंट जारी किया है?

श्री अध्यक्ष: ये तो कहते हैं कि फर्ज ने स्टे ले लिया है। स्टे मिलने के बाद ये कैसे ऐक्टिवेशन ले सकते थे?

श्री मूल चंद जैन: 11 करोड़ में से साढ़े चार करोड़ की स्टे आई है। साढ़े छः करोड़ रुपये की रकम तो अब भी बाकी है। उसके ऊपर कोई स्टे नहीं है?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हमने कुछ लोगों के खिलाफ कार्यवाही की है लेकिन उसकी इंफर्मे न लेने के लिये माननीय सदस्य हमें नोटिस दें। इनको बकायदा नाम बता दिए जाएंगे कि किस-किस के खिलाफ क्या क्या कार्यवाही की गई है। जबानी यह बात बताना मुश्किल है। (गोर)

श्री देवी दास: अध्यक्ष महोदय, सोनीपत में एक ई0सी0ई0 फैक्टरी है। इसके खिलाफ 3,80,710 रुपये बकाया है। यह बिरला की फैक्टरी है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि इससे वसूली न होने के कारण है?

चौधरी मेहर सिंह राठी: स्पीकर साहब, वसूली करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इनसे वसूली हो भी जाएगी क्योंकि यह बड़ी अच्छी कम्पनी है। (विघ्न)

श्री देवी दास: यह फर्म तो दिवालिया नहीं है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि लगभग चार लाख रुपया इससे क्यों वसूल नहीं किया गया?

चौधरी मेहर सिंह राठी: स्पीकर साहब, यह तो एक साल पहले का बकाया था। उसके बाद कितनी वसूली हो गई है

यह देखने की बात है। इन्होंने चूंकि एक साल पहले की इंफर्मे अन मांगी थी इसलिये यह सूचना दी गई।

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, यह जो सूची मंत्री महोदय ने सदन के पटल पर रखी है इसमें प्राइवेट फर्म्ज के अलावा कुछ पब्लिक अंडरटेकिंगज भी है जैसे हरियाणा रोड़वेज अम्बाला, कैथल, हिसार, रोहतक, गुड़गांव ओर हरियाणा डेरी डिवैल्पमेंट कार्पोरे अन भिवानी आदि। प्राइवेट फर्म्ज से बकाया राशि वसूल करने में तो इनकी दिक्कत हो सकती है लेकिन क्या मंत्री जी बताएंगे कि पब्लिक अंडरटेकिंगज से ये पैसा क्यों वसूल नहीं कर पाते?

चौधरी मेहर सिंह राठी: ये सरकारी फर्म्ज है। इनसे तो बुक ऐडजस्टमेंट होनी है। हो सकता है कि इस पैसे को राईट आफ भी करना पड़े। (गोर)

Shrimati Sushma Swaraj: This is no reply. Speaker, Sir, are you satisfied with the reply given by the Minister to my supplementary?

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। बात तो यह है कि न तो आप सवाल सुनने देते है और और न सवाल का जवाब सुनने देते हैं। इन हालात में यह कहना मेरे लिए मुश्किल है कि प्रौपर जवाब नहीं आया because there were so much side-talks.

श्री बलदेव तायल: स्पीकर साहब, सूची में लिचाा है कि डालमिया दादरी सीमेंट फ़ैक्टरी से.....
(गोर)

Mr. Speaker: Kindly listen to the questions and the replies calmly and there should be no interruptions.

श्री बलदेव तायल: स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि डिस्ट्रिक्ट भिवानी में डालमिया दादरी सीमेंट फ़ैक्टरी हैं। इसकी तरफ 41,35,636 रूपये हरियाणा सेल्ज टैक्स के और 19,55,337 रूपये सेंट्रल सेल्ज टैक्स के बकाया है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि यह एरियर कब से से पैडिंग है और कब तक रिकवर हो जाएगा?

चौधरी मेहर सिंह राठी: स्पीकर साहब, यह फ़ैक्टरी तो बंद हो गई है और लिक्वीडे ान में चली गई है। (विधन एवं भाोर)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, राठी साहब ने ठीक बताया, उन्होंने सुना नहीं। मैं दोबारा जवाब दे देता हूं। अध्यक्ष महोदय, डालमिया दादरी सीमेंट फ़ैक्टरी दादरी एक साल से बंद पड़ी है। यह प्राइवेट फ़ैक्टरी थी और दिवालिया निकाल कर मालिक चले गए और फ़ैक्टरी बंद पड़ी है। भारत सरकार इसे टेक ओवर करने की बात सोच रही है। हमने भारत सरकार से इस संबंध में बात की है। दो हजार लेबर इसके बंद होने से बेकार बैठी है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा अर्ज यह है कि इस फर्म के खिलाफ केवल यही पैसा बकाया नहीं है बल्कि 70-80

हजार रूपया बिजली बोर्ड का भी बाकी है। वह भी इससे वसूल करना है। बैंकों से भी इसने बहुत सा कर्जा ले रखा है। वह पैसा भी इसने देना है।

श्री मूल चंद जैन: मालगुजारी के रूप में क्यों नहीं वसूल करते?

चौधरी भजन लाल: किससे वसूल करें? फर्म तो दिवालियां निकाल कर चली गई है। इसके अलावा स्पीकर साहब, बाबू मूल चंद जैन जी को भाायद ध्यान नहीं कि यह पैसा जब ये फाईनैस मिनिस्टर थे उस वक्त से बाकी चला आ रहा है। (गोर)

श्री मूल चंद जैन: स्पीकर साहब, मैं इनकी इस बात पर जोरदार प्रोटैस्ट करता हूं। किसी भी जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर को इस तरह की बात कहना भाोभा नहीं देता कि आपके जमाने से यह पैसा बकाया चला आ रहा है। (गोर) यह निहायत गैरजिम्मेदारी की बात है। (गोर)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, क्या ये जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं? (गोर)

Mr. Speaker: Question is Hour is over.

तारांकित प्र न संख्या 1972 पर आधे घंटे की चर्चा की मांग

डा० मंगल सैन: स्पीकर साहब, हइम इस आनसर से सैटिसफाइड नहीं है, इस सवाल पर हाफ एन आवर डिस्कान होनी चाहिए। (गोर)

Mr. Speaker: We have already spent 15 minutes on this question.

विरोधी पक्ष की ओर से आवाजें: इस पर हाफ एन आवर डिस्कान होनी चाहिए (गोर)

श्री मूल चंद जैन: स्पीकर साहब, यह मामला सिर्फ सवाल का नहीं है। यह मामला गवर्नमेंट की नीति का है। किस तरीके से दो दो हजार रूपया कर्जा वसूल करने के लिये लोगों को परेशान किया जाता है। वह तो मैं गवर्नर ऐड्रेस पर जब बोलूंगा उस समय तफसील में बताऊंगा लेकिन इस सवाल पर आधे घंटे की डिस्कान जरूर होनी चाहिए। बिक्री कर के लिये आप एक आदमी के खिलाफ भी कार्यवाही नहीं करते। उनकी तरफ सरकार का लाखों रूपया बकाया पड़ा है।

स्वामी अग्निवे 1: स्पीकर साहब, यह बहुत गम्भीर मामला है। हमारे विपक्ष के नेता ने कहा है कि बड़ी अजीबों-गरीब हालत है कि गरीब किसानों को सख्त कानून के तहत जेलों में डाला गया है लेकिन दूसरी तरफ पूंजीपति और सरमायेदार लोग दिन-दहाड़े टैक्स की चोरी कर रहे हैं, बिजली की चोरी कर रहे हैं। लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। मुख्य मंत्री जी के पास एक भी उदाहरण नहीं है कि किसी भी

पूँजीपति को जेल में डाला हो। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस पर आधा घंटे की डिस्कान आप स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष: इस सवाल के बारे में मेरा अपना विचार यह है कि काफी से ज्यादा डिस्कान हो चुकी है। 15 मिनट से ज्यादा टाइम लग चुका है और जो जवाब आये है उनसे एटलीस्ट में तो सैटिसफाइड हूँ। अगर कोई कोर्ट की तरफ से स्टे है, उस पर उचित कार्यवाही हो रही है। मेरे सोचने के तरीके से तो उचित कार्यवाही हो रही है। (गोर) Further during the discussion on the Governor's Address and on the Budget, the hon. Members will get sufficient time to highlight any such points. Therefore, I do not see any necessity for half-an-hour discussion on this question. However, if the hon. Members feel agitated, they can give me a notice for half-an-hour discussion and I will consider that on merits. That is all I can promise that I will consider the notice on merits.

श्री सुरेंद्र सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, यह क्लियर नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर साहब ने यह कह दिया कि कानून ऐसा है लेकिन लीडर आफ दि अपोजिशन ने कहा कि ऐसा कानून बना नहीं है। क्या इस किस्म का कोई कानून है या बजट से गान में आ रहा है या पीछे इस कानून के तहत कोई कार्यवाही हुई है? यह बात क्लियर की जाये।

Mr. Speaker: This is no point of order.

श्री मूल चंद जैन: मैंने कहा था कि कानून बना हुआ है।

Mr. Speaker: What I understood from that was कि पुराना कोई कानून बना हुआ था जो इफैक्टिव नहीं था। उसको कारगर बनाने के लिये भायद कोई अमेंडमेंट आयी हो।

श्री बलदेव तायल: स्पीकर साहब, इस पर आपने अपनी रूलिंग दे दी लेकिन हमारी प्रार्थना है कि दौबारा री-कंसिडर करके हाफ एन आवर डिस्कान अलाउ कर दें तो बड़ी अच्छी बात होगी।

Mr. Speaker: I have already said that in my opinion it is not necessary. However, hon. Members can give a notice and I will consider it on merits.

Question Hour is already over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर।

Amount given to Industries by the Haryana Khadi and Village Industries Board

***2046. Shri Bhale Ram:** Will the Chief Minister be pleased to state the total amount given to various industries by the Haryana Khadi and Village Industries Board during the years 1979-80 and 1980-81 separately?

मुख्य मंत्री(चौधरी भजन लाल): विवरणी परिशिष्ट
“क” पर सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

परिशिष्ट “क”

वर्ष	अनुदान (लाखों में)	ऋण (लाखों में)
1979-80	12.29 रूपये	117.95 रूपये
1980-81	10.73 रूपये	43.50 रूपये
(फरवरी 1981 तक)		

Bus Stand at Uklana Mandi

***2066. Shri Jai Narain Verma:** Will the Minister for Transport be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a bus stand at Uklana Mandi; if so, the time by which the said bus stand is likely to be constructed?

परिवहन मंत्री (श्री जगन नाथ): सरकार इस मामले का निरीक्षण कर रही है। इस बारे में अभी निर्णय लिया जाना है। अतः इतना भीघ्र यह सूचित करना कठिन है कि इस बस स्टैंड के निर्माण में कितना समय लगेगा।

Nathpa Jhakri Project

***2013. Chaudhri Ram Lal Wadhwa:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the latest position of the agreement made between Haryana and Himachal Pradesh Governments regarding the construction of Nathpa-Jhakri Project in Himachal Pradesh be laid on the Table of the House; and

(b) the date by which the construction of this project is being started and the time by which it is likely to be completed together with the amount of expenditure involved, electricity production capacity and share of Haryana State in the power, Separately?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(सरदार तारा सिंह):

(क) नाथपा झाखड़ी की ताजा स्थिति यह है कि केंद्रीय सरकार भी हरियाणा हिमाचल प्रोजेक्ट में 25 प्रति अत पूंजी लगा कर सांझीदा होगी तथा बिजली में 21 प्रति अत की हकदार होगी। हरियाणा और हिमाचल क्रम 1: 50 प्रति अत तथा 25 प्रति अत पूंजी लगायेंगे और क्रम 1: 42 प्रति अत तथा 37 प्रति अत बिजली प्राप्त करेंगे। यह त्रिपक्षीय समझौता इस सिद्धांत पर जल्दी की कार्यान्वित होगा।

(ख) इस प्रोजेक्ट का निवृत्ति कार्य हाथ में ले लिया गया है और निर्माण कार्य जैसे ही भारत सरकार से औपचारिक अनुमोदन प्राप्त होगा जिस की इसी मास में आता है, भुर्खु कर दिया जायेगा। यह प्रोजेक्ट 6 वर्ष से 8 वर्ष तक 533.3 करोड़

रूपये की लागत से जिसमें 79 करोड़ रूपये संचार-प्रणाली पर खर्च होंगे पूरा होगा। केंद्र संचार की 49 प्रतिशत लागत सहन करेगा। पूरा होने पर नाथपा झाखड़ी प्रोजेक्ट 1020 मैगावाट उत्पादन के योग्य होगा और 4000 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष पैदा करेगा। हरियाणा राज्य 428.4 मैगावाट प्राप्त करने का हकदार होगा, जिसका मतलब है कि 1680 मिलियन यूनिट प्रतिवर्ष प्राप्त करेगा।

Women died on account of bringing less dowry

***2045. Smt. Dr. Kamla Verma:** Will the Minister for Home be pleased to state-

(a) the district-wise number of women who committed or who were forced to commit suicide either for not bringing the dowry or for bringing less dowry during the period from 1966 to-date in the State; and

(b) the number of cases registered with the police against the persons involved together with the results thereof?

गृह मंत्री(श्री कन्हैया लाल पोसवाल):

(क) तथा (ख) इस प्रश्न के उत्तर को तैयार करने में जो मेहनत व समय लगेगा उसकी तुलना में इस से कोई खास लाभ होने की संभावना नहीं है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Irrigation facilities in Hassangarh Constituency

414. Chaudhri Sant Kanwar: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether there is any arrangement for the irrigation of land in the Hasangarh Constituency of Rohtak District; if so, the total acre age of land being irrigated at present; and

(b) the total acreage of cultivable land that is still Barani in the Constituency referred to in part (a)?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(सरदार तारा सिंह)

(क) हां जी, यह क्षेत्र कई चैनलों द्वारा सिंचित हो रहा है। वर्ष 1979-80 के दौरान 48812 एकड़ क्षेत्र नहरों द्वारा सिंचित किया गया था।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है।

Civil Hospital, Rohtak

415. Chaudhri Sant Kanwar: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to prevent the accumulation of water near the Civil Hospital, Rohtak during the rainy seasons; if so, the details thereof?

स्वास्थ्य तथा पर्यटन मंत्री(चौधरी गजराज बहादुर नागर):

सामान्य अस्पताल रोहतक में पानी इक्ठ्ठा होने से रोकने के लिए एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। गंदे पानी को अस्पताल के अहाते से बाहर निकाल कर नगरपालिका के वर्तमान सिवर में डालने हेतु एस्टेट सीवरेज और पानी एकत्रित करने की टंकी के निर्माण हेतु 40 हजार रुपये के अनुमान पहले ही तैयार किया जा चुके है। आसपास की सड़को से अस्पताल के क्षेत्र में पानी के बहाब को रोकने हेतु 42,000 रुपये का एक अन्य अनुमान तैयार हो रहा है। इन अनुमानों के वर्ष 1981-82 में स्वीकृत किये जाने की सम्भावना है।

Financial or other help to the industries

416. Chaudhri Sant Kanwar: Will the Chief Minister be pleased to state whether any financial or other help is being given or has so far been given by the Government to the following industries; if so, the details thereof-

- (i) Atlas Cycles, Sonapat.
- (ii) B.S.T. Gannaur, Sonapat.
- (iii) Good-year Tyres, Faridabad.
- (iv) Escort Tractors, Faridabad
- (v) Jindal Pipes, Hissar and
- (vi) E.C.E. Bahalgarh Road, Sonapat?

मुख्य मंत्री(चौधरी भजन लाल): एक विवरणी जिसमें वांछित सूचना दी गई है, सलंगन है।

विवरणी

1. एटलस साईकल्ज सोनीपत

हरियाणा वितीय निगम ने 16-7-1975 में मै0 एटलस आटो साईकल सोनीपत को 11.00 लाख रूपये की राशि स्वीकार की थी। उपरोक्त स्वीकृत ऋण में से 5.86 लाख रूपये की राशि कम्पनी को वितरण कर दी गई थी और बाकी की राशि रद्द कर दी गई। 30-9-80 को बकाया 2.70 लाख रूपये था। वह कम्पनी एटलस साईकिल लि0 के साथ मिल गई थी। उद्योग विभाग की ओर से इस कम्पनी को कोई और सुविधा/सहायता नहीं दी गई।

2. बी0 एस0 टी0 गन्नौर

भूतपूर्व पंजाब सरकार ने 1962 में स्टील ट्यूब्स प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिये 129.11 एकड़ भूमि अभिग्रहण की थी। इसी कम्पनी के लिये स्टील स्ट्रिप्स मिल प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिये मई 1969 से 63.48 एकड़ भूमि अभिग्रहण की गई थी। भूमि के मालिकों को उचित मुआवजा कम्पनी द्वारा सरकार के माध्यम से दिया जा चुका है।

एक अन्य सुविधा अर्थात् 50 प्रतिशत अनुदान फिजीबिलिटी स्टडीज/रिपोर्ट तैयार करने हेतु मै0 भारत स्टील ट्यूब्स गन्नौर को 31-3-1970 को 75,000/- रूपये दिये गये।

भूतपूर्व पंजाब सरकार ने मै0 भारत स्टील ट्यूब्स लि0 गन्नौर के भोयार कैपीटल में मार्च 1964 में 39,38,000/- रुपये के भोयरज का निम्मांकन किया था। इस कम्पनी में जो सरकार द्वारा कुल निवे 1 किया गया है वह 54,77,500/-रुपये है।

3. गुडईयर टायर फरीदाबाद

भूतपूर्व पंजाब सरकार ने वर्ष 1960 में गुडईयर टायर व रबड़ कम्पनी लि0 बल्लभगढ़ के लिये 78 एकड़ 3 कनाल 1 मरला भूमि अधिग्रहण की थी। कम्पनी को उन द्वारा मुआवजा भूमि मालिकों को सरकार के माध्यम से दिये जाने पर भूमि का कब्जा दे दिया गया था। इसके इलावा कम्पनी को उद्योग विभाग की ओर से कोई सुविधा/सहायता नहीं दी गई।

4. एसकोर्ट ट्रैक्टर फरीदाबाद

भूतपूर्व पंजाब सरकार द्वारा मै0 एसकोर्ट ट्रैक्टर लि0 फरीदाबाद के लिये नवम्बर, 1965 में 67 कनाल एक मरला भूमि अधिग्रहण की गई थी यह भूमि ट्रैक्टर बनाने के लिये प्लांट स्थापित करने के लिये अधिग्रहण की गई थी। भूमि मालिकों को उपयुक्त मुआवजा कम्पनी द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से दे दिया गया था। इसके अलावा कम्पनी को उद्योग विभाग की ओर से कोई सुविधा/सहायता नहीं दी गई।

5. जिन्दल पाईप्स हिसार

जिंदल पाईप्स नाम की कोई यूनिट हिसार में नहीं है। लेकिन दो औद्योगिक इकाइयों जिनका नाम क्रम 1: मै0 जिन्दल इंडस्ट्रीज लि0 तथा मै0 जिन्दल स्ट्रीपस लि0 है उनको क्रम 1: 8,10,625/- रूपये तथा 1,31,650/-रूपये की राशि भारत सरकार की ओर से प्रचलित 10 प्रति शत से 15 प्रति शत केंद्रीय अनुदान स्कीम के अन्तर्गत केंद्रीय निवेश अनुदान के रूप में दिये गये हैं।

6. ई0 सी0 ई0 बहालगढ़ रोड सोनीपत

इस इकाई को उद्योग विभाग की ओर से कोई सुविधा/सहायता नहीं दी गई है।

Deaths of patients in the Medical Collage Hospital, Rohtak.

417. Chaudhri Sant Kanwar: Will the Chief Minister be pleased to state the number of persons who died while under treatment in the Medical College Hospital, Rohtak during the years 1979&80 and 1980&81 todate, separately?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): वांछित सूचना प्रत्येक वर्ष अनुसार निम्न प्रकार है:-

वर्ष	मृत रोगियों की संख्या

1979	1735
1980	1760
1981 (28-2-81 तक)	274

Recruitment of Police Constables in the State

410. Shri Bhale Ram: Will the Home Minister be pleased to state-

(a) the district-wise number of Police Constables recruited during the month of December, 1980, in the state; and

(b) the district-wise total number of the Police Constables out of those referred to in part(a) above belonging to Scheduled Castes and Backward Classes?

Home Minister(Shri Kanahiya Lal Poswal):

(a) The district-wise number of Police Constable recruited during the month of December, 1980 is as under:-

A mbala	6
K arnal	
K urukshetra	

nd	Ji	il
issar	H	il
arnaul	N	il
hiwani	B	il
rsa	Si	il
urgaon	G	il
aridabad	F	il
onepat	S	il
ohtak	R	il

(b) The district-wise total number of Police Constables out of those referred to in part (a) above belonging to Scheduled Castes and Backward Classes is as under:-

Name of the District	Scheduled Caste	Backward Class

Ambala	-	4
Karnal	1	-
Kurukshetra	-	-
Jind	-	-
Hissar	-	-
Narnaul	-	-
Bhiwani	-	-
Sirsa	-	-
Gurgaon	-	-
Faridabad	-	-
Sonepat	-	-
Rohtak	-	-

Primary Health Centres in District Sonapat

411. Shri Bhale Ram: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the names of blocks in district Sonapat where Primary Health Centres exist; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to open Primary Health

Centres in those Blocks where the above said centres do not exist at present?

स्वास्थ्य तथा पर्यटन मंत्री(चौधरी गजराज बहादुर नागर):

(क) जिला सोनीपत के विकास खंडों जिन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, के नाम निम्न प्रकार से है:—

- 1 गोहाना
 - 2 गन्नौर
 - 3 मुडलाना
 - 4 राई
 - 5 सोनीपत
 - 6 खरखौदा
- (ख) जी हां।

House Building Grants for the Harijans in the State

412. Shri Bhale Ram: Will the Minister for Transport be pleased to state the number of Harijans families in the State to whom a grant of Rs. 2,000 was given by the Welfare Department for the construction of Houses during the year 1979-80 in the State?

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्रीमती भाकुन्तला भगवाडिया):
भाून्य

**Expenditure incurred on furnishing the residence
and office of the Chairman Haryana Khadi and Village
Industries Board**

420. Shri Bhale Ram: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the expenditure incurred on furnishing the residence and office of the Chairman, Haryana Khadi and Village Industries Board from the date the present Chairman took over to 31-12-1980, separately; and

(b) whether it is a fact that the use of Khadi for the purpose referred to above is compulsory under the rules of the Khadi Board; if so, whether the cloth purchased for furnishing the office and residence of the Chairman of the Board is khadi or other cloth?

मुख्य मंत्री(चौधरी भजन लाल):

(क) निवास स्थान पर कोई खर्च नहीं किया गया। तथापि अध्यक्ष खादी तथा ग्रमोदयोग बोर्ड के कार्यालय की सजावट पर 31-12-1980 तक रूपये 4310-45 की राशि खर्च की गई है।

(ख) ऐसा कोई नियम नहीं है। तथापि अध्यक्ष खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्यालय की सजावट के लिये हैंडलूम का कपड़ा खरीदा गया था।

Justice Dulat Commission Report

422. Chaudhri Ude Singh Dalal, Shri Hira Nand Arya: Will the Chief Minister be pleased to state the action taken by the Government on the report of Justice Dulat Commission in connection with the M.D. University?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): आयोग की रिपोर्ट तथा उस पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ज्ञापन, हरियाणा विधान सभा के सम्मुख इसके पिछले सत्र में रख दिए गए थे।

T.A. drawn by officers in the Social Welfare Department

423. Shri Mool Chand Jain: Will the Minister of State for Social Welfare be pleased to state the total amount of travelling allowance (T.A.) drawn by the various officers in the Social Welfare Department on account of official tours during the years 1979-80 and 1980-81 to-date?

लोक निर्माण राज्य मंत्री(श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया): सूचना विधान सभा के पटल पर रखी जाती है।

समाज कल्याण विभाग के मुख्यालय पर कार्य कर रहे राजपत्रित एव अराजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपने सरकारी दौरे के

दौरान वर्ष 1979-80 एवं 1980-81 में ड्रा किए गए यात्रा भत्ते के आंकड़ों का वर्णन इस प्रकार है:-

	1979-80	1980-81
राजपत्रित अधिकारी (श्रेणी I एवं II)	6563.00	8802.20
अरातपत्रित अधिकारी (श्रेणी 111)	4001.45	6501.75
कुल जोड़	10564.45	15303.95

T.A. drawn by the officers in the Forest Department

424. Shri Mool Chand Jain: Will the Minister of State for Forest be pleased to state the total amount of travelling allowance drawn by the various officers in the Forest Department on account of official tours during the years 1979-80 and 1980-81 to-date?

सिंचाई तथा बिजली राज्य मंत्री(श्री देवेन्द्र भार्मा): वन विभाग के विभिन्न अधिकारियों द्वारा सरकारी दौरों के लिये प्राप्त किया गया कुल यात्रा भत्ता आपेक्षिक अवधि के लिये निम्न प्रकार है:-

(i)	1979-80	रूपये	98,274.95
-----	---------	-------	-----------

(ii)	1980-81 तक)	(अब रूपये	1,04,774.65
------	----------------	--------------	-------------

T.A. drawn by the officers in the General Administration Department

425. Shri Mool Chand Jain: Will the Chief Minister be pleased to state the total amount of travelling allowance drawn by various officers in the General Administration Department on account of official duty to various places during the years 1979-80 and 1980-81 to-date?

मुख्य मंत्री(चौधरी भजन लाल): सूचना इक्ठ्ठी करने में जो समय तथा परिश्रम लगेगा उससे कोई विशेष लाभ न होगा।

T.A. drawn by officer in the Home Department

426. Shri Mool Chand Jain: Will the Minister for Home be pleased to state the total amount of travelling allowance drawn by the various officers in the Home Department on account of official tours during the years 1979-80 and 1980-81 to-date?

गृह मंत्री(श्री कन्हैया लाल पोसवाल):

1979-80	रूपये	2078.95
1980-81	रूपये	2499.50

Members of the Haryana State Electricity Board

418. Chaudhri Jagjit Singh Pohloo: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the names of the Members of the Haryana State Electricity Board alongwith their academic qualifications together with their permanent and present residential address?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(सरदार तारा सिंह): एक सूची जिसमें हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के सदस्यों की भौक्षणिक योग्यताये, उनके स्थाई पते और वर्तमान आवासीय पते दर्ताए गए है, अनुलग्नक "ए" पर सलग्न है।

"अनुलग्नक ए"

हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के सदस्यों के नाम, योग्यताएं और स्थाई तथा वर्तमान आवासीय पते दर्ताते हुए की सूची।

क्रम संख्या	नाम तथा पद	भौक्षणिक योग्यता	स्थाई पता	वर्तमान रहने वाली जगह का पता
सर्वश्री				
	एच: सी: खन्ना, अध्यक्ष	बी: ए:(आनर्स) एम: ए: (अंग्रेजी साहित्य) और	ए-2 निजामुदीन ईस्ट (पूर्व) नई दिल्ली	म: न: 768, सैक्टर-8 हरियाणा राज्य बिजली

		फैलो कारनैल वि वविद्यालय		बोर्ड (अतिथि गृह) चंडीगढ़
	आर: के: सिंगल, सदस्य तकनीकी (परिचालन)	एफ: एस: बी: बी: एस: सी: (विद्युत एवं म िनरी) इंजीनियरिंग (बनारस)	नवल निवास, फतेहगए पूर्व जिला: बरेली (उत्तरप्रदे ा)	म: न: 61, सैक्टर-27-ए, चंडीगढ़
	के: एन: भाटिया, सदस्य तकनीकी (उत्पादन एवं प्रोजैक्ट)	एफ: एस: सी:, बी: एस: सी: (विद्युत एवं म िनरी इंजीनियरिंग, बनारस)	60 / 25 रोहतक रोड़, करौल बाग, नई दिल्ली	म: न: 437, सैक्टर 37 / ए चंडीगढ़
	जिया लाल जैन, सदस्य चारटर्ड अकाउंटैंट (वित एवं लेखा)		9 6 माडल बस्ती नई दिल्ली, 5	म: न: 1152, सैक्टर 15 बी, चंडीगढ़

	रा मजी लाल, अं ताकालिक सदस्य	उ पलब्ध नहीं है	ग ांव और डाकखाना कुरड़ी, जिला हिसार	मा फत मैसर्ज अर्जुन लाल रामजी लाल, कपड़ा विक्रेता, गांधी चौक, हिसार।
	ग नपत राय, अं ताकालिक सदस्य	बी: ए: एल: एल: बी:	२ तपूर्व विधायक काठमंडी (दादरी)	भू तपूर्व विधायक काठ मंडी (दादरी)
	रा ज कुमार, वकील, अं ताकालिक सदस्य	बी: ए: एल: एल: बी:	ब ी ए-5 प्रेम नगर एटलस रोड (सोनीपत)	ए -5 प्रेम नगर एटलस रोड (सोनीपत)

Chairman of the CONFED

419. Chaudhri Jagjit Singh Pohloo: Will the Minister for Co-operation be pleased to state the name of the Chairman of the CONFED with his academic qualification and full address?

सहकारिता तथा योजना मंत्री(ठाकुर बीर सिंह): श्री रामजी लाल पुत्र श्री सेवा राम गांव डा0 कुरड़ी, जिला हिसार। उनकी भौक्षणिक योग्यता एफ0 ए0 है और वह पिछड़ी जाति से संबंध रखता है।

अध्यक्ष द्वारा घोशणा—

श्री रण सिंह मान, एम0 एल0 ए0 की रिहाई संबंधी।

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बरज, मुझे हरियाणा विधान सभा के रूलज आफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट आफ बिजनैस के रूल 282 के तहत यह सूचित करना है कि मुझे अधीक्षक जिला जेल भिवानी से सूचना प्राप्त हुई है कि श्री रण सिंह मान एम 0 एल0 ए0 को 9 मार्च, 1981 को इस जेल (जिला जेल भिवानी) से 9-3-1981 को जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

श्री बलदेव तायल: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, कल एक बड़ी अनौमली हाए में कियेट हुई। प्रिविलेज कमेटी की हाउस में दो रिपोर्ट्स पे 1 की गई। एक कमेटी के दो एक्टिंग चेयरमैनो ने रिपोर्ट्स पे 1 की। एक रिपोर्ट स्वामी आदित्यवे 1 ने पे 1 की और दूसरी चौधरी रण सिंह ने पे 1 की। यह थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको अगर क्लियर कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी।

Mr. Speaker: I will certainly clear it. जब भुरु में प्रिविलेज कमेटी बनी तो मैंने सरदार लक्षमन सिंह को चेयरमैन

नोमीनेट किया था। मिनिस्टर बनने के बाद वे अस्तीफा दे गये। कमेटी का समय बहुत कम रह गया था और इधर से बजट सै ।न भी आ रहा था। मैंने नय चेयरमैन बनाना उचित नहीं समझा। मीटिंग में आपस में मैम्बरान ही डिसाइड करते है कि इस मीटिंग के लिए फलां एक्टिंग चेयरमैन होगा। अब मैं नहीं कह सकता कि उस मीटिंग में जो मैम्बर थे उन्होंने किस आधार पर स्वामी आदित्यवे । को एक्टिंग चेयरमैन बनाया और किस आधार पर चौधरी रण सिंह जी को बनाया।

Shri Baldev Tayal: Thank you, Sir.

चौधरी राम लाल वधवा: मेरी प्रार्थना है कि मेरा 2013 नम्बर क्वै चन बड़ा इम्पोर्टैंट था जो नाथपा झाखड़ी के विशय में था। वह टेक अप नहीं हो सका। (गोर)

श्री अध्यक्ष: अब टाईम खत्म हो गया। यह कोई नयी चीज नहीं है।

चौधरी राम लाल वधवा: हमने नोटिस दिया है। 27 मैम्बरों के दस्तखत है। सारे अपोजी ।न के मैम्बर है, जिन्होंने दस्तखत किये है। स्पीकर साहब एग्रीमेंट चेज हो रहा है। (गोर) इस सवाल पर हाफ एन आवर डिस्क ।न होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए।

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब 27 मैम्बरों ने दस्तखत करके नोटिस दिया है। यह सारी स्टेट का मामला है। (गोर)

Mr. Speaker: This is not the place to make that request. Please come to my Chamber. वैसे जिस दिन के बिजनैस के लिए जो सवाल लिस्ट पर होते हैं, उनके बारे में मैं हर किस्म का प्रयत्न करता हूँ कि वह लिस्ट पूरी हो जाये यानी सभी सवाल आ जायें लेकिन एक साइड पर मैम्बर एजिटेटिड फील करते हैं जब सवाल ओरल आनसर के लिए नहीं आ पाता और दूसरी तरफ एक एक सवाल पर दस-दस, बारह-बारह सप्लीमेंटरी करते हैं चाहे वे मेन सवाल से संबंधित हों या न हों। उनके लिए भी एजिटेट करते हैं और मुझे वे एडमिट करने पड़ते हैं। या तो आप मेरे को अपना व्यू दे दीजिए कि हम भी ऐसा कर लें जिस प्रकार से लोक सभा में है कि एक सवाल पर दो सप्लीमेंटरी होंगी। एक सवाल पूछने वाला कर सकता है और एक दूसरा कोड़ और मैम्बर कर सकता है ऐसा करने से we may be able to cover all the questions on the list. फिर भी अगर कोई सवाल रह जाता है और उसके लिए हाफ एन आवर डिस्कान की मांग करें तो I can consider that on merits.

चौधरी राम लाल वधवा: मैं रूल 57 की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ तथा आपसे गुजारि कराना चाहता हूँ। (गोर)

Mr. Speaker: No please. If there is some particular thing, please come to my Chamber and discuss it. House is not the place for making that request.

वाक आऊट

चौधरी हुक्म सिंह: स्पीकर साहब, मैंने एक एडजर्नमेंट मो इन दी थी, उसको आने रिजैक्ट कर दिया है। वैसे तो मैं आपके हुक्म का सम्मान करता हूँ लेकिन यह बड़ा गम्भीर मामला है। वहां पर लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पुलिस ने लाठी और गोलियां चलाई। (10र)

श्री अध्यक्ष: जो एडजर्नमेंट मो इन रिजैक्ट कर दी गई है, उसके बारे में यहां पर कुछ नहीं पूछा जा सकता। (10र)

चौधरी हुक्म सिंह: मामला बड़ा गम्भीर है। किसान बेचारे बिजली की वजह से दुःखी हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: जहां तक पावर की भार्टेंज का संबंध है उसके बारे में पांच काल अटैं इन मो इन मैंने एडमिट कर रखे हैं। क्योंकि मुझे भी पता है कि उससे हमारे किसानों के लिए मुसीबत पैदा हुई है। लेकिन अब मुझे यह भी पता चला है कि आजकल स्ट्राइक खत्म होने के बाद बिजली की हालत काफी हद तक सुधर चुकी है। (10र)

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, यह बिजली का सवाल नहीं है। (10र)

चौधरी संत कंवर: कांग्रेस के एक मैम्बर ने स्वयं कहा है कि तीन घंटे से ज्यादा बिजली किसानों को नहीं दी जा रही है। (गोर)

चौधरी राम लाल वधवा: यह बिजली का नाम ले कर.....
.....(गोर)

श्री अध्यक्ष: जो चीज मैं डिस-अलाऊ कर चुका हूं उस पर दोबारा डिस्कान नहीं हो सकती। If you want to say anything you can come and see me in my Chamber. (Interruptions) आनरेबल मैम्बरज मुझे चार काल अटैंतान मोतान सर्वश्री राम लाल वधवा, हरस्वरूप बूरा, बीरेंद्र सिंह तथा श्रीमती सुशमा स्वराज एम0एल0एज0 साहेबान की ओर से बिजली की कमी और उसमें चोरी की वजह से पब्लिक में पैदा हुई दिक्कत के बारे में प्राप्त हुए हैं। मैं उनको कन्सीलिडेट करके एडमिट करता हूं। अब चौधरी राम लाल वधवा जी नोटिस पढ़ दें। (गोर)

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, मेरा भी एक काल अटैंतान मोतान था। (गोर)

श्री अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जिन विशयों पर मैं अपनी रूलिंग दे चुका हूं, उनके बारे में इस वक्त कोई बात करना ठीक नहीं है। आप मेरे चैम्बर में आ जाएं वहां पर मैं बात कर लूंगा।

चौधरी हुकम सिंह: हम एज ए प्रोटैस्ट वाक आऊट करते है।

(इस समय सर्वश्री हुकम सिंह तथा संत कंवर सदन से वाक आऊट कर गए)

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, कल धरोंडा के अन्दर 10 हजार किसानों पर लाठियां/गोलियां चलाई.....गई (गोर)

श्री अध्यक्ष: क्या आपने इसका नोटिस दिया है? (गोर)

चौधरी गंगा राम: मैंने अपना काल अटैं इन मो इन दिया था। (गोर)

श्री अध्यक्ष: अगर आपने काल अटैं इन मो इन दिया है तो मैं उसको कंसीडर करूंगा। आप उस काल अटैं इन मो इन की यहां इतनी क्यों वकालत करते हों? (गोर)

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, वहां पर किसानों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, उनके साथ ज्यादाती की गई। (गोर)

श्री अध्यक्ष: अब राम लाल वधवा जी अपना नोटिस पढ़ेंगे।

श्री बीरेंद्र सिंह: स्पीकर साहब, मेरी एक बहुत इम्पोर्टैंट बात रह गई है। मेरी एक एडजर्नमेंट मो इन थी। हांसी के एक

आदमी ने सिर्फ तीन हजार रुपये का कर्जा गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए ले रखा था। वह आदमी रैवेन्यू लाक-अप के अन्दर मार दिया गया। जबकि यहां करोड़ों रुपये का घपला किया गया है मगर इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही।
(गोर)

Mr. Speaker: That adjournment motion has been disallowed by me. बड़े अफसोस की बात है कि किसी आदमी की डैथ हो गई। But that is not a sufficient cause to adjourn the business of the House during the Budget Session. इस प्वायंट को रोज करने के लिए बसजट सै इन में आपको सफ़ीरि येंट अपरच्युनिटीज मिलेगी।

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, इस को काल अटैं इन मो इन में बदल दीजिए। (गोर)

Mr. Speaker: For that you please come and see me in my Chamber.

ध्यानाकर्षण सूचना

बिजली की कमी तथा चोरी के परिणामस्वरूप जनता को असुविधा होने तथा इसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ने संबंधी।

Mr. Speaker: Mr. Ram Lal, now you may please read out call attention motion, which has been admitted in a

consolidated form, regarding shortage and theft of electricity etc.

@ Chaudhri Ram Lal Wadhwa

Chaudhri Har Swarup Bura

Shri Verender Singh

Smt. Sushma Swaraj.} I want to draw the attention of this august House towards the matter of an urgent public importance that the power (electricity) condition in the State of Haryana is becoming worst day by day. The agricultural and industrial sectors are badly affected due to non-availability of power. The generation of electricity is day by day decreasing due to in-efficiency and mis-management of Haryana Government and the Haryana State Electricity Board. The situation has become so grave that the people in Haryana are living in darkness. Even the drinking water is not available to the citizens due to non-supply of electricity to the water works. Thermal Plants of Panipat and Faridabad are not working properly due to mismanagement. technical defects and shortage of coal. The scarcity of power is badly affecting the agricultural and industrial production and the economy of the State is shaken. The supply of power from all sources had been reduced to about 40 lakhs units per day against a requirement of 130 lakhs units. Even this decreased supply is irregular and no one knows when the power will come. The Bhakra Management Board is also diverting power to other States i.e. Jammu and Kashmir, etc., from the quota of Haryana, and the Haryana Government and the Electricity

Board, Haryana has hopelessly failed to watch and safe-guard the interests of the people of Haryana.

Further, the power crisis has proved a cruse to the farming in Haryana particularly in the drought prone areas and generally in all of the State. Crops of wheat, gram and sarson are withering out due to the acute shortage of power. The above said crops will be completely ruined if the present power situation does not improve. The farmers be ensured supply of sufficient power immediately to provide atleast one water to the withering crops.

Special measure to supply adequate power to agricultural purposes for longer period be adopted particularly in the areas where crops are withering out due to non-availability or inadequacy of power and where the canal water facilitiesa are quite meagre.

Jui feeder which has not been running for the last one and a half month because of complete non-supply of power to the lift system installed on the same canal to lift the running water. This failure of running of water has caused a wide spread devastation in about 30 villages of three constituencies namely, Meham, Jullana and Mundhal. The standing crops of wheat, sarson, and gram of these villages are withering out. There is no provision like tubewells etc. to irrigate the standing crops. The State Govt. is requested to direct the Irrigation Department to discharge the required water in this canal immediately. This is possible only if there is a regular and adequate supply of power to the lift system of this cananl.

The present power crisis has also affected the housewise. All the electric implements to be used in the house and in kitchen have become useless due to non-availability of electricity throughout the day. Whereas the production of industrial units are decreasing due to the non-availability of electricity and the labourers are also becoming victims of the problems like lay off and retrenchment. The utencils industry of Yamunanagar and the science industry of Ambala are about to wreck. At the first instance electricity is not available and if it is available at all it is supplied at intervals and one does not understand that at what time the labourers be called to work and at what time they may be permitted to leave. At such a critical time the decision adding fuel to the fire. "The electricity might be available or not but has caused more resentment amongst the people. In spite of the announcement made by the State Government for changing this decision the bills are being realised at enhanced rates. People have shown their resentment even on the roads against the cut on electricity and enhancement of the electricity rates. But no effective steps have been taken by the Government to solve this problem.

Moreover, the recent survey conducted by the HSEB. One of the reasons may be due to the sluggish meters used by the industrialists in different parts of the State of Haryana i.e. Sonapat, Yamunanagar, Jagadhri and Bahadurgarh. Even the civil hospitals are without power supply throughout the day and as a result of which urgent operations have to be postponed. Patients are dying for want of operations which are not performed because of lack of electricity. Even the students community find it difficult to

cope up with their studies which they have to make as the final examinations are at hand. The distribution is altogether defective and effected the various sectors of the economy.

If the present power crisis continues it will amount unrest among farmers, industrialists, labourers, students and the people of the whole State of Haryana, which may worsen the law and order situation. The regular and sufficient supply of electricity may be made to agricultural sector, industrial, hospitals, education, drinking water and domestic purpose and the supply should be in day light maximum. They request the State Government to reply as soon as possible during the present budget session.

डा० मंगल सैन: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, जब मैं सदन में आया तो मेरी मेज पर एक पम्फलट पड़ा हुआ पाया गया। इस के अन्दर आसाम की स्थिति के बारे में भी लिखा है। मैं आपकी रूलिंग चाहता हूँ कि क्या आसाम के बारे में कोई भी मैटर सदन में लाया जा सकता है और क्या यह पम्फलैट आपकी इजाजत से यहाँ रखा गया है? अगर रखा गया है तो मैं आपका ध्यान रूलज की तरफ दिलाना चाहता हूँ। (गोर)

(इस समय विरोधी पक्ष के कई मैम्बर पम्फलैट की कापियां लहराने लगे।) (गोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: I have no knowledge of it as to who has placed it on the Tables?

विरोधी पक्ष की ओर से आवाजें: स्पीकर साहब, यह कैसे रखा गया है?

Mr. Speaker: If this pamphlet has been placed on any-body's Table, it has been done without my permission. Therefore, I cannot take cognizance of it. I will enquire into the matter as to who and how it has been placed on the Tables.

चौधरी गंगा राम: यह तो सर, बंडल में इक्ठे बंधे हुए है।

श्री अध्यक्ष: चौधरी गंगा राम जी, उस बात को रिपीट करके मुझे एजुकेट करना आप को भाभा नहीं देता। मैंने रूलिंग दे दी है कि यह चीज मेरी इजाजत के बगैर रखी गयी है, आगे से ऐसी कार्यवाही नहीं होगी?

मुख्य मंत्री(चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय यह भी हो सकता है कि इन्होंने ही रखा हो।

श्री वीरेंद्र सिंह: हम कहां से ले आये? (तोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Would the Hon'ble Minister like to make a statement on the Call Attention motion read out by Chaudhri Ram Lal Wadhwa, today or later?

Irrigation and Power Minister(Sardar Tara Singh): Sir, I will make a statement tomorrow.

श्री मूलचंद जैन: सर, मैंने भी एक काल अटैं इन मो इन का नोटिस दिया है। कल घरौंडा में एक 302 का केस दर्ज हुआ है और उन्हें पुलिस अफसर का गिरफ्तार किया गया है। लोगों की मांग है कि.....

Mr. Speaker: Babu ji, it has been received in the office at 9.30 a.m. today. I have not seen it so far. The office will deal it and then I will examine it when it comes to me.

श्री मूलचंद जैन: मेरी अर्ज यह है कि उस काल अटैं इन मो इन को एडमिट किया जाये ताकि लोगों के सामने फ़ैक्ट्स आ सकें।

श्री अध्यक्ष: बाबू जी, वह अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा है।

सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र

श्री अध्यक्ष: अब एक मंत्री महोदय डबवाली में हुई घटना के संबंध में जांच आयोग की रिपोर्ट पे आ करेंगे।

वित्त मंत्री(चौधरी खुरीद अहमद): मैं जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 (4) के अधीन की गयी अपेक्षा के अनुसार डबवाली में भीला देवी (पत्नी श्री नफे सिंह) के अभिकथित बलात्कार की घटना, किन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई तथा 13 से 16 जुलाई, 1980 की अवधि के दौरान डबवाली में लोगों के समूह पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने की घटना की

जांच करने के लिए श्री प्रित पाल सिंह, जांच आयोग द्वारा दी गयी जांच रिपोर्ट तथा उस पर की गयी कार्यवाही का ज्ञापन मेज पर रखता हूं।

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, इस रिपोर्ट के आने के बाद सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये वरना इस सरकार को बरखास्त कर देना चाहिये। यह रिपोर्ट सरकार के ऊपर कलंक है। इसने लाल चेहरे को काला कर दिया है। (व्यवधान व भाोर)

चौधरी राम लाल वधवा: अध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट पर डिस्कान अलाऊ की जाये।

श्री अध्यक्ष: आप मुझे नोटिस दीजिए।

डा० मंगल सैन: हमने तो आलरैडी नोटिस दे दिया है।
(तोर)

Mr. Speaker: No interruptions please. अब एक मंत्री हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फ़ैसिलिटीज टू मैम्बर्ज) अमेंडमेंट बिल पे टा करेंगे।

Dr. Mangal Sein: Discussion may be allowed on this Report, Sir. (Interruptions).

Mr. Speaker: Dr. Sahib, please sit down. No interruptions please.

बिल्ज (इंट्रोड्यूसड—सदन की अनुमति से)

(i) दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फ़ैसिलिटीज टू मैम्बर्ज) अमेंडमेंट बिल, 1981

वित मंत्री(चौधरी खुर ग़िद अहमद): में प्रस्ताव करता हूं कि—

हरियाणा विधान सभा (सदस्य-सुविधा) सं गोधान विधेयक, प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि—

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फ़ैसिलिटीज टू मैम्बर्ज) अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।

श्री अध्यक्ष: प्र न है कि—

दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (फ़ैसिलिटीज टू मैम्बर्ज) अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

वित मंत्री(चौधरी खुर ग़िद अहमद): स्पीकर साहब, अब में बिल प्रस्तुत करता हूं ।

(ii) दि हरियाणा स्टेट लैजिस्लेटिव (प्रिवैन् ग़ान आफ डिस्कवालीफिके ग़ान) अमेंडमेंट बिल, 1981

वित्त मंत्री(चौधरी खुर गिद अहमद): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि—

हरियाणा राज्य विधान-मण्डल (निरर्हता-निवारण) सं गोधन विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि—

दि हरियाणा स्टेट लैजिस्लेचर (प्रवै गन आफ डिसक्वालीफिके गन) अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

चौधरी राम लाल वधवा(करनाल): सर, इस बिल की इंट्रोडक् गन के बारे में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि इसके बारे में पहले एक आर्डिनैस इू हुआ था, उसकी डिस-एप्रूवल का नोटिस मैंने दे रखा है। अब यह बिल इंट्रोडक् गन के लिये आया है, मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह इंट्रोडयूस न किया जाये क्योंकि मैंने पहले ही इसकी डिस-एप्रूवल का नोटिस दे रखा है। या तो इ स बिल की इंट्रोडक् गन को और आर्डिनैस की डिस-एप्रूवल के नोटिस को इक्ठ्ठा ही ले लिया जाये और इन दोनों पर इक्ठ्ठे ही डिस्क गन हो जाये वरना मैं इस बिल की इंट्रोडक् गन का विरोध करता हूँ।

Mr. Speaker: Chaudhri Ram Lal Ji, would you like to speak on your objection? If you will speak then the Minister will also have to reply to that.

चौधरी राम लाल वधवा: मैं तो इसके बारे में यही आब्जैक्टिव बन करना चाहता हूँ कि जो आर्डिनैस इंट्रोड्यूस हुआ था और जिसकी डिस्-एप्रूवल का मैंने नोटिस दिया हुआ है, पहले उसका फैसला किया जाना चाहिए। उसके बाद बिल को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिये। यदि आज यह बिल इंट्रोड्यूस हो जाता है तो यह लीगली भी ठीक नहीं होगा क्योंकि जो आर्डिनैस की डिस्-एप्रूवल का नोटिस मैंने दिया है पहले उसका फैसला होना चाहिए। इसलिय मेरी प्रार्थना यह है कि इस बिल को इंट्रोड्यूस करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिये।

Mr. Speaker: As far as the question of leave to introduce the bill is concerned इसमें जो मैम्बर साहेबान चाहें इसके हक में वोट कर सकते हैं और जो मैम्बर साहेबान चाहे, इसका विरोध कर सकते हैं। जो आपका डिस्-एप्रूवल का मोशन है, वह तो एक्जुअली इस बिल की कंसिडरेशन स्टेज पर आएगा। उस समय आप जो कहना चाहें, कह सकते हैं।

चौधरी राम लाल वधवा: ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है कि—

दि हरियाणा स्टेट लैजिस्लेचर (प्रिवैन्शन ऑफ डिस्कवालीफिकेशन) अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वित्त मंत्री(चौधरी खुरीद अहमद): स्पीकर साहब, मैं बिल प्रस्तुत करता हूँ।

स्वामी अग्निवे 1: स्पीकर साहब, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी श्री प्रितपाल सिंह जी की डबवाली कांड के ऊपर रिपोर्ट पे 1 की गयी है। (गोर व व्यवधान) मैं उसके बारे में यह कहना चाहता हूँ कि हिंदी में रिपोर्ट की कोई कापी नहीं है। (गोर व व्यवधान)

वित्त मंत्री(चौधरी खुरीद अहमद): सर, कमीशन ने अपनी रिपोर्ट इंगलि 1 में दी है। उसका ट्रांसलेशन या तो तर्जुमा करवाने में गलती भी हो सकती है। इसलिए हमने उसको ज्यों का त्यों रखा है।

श्री अध्यक्ष: स्वामी जी, क्या आपका प्वायंट खत्म हो गया है?

स्वामी अग्निवे 1: नहीं जी, एक तो डबवाली कांड की रिपोर्ट केवल अंग्रेजी में है जोकि हिंदी में भी जरूर होनी चाहिये। इसके अलावा हरियाणा फाईनैलिटील कार्पोरेशन की रिपोर्ट भी हिंदी में नहीं है।

Mr. Speaker: I do not know when this report was presented to the House? Swami Ji you are raising this point today.

स्वामी अग्निवे 1: वह भी टेबल पर रख दी गयी है?

श्री अध्यक्ष: कब रख दी गयी है?

स्वामी अग्निवे T: यह तो पहले ही हो चुकी हो।

चौधरी खुर पीद अहमद: स्पीकर साहब, डबवाली के बारे में कमि न की रिपोर्ट (11.00बजे) सदन में रखी गई है। यह एक जजमेंट है और जज ने जिन लफ्जों में जजमेंट लिखा है हमने उसको ज्यों का त्यों उन्हीं लफ्जों में रखना है। तर्जुमा करने से कोई भी भाब्द इधर उधर हो सकता है और connotation can change. इसलिए औरिजनल रिपोर्ट को या जजमेंट को ट्रांसलेट करने से कुछ का कुछ मतलब निकल सकता है। मैं समझता हूं कि अगर कोई मैम्बर हिंदी में इस रिपोर्ट को चाहता है तो वह खुद ट्रांसलेट कर ले या किसी से ट्रांसलेट करवा लें।

Mr. Speaker: I will go a step further. The translators of the Haryana Vidhan Sabha Secretariat will be placed at the disposal of Members who wish to get the report translated.

स्वामी अग्निवे T: अध्यक्ष महोदय, बड़ी अजीब बात है। हमारे जितने भी बिल है वे अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट होकर आते हैं। रूल्ज ट्रांसलेट हो रहे हैं और जो काल अटैं इन नोटिस आदि है वे भी सब अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट होकर सदन में रखे जाते हैं लेकिन इस रिपोर्ट के बारे में कहा जा रहा है कि कौनोटे इन बदल जाएगी। (व्यवधान)

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, आपकी अपनी रूलिंग है कि हर कागज हिंदी और अंग्रेजी में रखा जाएगा तो यह कहना कि हिंदी में तर्जुमा करने से अर्थ बदल जाएगा या अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक नहीं है। क्या आज मुख्य मंत्री महोदय को अंग्रेजी में रिपोर्ट पढ़नी आएगी। वे आपसे तर्जुमा करवाएंगे (हंसी)। इसलिए हमारे लिए नहीं तो अपने मुख्य मंत्री की सुविधा के लिए करा लो।

Mr. Speaker: All right. Please sit down. This is not the zero hour. अभी डबवाली रिपोर्ट पे 1 हुई उसके बारे में आपने प्वायंट रेज किए और दूसरी तरफ से उसका जवाब आया है। But kindly do not convert this time into zero hour. The matter under discussion is something entirely different. मैम्बर साहेबान इस प्वायंट पर इतना ऐजिटेटिड फील कर रहे है लेकिन मैं समझता हूं कि इतनी हीट जनरेट करने वाला कोई प्वायंट नहीं है। कुछ ज्यादा ही हीट जनरेट हो गई है। मैं स्वामी जी को कहना चाहता हूं कि विधान सभा के ट्रांसलेटर्ज दो घंटे के लिए उनके डिस्पोजल पर होंगे। वे उनसे ट्रांसलेट करा सकते है। The matter is now closed.

स्वामी अग्निवे 1: अध्यक्ष महोदय, जब और सारे कागज हिंदी में ट्रांसलेट होकर आते है.....(व्यवधान)

Mr. Speaker: Swami Ji, please sit down. I have decided the matter. I will not allow further discussion on it.

(iii) दि हरियाणा एसैि ऱयल सर्विसिज मैँटीनैँस
(अमैँडमैँट) बिल, 1981

वित मंत्री(चौधरी खुर गिद अहमद): स्पीकर साहब, मैँ प्रस्ताव करता हूँ कि:—

दि हरियाणा एसैि ऱयल सर्विसिज मैँटीनैँस (अमैँडमैँट) बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि—

दि हरियाणा एसैि ऱयल सर्विसिज मैँटीनैँस (अमैँडमैँट) बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।

चौधरी संत कंवर(हसनगढ़): स्पीकर साहब, यह जो आर्डिनैँस इ लू किया गया और उसको एक्ट बनाने के लिए जो बिल लाया गया है, हम इसका विरोध करते है।

श्री अध्यक्ष: हम कहने का क्या मतलब है। आप इसका विरोध करते हैं या सब विरोध करते है?

चौधरी संत कंवर: स्पीकर साहब, हमारा लोकदल के सभी मैँम्बरों का इस बारे में औब्जैव ान है। स्पीकर साहब, सब को पता था कि 9 तारीख को असैँम्बली बैठेगी। लेकिन हाउस के एक हफता बैठने के पहले सरकार ने आर्डिनैँस जारी कर दिया। यह बहुत गलत बात है। दूसरी बात यह ळे कि इस प्रकार का बिल नागरिकों को डैमोकेसी खत्म करने के लिए लाया जा रहा

है। मेरा कहना है कि इस तरह का बिल हाउस में नहीं आना चाहिए। स्पीकर साहब, हम इसका सख्त विरोध करते हैं। यह बिल प्रदेश की जनता व कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों को छिनने वाला है।

चौधरी राम लाल वधवा(करनाल): स्पीकर साहब, मेरा पहला औब्जैक्टिव तो वैसा है जैसा कि पिछले बिल के ऊपर था। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि मैं इसकी डिस-एप्पूवल का भी नोटिस दे रखा है। यह एक लीगल बात है कि बज तक डिस-एप्पूवल का फैसला न हो, बिल को हाउस में लाना सरकार के लिए ठीक नहीं है। दूसरी बात आर्डिनैस के बारे में है जैसा कि मेरे साथी चौधरी संत कंवर ने कहा है कि यह हाउस की कंटैम्पट है। आर्डिनैस को एक हफ्ता पहले जारी करने की क्या अरजेंसी थी। हाउस को तो बुलाया ही गया था। अगर हाउस ने बुलाया जा रहा होता तो आर्डिनैस इतनी करने वाली बात ठीक हो सकती थी। इसलिए जब हाउस मीट कर रहा था और इसी दौरान आर्डिनैस इतनी किया गया है तो यह हाउस की प्रिविलिज को ब्रीच किया गया है और हाउस की कंटैम्पट है। स्पीकर साहब, मेरा कहना यह है कि इस इतनी पर विचार किया जाए और सरकार से यह पूछा जाए कि क्या इस तरीके से आर्डिनैस जारी हो सकता है? स्पीकर साहब, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से इस बिल की इंट्रोडक्शन का विरोध करता हूँ।

श्री अध्यक्ष: यह मामला मैंने गवर्नमेंट से डिस्कस कर लिया है। I agree that once the Assembly has been called, the promulgation of any ordinance is to be discouraged. This ruling has been given by the Speaker of the Lok Sabha. लेकिन कभी-कभी सरकार को एसैंिायल सर्विसिज को मेनटेन करने के लिए ऐसे मैयर्ज लेने पड़ते हैं जिस का एक दिन के लिए भी इन्तजार नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याम में यह मैटर बिजली की स्ट्राईक के बारे में था (व्यवधान)। यह एसैंिायल सर्विसिज को मेनटेन करने का मैटर था। मैं समझता हूँ कि यह बहुत जरूरी मामला था।

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि यह सिचुऐंन उस दिन ही पैदा नहीं हुई। यह सिचुऐंन तो पहले से ही थी।

श्री अध्यक्ष: यह सिचुऐंन कितने दिनों से चल रही थी, जब तक आपके सामने पूरे फ़ैक्टस एंड फिर्ज न हों कि आगे सिचुऐंन क्या होगी तब तक कुछ किया भी नहीं जा सकता।

श्री बलदेव तायल(हांसी): स्पीकर साहब, मैं इस बिल की इंट्रोडक्शन का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। स्पीकर साहब, बहुत दफा सरकार की यह चेश्टा रहती है कि ऐसे बिल पास किए जाएं जिससे नागरिक अधिकारों का हनन हो। स्पीकर साहब, यह बिल डैमोक्रेटिक प्रिंसिपल्ज के अगेन्सट है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन मंत्री को मीसा के दिनों की याद

दिलाना चाहता हूं और मुझे अच्छी तरह से याद है कि 9 महीने के अन्दर ये बीमार भी पड़ गए थे.....

Chaudhri Khurshid Ahmed: I think, this has got nothing to do with the Bill.

परिवहन मंत्री(श्री जगन नाथ): बीमार जरूर पड़ गया था लेकिन वजन बढ़ गया था।

श्री अध्यक्ष: कृपया इंट्रस्ट न करें।

श्री बलदेव तायल: और आज ये ऐंटी जनता बिल के समर्थन में लगे है। मुझे पता नहीं है कि ये क्या सोचकर लगे हुए है। लेकिन मुझे पूर्ण वि वास है कि एक न एक दिन इनकी आत्मा जागेगी। हो सकता है कि जिस तरह से लाला बलवंत राय तायल की आत्मा जागी है उसी तरह से जिस दिन चौधरी भजन लाल इनको मंत्रीमंडल से निकाल देंगे, इनकी आत्मा भी जाग जाए। अध्यक्ष महोदय, मुझे पूर्ण वि वास है कि उस दिन ये इस बिल के विरोध के लिये अव य ही खड़े होंगे। (हंसी) तो अध्यक्ष महोदय, मैं रिकवैस्ट करूंगा कि सरकार इस बिल को इंट्रोडयूस करने से पहले एक बार फिर विचार करे। यह एक बहुत अहम बिल है जिसके जरिये सरकार अपने हाथ में एक बड़ी पावर लेने जा रही है। ऐसा करके हर सरकारी कर्मचारी को और दूसरी लोग जो कि इन कर्मचारियों के सिम्पेथाइजर हों, उनको भी गिरफ्तार करने की पावर इस बिल के जरिये सरकार अपने हाथ में लेने जा रही है।

Mr. Speaker: I may tell the hon. Members that the occasion for raising this discussion will be after, the Bill has been introduced.

Shri Baldev Tayal: I will take a second more. अध्यक्ष महोदय, इस बिल के अंदर एक दो और बुरी बातें हैं जैसे काग्नीजेबल औफैन्स बनाना और नान बेलेबल वारंट जारी करना वगैरह। इन्हीं कारणों से मैं अपनी व अपनी पार्टी के साथियों की तरफ से इस बिल का विरोध करता हूँ।

श्री अध्यक्ष: प्र न है कि—

दि हरियाणा एसैमिंटियल सर्विसिज मैटीनेंस (अमेंडमेंट) बिल प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, हम इस पर डिवीजन मांगते हैं। After ascertaining the votes of the Members by voices Mr. Speaker announced that 'Ayes' have it. This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker after calling upon those Members who were for 'Aye' and those who were for 'No' respectively to rise in their places and on a account having been taken declared that the motion was carried.

The motion was carried.

वित्त मंत्री(चौधरी खुर गिद अहमद): स्पीकर साहब, मैं बिल प्रस्तुत करता हूँ।

वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 के एकसैस डिमांडज ओवर ग्रांटस एंड एप्रोप्रिए ांज प्रस्तुत करना

वित्त मंत्री (चौधरी खुर गीद अहमद): अध्यक्ष महोदय, मैं—

(i) वर्ष 1975-76 के अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगे; तथा

(ii) वर्ष 1976-77 के अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगों पे ा करता हूं।

राजपाल के अभिभाषण पर चर्चा

श्री अध्यक्ष: साहेबान, अब राजपाल महोदय के अभिभाषण पर डिस्क ान होगी। श्री सुमेर चंद भट्ट अपना मो ान मूव करेगे।

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, एक मिनट के लिये मैं बोलना चाहूंगा। मेरा प्वायंट आफ आर्डर है, मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप किस रूल के तहत अपना प्वायंट आफ आर्डर रेज कर रहे है?

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब, मैंने पहले भी क्वै चन आवर में कहा था.....

श्री अध्यक्ष: कुछ भी रिकार्ड न किया जाए।

चौधरी गंगा राम: स्पीकर साहब.....

.....

श्री सुमेर चंद भट्ट(नांगल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ। कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित भावों में पेश किया जाए—

कि इस सत्र में इक्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिये राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 9 मार्च, 1981 को सदन में देने की कृपा की है।

स्पीकर महोदय, यह एक पार्लियामेंटरी डैमोक्रेसी की प्रणाली है कि जब भी साल का नया इजलास शुरू होता है तो गवर्नर महोदय अपने अभिभाषण से सरकार की नीतियों के लिये प्रकाश डालते हैं। लेकिन मुझे कल अफसोस हुआ कि ऐसे मौके पर भी जब गवर्नर साहब यहां पर तारीफ लाए तो हमारे साथियों में से बिना ही कारण के कुछ ने तो बाईकाट किया और कुछेक साथियों ने वाक आउट करने का फैसला किया। स्पीकर साहब, मैं यह मानता हूँ कि अपोजीशन का यह अधिकार है कि जब उनको ऐसा लगे कि हालत का तकाजा है या सिचुएशन इस तरह से वारंट करती है तो वे इस तरह का कदम ले सकते हैं। लेकिन कम से कम कल जब गवर्नर साहब हाउस में आए तो ऐसा

कोई कारण नहीं था जिसकी वजह से उनको मजबूर होकर ऐसा फैसला करना पड़ा हो। स्पीकर साहब, जिस तरह की प्रणाली हमारे देश में चल रही है आप उस बात को भली भाँति जानते हैं कि अपोजी इन भी सरकार का एक हिस्सा होती है। इंग्लैंड में, जहाँ से यह तरीका हमने अपनाया है अपोजी इन को किंगज अपोजी इन कहते हैं। अपोजी इन की भी उतनी ही जिम्मेदारी सरकार को ठीक चलाने की होती है जितनी जिम्मेदारी रूलिंग पार्टी की होती है। लेकिन हमारे यहाँ सारे ही देश का सियासी माहौल उखड़ा हुआ है। हमें यह चाहिए कि हम अपोजी इन वालों और रूलिंग पार्टी वाले आपस में बैठकर खोज करें कि अपने उस फर्ज को निभाने के लिए जिसके लिये लोगों ने हमें चुन कर यहाँ भेजा है किस ढंग से हम ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकते हैं मुझे एक बात की ख़ुशी है कि अब अपोजी इन के लीडर बाबू मूल चंद जैन जी हैं इनका इस हाउस में बहुत तजुर्बा है और इस हाउस को ठीक ढंग से चलाने में भी इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दूसरी तरफ इस सदन के जो लीडर हैं, वे भी सौभाग्य से एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर ठीक चीज को बिना किसी हिच-किचाहट के मान लेते हैं। स्पीकर महोदय, मैं चाहूँगा कि अगर वाकई इस सदन ने यह सब करना है जिसके लिये लोगों ने हमें चुन कर भेजा है तो आपस में दोनों तरफ के सदस्यों को ब्रेक कर उस तरीके की खोज करनी चाहिए, जिससे यह हाउस ज्यादा इफैक्टिव हो सके। यह एक मेरी उम्मीद है और मुझे विश्वास है कि अगर इस तरह की कोशिशें शुरू हो जाएँ तो बिल्कुल एक नया

तरीका और एक स्क्वाइल आफ फंकानिंग अपोजी इन का भी और रूलिंग पार्टी का भी आपस की बात चीज से निकल सकता है। स्पीकर साहब, कल इस हाउस में जो गवर्नर साहब ने अपना अभिभाषण दिया उसमें कोई बहुत हाई साउंडिंग फ्रेजिज का इस्तेमाल नहीं किया गया। न ही उन्होंने उसमें कोई बहुत नये नये नारे दिये बल्कि उन्होंने बहुत ही स्वाभाविक रूप से जो सरकार की पिछले साल की गति रही, उसकी तरफ इशारा किया और अगले माली साल में सरकार की जो योजनाएं और नीतियां हैं, उन पर पूरा-पूरा प्रकाश डाला। गवर्नर साहब मुबारिकबाद के पात्र हैं कि वे अपना कीमती समय निकाल कर हाउस में तारीफ लाए और अपना एड्रेस पढ़ा। गवर्नर साहब ने मोटे तौर पर दो बातें ऐसी कहीं जिनकी तरफ वे चाहते थे कि हाउस की तवज्जह जाए। एक बात तो उन्होंने सोशल जस्टिस की डिमांड के बारे में कही और दूसरी तरफ उनका जो फोकस था वह इंक्लीज्ड प्रोडक्शन की तरफ था। स्पीकर साहब, पिछले तीस सालों में एक ऐसी भावना रही है और गाहे बगाहें इस तरह की आवाज आती रही है कि जो कुछ भी डिवैल्पमेंट का काम चला उसका ज्यादा फायदा कुछेक लोगों को ही गया। नतीजें के तौर पर जो लोग गरीब थे वे और गरीब होते गये और जो लोग अमीर थे वे और अमीर होते गये। मैं अपनी सरकार को इस बात के लिये मुबारिकबाद देता हूँ कि इसने इस दिशा में भुरुआत की। हमारी सरकार ने इस बात की तरफ ध्यान दिया है कि कैसे प्रोडक्शन को इंक्लीज किया जाए और कैसे इकोनोमिक डिवैल्पमेंट

की जाए हमारी सरकार ने कुछ ऐसे कार्यक्रम भी अपनाए जिसे सीधा फायदा उन लोगों को हुआ जो सदियों से दबे हुए और पिछड़े हुए थे। गवर्नर साहब ने अपने ऐड्रेस में बताया कि सरकार सो गल जस्टिस अचीव करने के लिए किस तरह से सक्रिय है और कितनी तत्परता से एक के बाद दूसरा कदम लेती जा रही है। हमारा छठा पांच साला प्लान कुल मिला कर 1800 करोड़ रुपये का है। उसमें से इस माली साल में 290 करोड़ रुपये चार्ज होने का अनुमान है। पिछले साल की निस्वत यह रकम 36.22 करोड़ रुपये ज्यादा है। इसका ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो आज तक पिसते रहे हैं। स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद इस ऐड्रेस के पैराग्राफ 5 की ओर दिलाना चाहूंगा जिसमें गवर्नर साहब ने सरकार की तरफ से एक एक वचन दिया है कि हरिजनों के लिये टोटल प्लान आउटले का 12.26 प्रति गत पैसा खर्च होगा। जो लोग आज गरीबी की रेखा से नीचे रहे हैं उनमें सब से ज्यादा तादाद हमारे हरिजन भाइयों की है। यही नहीं उनकी हालत को सुधारने के लिये और भी बहुत से कदमों का जिक्र किया गया है, जिनका खास तौर पर मैं जिक्र करूंगा। एक तो सरकार की वह स्कीम है जिसके तहत हरिजन बस्तियों में लाइट देने का फैसला किया गया है और यह काम बड़ी तेजी से सारी हरियाणा स्टेट के गांव गांव में चल रहा है। इसके साथ साथ सरकार ने यह फैसला भी किया है कि जिन हरिजन भाइयों को कई साल पहले प्लॉट अलाट किये गये थे और किसी वजह से वे

प्लाट उनके कब्जे में नहीं गये थे वे अब एक निश्चित समय तक उनमें बांट दिये जाएंगे।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब के एड्रेस के पैरा 4 की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगा। इस पैरा में गवर्नर साहब ने इस बात का उल्लेख किया है कि हरिजनों को छोड़ कर जो लोग पिछड़ी जातियों से ताल्लुक रखते हैं, सरकार ने उनके लिए एक निर्धारित कार्यक्रम चलाया है। दो करोड़ रूपया रख कर एक अलग बैकवर्ड निगम बना दिया। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि जिस उददेश्य को लेकर यह निगम स्थापित किया है और जिन लोगों के हाथ में इस निगम की बागडोर सम्भाली है, वे पूरी तनदेही के साथ काम करेंगे ताकि बैकवर्ड क्लासिज के लोगों का उत्थान हो सके तो आज तक पिछड़ते रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब ने अपने अभिभाषण में हाउसिंग का जिक्र किया है। जब तक हम मकान की समस्या को हल नहीं कर पायेंगे तब तक ऐसी सरकार को चैन नहीं रहता जो वैंल्फेयर सरकार हो। सरकार ने हरियाणा में हाउसिंग बोर्ड की स्थापना की है ताकि सरकार उन लोगों को भी मकान बनाकर दे जिनके पास सिर छिपाने की जगह नहीं है। इन लोगों के लिये अगले साल दस हजार मकान बनाकर देने का टारगेट रखा

गया है जिसमें से 75 परसेंट मकान उन लोगों को देंगे जो या तो हरिजन जाति से ताल्लुक रखते हैं या पिछड़ी जातियों से ताल्लुक रखते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि इस काम को और तेजी से किया जाए क्योंकि इस वक्त जिस रफतार से मकान बनाने का काम चल रहा है, इससे मुमकिन नहीं होगा कि सभी लोगों को मुमकिन नहीं होगा कि सभी लोगों को मकान बनाकर दिये जा सकेंगे। पिछले दिनों पब्लिक अंडरटेकिंगज कमेटी की मीटिंग में हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी आये थे। उस वक्त कमेटी की तरफ से इस प्रोग्राम को और तेज करने पर जोर दिया गया था। हमें इस बात की खुशी है कि बोर्ड के अधिकारियों ने यह आवासन दिया था कि इस स्कीम को और तेज करके कम से कम अर्से में अमलीजामा पहनायेंगे। उन्होंने कम से कम टाइम में मकानों की कमी को पूरा करना है, इसके लिये वे तत्पर हैं और मुझे उम्मीद है कि उन्हें कामयाबी हासिल होगी।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ गवर्नर साहब ने पृष्ठ आठ पर उन लोगों को लीगली मदद देने की बात कही है जो अपने तौर पर खर्चा बर्दास्त नहीं कर सकते। मैं सरकार को इसके लिये मुबारिकबाद देता हूँ कि जहां सरकारकी तवज्जह पिछड़ी जातियों के लोगों की तरफ गई है वहां इन लोगों की तरफ भी गई है जो लीगल खर्चा बर्दास्त नहीं कर सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने मेवात डिवैल्पमेंट बोर्ड कायम किया है। मेवात में वे लोग हैं जो बहुत अर्से से

पिछड़े हुए हैं, सरकार की तवज्जह इनकी तरफ जानी स्वाभाविक ही थी। इसके लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब जब बारिश या ओला-वृष्टि के कारण लोगों की फसलें तबाह हुईं, सरकार ने बिना किसी हिचकिचाहट से, बड़ी तत्परता से इफैक्टिव एरियाज में किसानों की मदद की और जो मुआवजा कोई दूसरी सरकार नहीं दे पाई थी, वह इस सरकार ने किसानों को दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर एड्रेस के पृष्ठ 19 पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हरियाणा में कुछेक जिले ऐसे हैं जिनमें सूखे की वजह से और कुछेक जिले ऐसे हैं जिनमें फ्लड आ जाने की वजह से फसलें तबाह हो जाती हैं या फसल उग नहीं पाती। ऐसे जिलों के किसानों को मदद देने के लिए सरकार ने बजट का काफी हिस्सा निर्धारित किया है। इसके साथ ही साथ सरकार यह भी समझती है कि जब तक इन इलाकों के गरीब आदमियों को अपने पावों पर खड़ा नहीं होने देंगे या वे खड़ा नहीं हो पायेंगे तब तक वे हमें जिन्दगी की दौड़ में पीछे ही रहेंगे। इसलिये सरकार ने फैसला किया है कि ऐसे गरीब भाई, जिनके पास गुजारा करने के साधन नहीं हैं, अगर वे खेती के काम के इलावा या खेती छोड़ कर औद्योगिक क्षेत्र में जाना चाहें तो सरकार ने बहुत सी सहायता देने का न केवल ऐलान ही किया है बल्कि बड़ी तेजी के साथ इस दिशा में कदम भी उठाए

है, इसके लिए मैं सरकार को मुबारिकबाद देता हूँ। जहां तक साधारण आदमियों का ताल्लुक है, जिनको रोजमर्रा की जरूरियात की चीजों की जरूरत होती है और इन चीजों को हासिल करने में जो कठिनाई आती है, उस कठिनाई को दूर करने के लिये पांच हजार से ज्यादा डिपों कायम किए हैं ताकि जो जिन्दगी की जरूरियात को चीजें जैसे आटा, गंदम, घी वगैरह है, इन डिपुओं से उपलब्ध हो सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उन कामों का जिक्र किया है जो गरीबों से ताल्लुक रखते हैं। अब उन लोगों को फायदा हो सकेगा जो आज तक जिन्दगी की दौड़ में पिछड़े ही रहे हैं। इनका पिछड़ापन दूर करना तभी मुमकिन हो सकेगा अगर हम अपने देश की वैल्य को बढ़ायेंगे। इसकी तरफ सरकार ने पूरी तवज्जह दी है सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई हैं जिससे एग्रीकलचरल सैक्टर और इंडस्ट्रियल सैक्टर में तेजी से तरक्की हो सकेगी। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हमारा राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि की तरक्की हो, इसके लिये दो मोटी मोटी बातें ध्यान में रखने की जरूरत पड़ती है। एक है फसल को फलड से बचाया जाए। पिछले कई सालों से हर साल कभी एक जिले में, कभी दूसरे जिले में फलड से फसलों की तबाही होती रही है। इसकी रोकथाम के लिये सरकार ने मास्टर प्लान बनाई है ताकि हमें हमें के लिये इस स्टेट को फलड की मार से बचाया जा सके। लेकिन अभी यह काम पूरी तरह से

मुकम्मल नहीं हुआ है। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि फलड की रोकथाम के लिये जितना प्रावधान इस साल के बजट में इस मास्टर प्लान को पूरा करने के लिये किया गया है, यह ना काफी है। अगर कुछ और पैसा दरकार होगा तो इसका इन्तजाम सरकार कर पायेगी जितना पैसा अब तक लग चुका है उससे यह काम मुकम्मल नहीं हो पाया है। अगर और देरी हो गई तो बहुत सा पैसा जाया होने का अंदाजा है। अम्बाला जिले में जहां हर साल या हर दूसरे साल फलड आता है, फसलों की तबाही होती है। वहां और भी जरूरी है कि फलड की रोकथाम के लिये जो काम चल रहा है वह जल्दी से जल्दी मुकम्मल किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब तक हरियाणा में सिंचाई का इंतजाम नहीं होगा तब तक कृषि के क्षेत्र में तरक्की नहीं हो सकती। इस उद्देश्य को अचीव करने के लिये सरकार ने इरीगेशन की बहुत सी योजनाएं बनाई है और इस साल लगभग साठ करोड़ रुपया इन स्कीमों पर खर्च किया जाना है। इन स्कीमों के पूरा होने पर ही हम उन इलाकों को, जहां अब तक किसान भाइयों को नहरी पानी नहीं दे पाये है, कुछ समय के बाद देना मुमकिन हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब एक बात की तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। किसान के खेत को चाहे पानी नहर से दिया जाए चाहे ट्यूबवैल्ज से दिया जाए एक ही बात है लेकिन खेती के पानी की कमी अम्बाला जिले में बहुत ज्यादा है। जिस

तरह अम्बाला जिले को पानी की जरूरत है, उसी तरह दूसरे जिलों को भी जरूरत है। लेकिन कुछेक जिले ऐसे है जहां नहर का पानी जाता है और कुछेक जिले ऐसे है जहां कमोवे ट्यूबवैल्ज से आबपापि का काम किया जाता है परन्तु न मालूम क्यों इन दोनों की आबियाना की भाहर में जमीन आसमान का फर्क है। मैं अपनी सरकार से दरखास्त करूंगा कि यह जो डिसकिमिनेशन है कि कुछेक को तो पानी कम दाम पर दिया जाए और कुछेक को ज्यादा दाम पर दिया जाए इसे खत्म किया जाए। अगर नहरी पानी मुहैया कराने के लिये सरकार को बहुत सी सबसिडी देनी पड़ती है तो थोड़ी बहुत सबसिडी सरकार उस पानी के लिये भी दे जो ट्यूबवैल्ज से हासिल होता है तो निहायत ही सराहनीय कदम होगा। इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय मैं जिक्र करूंगा एस0वाई0एल0 के पानी का जो हमें पंजाब से मिलना है। मुझे इस बात का पूरा पूरा पता है कि हमारी सरकार इस मामले में बड़ी सजग रही है और इस पानी को प्राप्त करने के लिये इसने कोशिशें भी बहुत की है लेकिन कुछेक मजबूरियों की वजह से हमें अफसोस है कि हम आज इस पोजीशन में नहीं हैं कि वह पानी अपनी स्टेट में ला सकें। यह कोशिशें जारी रहनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट विशेषकर प्रधान मंत्री जी इस मामले में हस्तक्षेप करेगी तो जो हरियाणा के पानी का जायज हिस्सा है, वह हरियाणा का मिलेगा। जब तक यह न हो तब तक मेरा अपने मंत्री महोदय से एक और सुझाव है। जितना पानी हरियाणा में दस्तेआब है, चाहे वह बारिश का है या

दूसरा है, उसका यदि ठीक ठीक इंतजाम किया जा सके तो यह इस सूबे की डिवैल्पमेंट के लिये बहुत सराहनीय कदम होगा। हमारी स्टेट में सबसे ज्यादा बारिश अम्बाला जिला में होती है। पहले तो हम इस बात के लिये पैसा खर्च करते हैं कि यह पानी अम्बाला जिले से निकाल कर किसी तरह से कुरुक्षेत्र जिला में चला जाए, कुरुक्षेत्र जिला से करनाल में चला जाए और करनाल से सोनीपत जिला में चला जाए। तीन महीने तो पैसा इस पानी को निकालने के लिये खर्च किया जाता है और नौ महीने इस बात के लिये खर्च किया जात है कि आबपापि के लिये जहां पानी दस्तेआब नहीं है वहां कहां से पानी लाया जाए। तो मेरा सुझाव यह है कि हमें अपनी स्ट्रैटजी को बदलना चाहिए। इस पानी को जिसे कुदरत हमें देती है, अम्बाला की किसी भी मौसम में होने वाली जरूरत के मुताबिक, हमें अम्बाला में स्टोर करना चाहिए और उतना कुरुक्षेत्र में जाना चाहिए जो अम्बाला को दरकार न हो। अम्बाला और कुरुक्षेत्र की मांग पूरी होने के बाद ही बाकी का पानी करनाल और सोनीपत जाना चाहिए। इस तरह से हमारे बहुत से रिसोर्सिज बच जाएंगे और उस पानी का ठीक प्रयोग हो सकेगा जो कुदरत लैविली हमारे पास भेजती है।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछेक जिले ऐसे है जहां वाटर कोर्सिज का काम चल रहा है। मुझे खुशी है कि इस काम को तेजी से चलाया जा रहा है लेकिन मैं अपने इरीगेशन एंड पावर मिनिस्टर से यह भी दरख्वास्त करूंगा कि वे उन जिलों का भी

ख्याल रखें जहां वाटर कोर्सिज नहीं है। अगर एक जिले के किसान को वाटर कोर्सिज की जरूरत है तो नैचुरली दूसरे जिलों के किसानों को भी जरूरत है।

डिप्टी स्पीकर साहब, जिस तेजी से बिजली पैदा करने के लिये हमारी सरकार काम कर रही है उसके लिए मैं इसे मुबारिकबाद देता हूं। पिछले ही साल कोई 170 मैगावाट बिजली और ज्यादा पैसा करके जो हमारा पूल था उसमें शामिल की गई। अगले साल में भी पूरी पूरी कोर्सा है कि बिजली की पैदावार में और ज्यादा इजाफा किया जाए। इसके लिए हमारा बिजली बोर्ड भी और सरकार भी मुबारिकबाद की मुस्तहक है। इन्होंने बड़ी दूर अंदेरी से काम लेकर के अपने साथ वाले प्रदेशों हिमाचल प्रदेश के साथ नाथपा झाकड़ी प्रोजैक्ट के बारे में ऐग्रीमेंट किया है। इससे 1020 मैगावाट बिजली पैदा होगी और उसमें ज्यादा हिस्सा हरियाणा का होगा। मैं सरकार को एक और सुझाव दूंगा कि यह थोड़ा और दूर अंदेरी से काम ले क्योंकि जिना हाईडल का पोटेंशियल हिमाचल प्रदेश में है, उतना इस रीजन के किसी प्रदेश में नहीं है। अपने रिसोर्सिज की कमी की वजह से हम इस तरह के प्रोजैक्ट्स पर काम चाहे भुरुन भी कर पाएं लेकिन कुछेक और प्रोजैक्ट्स के ऐग्रीमेंट्स हिमाचल प्रदेश के साथ हो जाने चाहिए ताकि जब हमारे रिसोर्सिज हमें इजाजत दें तब इन प्रोजैक्ट्स को हाथ में लिया जा सके और मुकम्मल किया जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, बिजली की जरूरत

सभी प्रदेशों को है और सब में इसकी कमी का एहसास किया जा रहा है इसलिये सबकी नजर हिमाचल प्रदेश की तरफ है लेकिन इस मामले में जो पहल हमने की है वह हमें बनाए रखनी चाहिए। (घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आपकी बैल मुझे सुनाई दे रही है। मैं दो मोटी मोटी बातें, जिनका ताल्लुक हमारे ऐजुकेशन डिपार्टमेंट से है, की तरफ इतारा करके अपना स्थान ले लूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह मानना पड़ेगा कि प्राइमरी, मिडल, हाई तथा कालेज ऐजुकेशन में पिछले साल हमारे यहां काफी तरक्की हुई है। इस साल एक सराहनीय कदम सरकार ने यह उठाया कि प्राइमरी ऐजुकेशन का जो सैक्टर काफी निगलैक्टिड रहा था उसका स्तर ऊंचा करने के लिये एक नया डायरेक्टोरेट कायम किया गया। अब उम्मीद है कि प्राइमरी ऐजुकेशन का जो स्तर बहुत गिर गया था उसको ऊंचा किया जा सकेगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे टीचर साहेबान की बहुत सी ऐसी समस्यायें हैं जिनकी तरफ मैं चाहूंगा कि हमारी सरकार का ध्यान जाए। कुछ ध्यान गया भी है लेकिन अभी काफी कुछ करने को रहता भी है। हमारे बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल में काम करते हैं। ये टीचर्स वही काम करते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में लगे हुए टीचर्स करते हैं। इन स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट्स की तादाद भी काफी है। अगर इन टीचर्स को सरकार ने समान वेतन देने का फैसला किया है तो यह

निहायत सराहनीय कदम है। मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से प्राईमरी स्कूल के टीचर्स की समस्या को सरकार ने हल किया है उसी फराखदिली से कालेज टीचर्स की समस्या को भी यह हल करे। मुझे उम्मीद है कि सरकार उनकी तरफ भी पूरी पूरी तवज्जह देगी और जल्दी से जल्दी कालेज टीचर्स की दिक्कतों का कुछ न कुछ हल किया जाएगा। क्योंकि हमें जान लेना चाहिए कि आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य इन टीचर्स साहेबान के हाथ में है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस उम्मीद के साथ कि जो बहुमुखी तरक्की हमारी स्टेट ने पिछले साल की है उसकी रफतार इस साल न सिर्फ़ मैनटेन की जाएगी बल्कि उसमें ज्यादा इजाफा किया जाएगा। मैं यह प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। जयहिंद।

चौधरी हरस्वरूप बूरा(मेहम): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे साथी माननीय सुमेर चंद भट्ट ने सदन के सामने गवर्नर एड्रेस के समर्थन में जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। उपाध्यक्ष महोदय हमारे साथी ने इस अभिभाषण के संबंध में एक एक पहलू का बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया है। वैसे तो उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने कल सदन के अन्दर जो अभिभाषण दिया वह खुद में ही एक विवरण है और विवरण भी बहुत बेहतरीन और अच्छा है। यही नहीं यह एक विकास तिल और प्रगति तिल विवरण भी है। मैं

इसको इसलिये प्रगति गील और उन्नति गील विवरण कहता हूं क्योंकि इसमें प्रान्त की तरक्की का काफी फ़ैक्टस एंड फिगर्ज के साथ जिक्र किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सारे भाई पढ़े लिखे हैं और उन्होंने इस विवरण को भी पढ़ा भी है। उनहोंने इसमें पढ़ लिया होगा कि पिछले दो सालों में यानि वर्ष 1979-80 और 1980-81 में क्या कुछ हुआ तथा इस वर्ष यानि 1981-82 में क्या कुछ होने जा रहा है। उन्होंने देखा होगा कि पिछले सालों के मुकाबले में इस साल एक एक पहलू के अंदर बढ़ौतरी से पैसा लगेगा और हर पहलू में तरक्की होगी। जो विवरण अपने अभिभाषण में गवर्नर साहब ने अपनी सरकार के संबंध में कल इस सदन के सामने पढ़ा उससे यह जाहिर होता है कि सरकार का ध्यान अपनी स्टेट की तरक्की के लिये बहुत लगा हुआ है। ध्यान ही नहीं लगा है बल्कि करने के लिए काफी प्रयत्न गील है। अगर मैं एक एक बात यहां पर रखूंगा तो काफी बातें दोहरायी जायेंगी लेकिन कुछ बातें जो उन्होंने नहीं कही हैं, उनके ऊपर मैं खास तौर से ध्यान दिलाना चाहूंगा। सब से पहले मैं एम्प्लायमेंट के विशय में अर्ज करना चाहता हूं। मैं जनता सरकार में भी रहा, उसके बाद भी रहा और आज कांग्रेस में हूं (गोर)

उपाध्यक्ष महोदय, एस0 एस0 एस0 बोर्ड द्वारा निकाली गई पोस्टें कितने दिनों से खाली पड़ी हुई थीं लेकिन किसी भी सरकार ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। हमारे नौजवान साथी सन् 1970 से ताक में बैठे थे कि हमें कब रोजगार मिले।

नौजवानों के मन में यह बात आ चुकी थी कि उनको रोजगार नहीं मिलेगा। लेकिन जब से हरियाणा में चौधरी भजन लाल जी की सरकार आयी है तब से कितने ही लोगों को रोजगार मिल चुका है। मैं अपने मुंह से क्या बताऊं यह तो सभी साथियों को भलिभान्ति मालूम है। चौधरी देवी लाल अपने वक्त में उन बेरोजगार लोगों को नहीं लगा सके लेकिन चौधरी भजन लाल की सरकार आन पर धड़ाधड़ लगा दिया गया। ये अपोजी इन के भाई भी महसूस कर रहे हैं कि यह फैक्ट है। जो हकीकत है वह हकीकत रहेगी। इन अपोजी इन के भाइयों के पचास पचास कैंडीडेटस की लिस्ट भेजी थी लेकिन चौधरी देवी लाल नहीं लगा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार के आने के पचात बैकवर्ड क्लासिज निगम बनायी गई और मेवात डिवैल्पमेंट बोर्ड बनाया गया। ये दोनों ही गरीबों की भलाई के लिये बनाये गए हैं। मेवात में जो लोग रहते हैं उनके बारे में किसी भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया लेकिन जब से यह मेवात बोर्ड बना है तब से उनकी हालत में काफी सुधार आया है, एक झलक आयी हुई है। उनका जीवन स्तर ऊंचा उठा है। वे बेचारे इसी बात पर उम्मीद लगा कर बैठे हुए थे कि हमारी उन्नति हो। आज बोर्ड बनने के पचात उम्मीद दिखाई दे रही है कि वे हरियाणा प्रदेश में एक अच्छी जीवन बसर कर पायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें दो राय नहीं है कि हमारी आर्थिक हालत इतनी नहीं सुधरी है जितनी सुधरनी चाहिए थी। हमारे पास साधन होंगे तो हमारी आर्थिक हालत सुधरेगी। जो हमारे साथी हाउस में हरा साफा बांध कर गन्ने का हरा गोला लेकर आते हैं, उसको हाउस में दिखाने से हालत नहीं सुधरेगी। मुझे अच्छी तरह से पता है जब यहां पर इनकी सरकार थी तो दो और अढ़ाई रूपए क्विंटल के हिसाब से गन्ना बिका था। हरा साफा बांध कर आने से और हरा गोला यहां पर दिखाने से किसानों के साथ हमदर्दी नहीं हो सकती। किसानों के साथ हमदर्दी तो उनको गन्ने का भाव देने से होगी। पहले हमारी सरकार ने गन्ने का भाव बीस रूपये क्विंटल रखा लेकिन मैंने यहां हाउस में कहा था कि बीस रूपये कम है इससे ज्यादा होना चाहिए यानि 23 रूपये होना चाहिए। चौधरी भजन लाल जी ने 23 रूपये क्विंटल दे दिया और आज के दिन अपाको पता है कि 26 रूपये का भाव कर दिया है। दूसरी ओर हमारे साथी चौधरी भले राम किसानों का भला करने के लिये हाउस में हरा साफा बांध कर और गन्ने का हरा गोला लेकर आते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि उनके दिल में किसानों के प्रति कोई तड़प नहीं है। उस टाइम की सरकार ने किसानों को गन्ने का भाव नहीं दिया लेकिन आज की सरकार ने दिया है। आज सरकार लोगों की तकलीफों को समझ रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्या बात कहूं यहां पर ये चीनी के भाव की बात भी उठा रहे है कि चीनी के भाव बढ़ गये है। जब आप किसानों का तीस रूपये भाव

से गन्ना ले रहे है तो दो रूपये किलो के भाव से चीनी कैसे मिलेगी? चौधरी हुक्म सिंह जी जब आप गन्ने का भाव तीस रूपये किंवटल मांग रहे है तो चीनी का भाव भी बढ़ाना पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं कि किसानों की दिक्कतें कैसे दूर हो सकती है। मैं किसानों का हमदर्द हूं। आप लोगों की तरह से हमदर्द नहीं हूं कि साफा बांध लो और हाउस में गोल लहरा दो। इस तरह से किसानों का भला नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे भाई इस बात को भी हाई लाइट नहीं करेंगे कि हरिजनों की बस्तियों में इस साल स्ट्रीट लाइट देंगे और इस बात को भी हाइ-लाइट नहीं करेंगे कि 31 मार्च 1981 तक पहाड़ी क्षेत्र एवं खादर के कुछ गांवों को छोड़ कर राज्य के सभी गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जायेगा। अपोजी इन के भाइयों को अपोजी इन के भाइयों को अपोजी इन का सही रोल अदा करना चाहिए। ये भाई कहते है कि अपोजी इन को मजबूत करो तभी सरकार ठीक चलेगी लेकिन असल बात तो यह है कि उनको भी तो अपना रोल सही रूप में अदा करना चाहिए। उनको यहां हाउस में सरकार की कमियों को बताना चाहिए। उनको अच्छे सुझाव देने चाहिए और अच्छी बातें बतानी चाहिए। मैं बाबू मूल चंद जी से उम्मीद करूंगा कि वे जरूर इन बातों को हाइ लाइट करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, हमने लोगों से वायदा किया है कि किसानों की चप्पा चप्पा भूमि को पानी दिया जाएगा इसके लिये सरकार नयी से नयी योजना बना रही है।

जब मेरे साथी चौधरी बीरेंद्र सिंह आई०पी०एम० हुआ करते थे, उस टाइम पर मैं उनके नोटिस में बार बार लाता रहा कि मंडियों के अन्दर जो किसान चारा लाते हैं उस पर म्यूनिसिपल कमेटियां टैक्स लगाती हैं जो नहीं लगना चाहिए लेकिन उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जब मैं चौधरी भजन लाल जी के नोटिस में यह बात लाया तो उन्होंने आर्डिनैस जारी करवा दिया कि चारे पर टैक्स नहीं लगेगा। इससे गरीब किसानों को काफी लाभ हुआ।

इसी प्रकार मेरे साथी चौधरी मेहर सिंह राठी ने हमारे हल्के में एक माइजर बनवा कर किसानों का बहुत भला किया है। लेकिन उस टाइम पर मेरे बार बार कहने पर भी उस माइजर की ओर गौर नहीं किया गया। इस माइजर का सरदार तारा सिंह जी ने सात फरवरी को उद्घाटन करके लोगों को नया जीवन दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं हाउस में एम० आई० टी० सी० के बारे में लगातार काल-अटैं इन मो इन और रैजोल्यू इन देता रहा लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब चौधरी भजन लाल जी की सरकार आयी इसने फैसला लिया कि अढ़ाई एकड़ वाले किसान से खाल बनाने का कोई पैसा नहीं लिया जायेगा और बाकी किसानों का पचास परसेंट माफ कर दिया। श्री बीरेंद्र सिंह जी इरीगे इन मिनिस्टर थे तो उन्होंने 33 परसेंट माफ करने के लिए कहा था लेकिन उन्होंने आर्डिनैस जारी नहीं किया। वैसे

इन्होंने मान लिया था कि 33 परसेंट माफ होना चाहिए लेकिन वह उनके दिल में और कागजात में ही रह गया। किसानों तक उसका लाभ नहीं पहुंच पाया।

मैं चौधरी शिव राम वर्मा जी को भी इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने गांवों में पंजुओं के लिये हस्पताल और डिस्पेंसरीज खोलने का प्रबंध किया है। आजकल एग्रीकलचर इतनी इकोनोमिकल नहीं है जितनी पंजुपालन है। आजकल गांवों में बहुत से लोग पंजुओं पर ही निर्भर हैं। जहां पहले बीस से ज्यादा हस्पताल नहीं खुल सके थे वहां आज हरियाणा में पिछले साल सौ खोलें और इस साल भी सौ खोलने जा रहे हैं। इनके खुलने से हमारे कितने ही नौजवान स्टाक अस्सिस्टेंट और वैटनरी कम्पाउन्डर बनेंगे। उन नौजवानों को नौकरी मिलेगी और किसानों का भला होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं ऐजुकेशन के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। जो पहले सिक कालेज थे उनको टेक ओवर ही नहीं किया बल्कि उन कालेजों को 1.4,80 से 75 प्रति सैट ग्रांट देनी शुरू कर दी है। उपाध्यक्ष महोदय, पहले यह सिस्टम था कि पिछले वर्ष की ग्रांट को इंकम में एड कर लिया जाता था तब टोटल डैफिसिट कैलकुलेट किया जाता था लेकिन चौधरी भजन लाल की सरदार ने उसको इंकम नहीं माना है और टोटल डैफिसिट की 75 प्रति सैट ग्रांट हर साल देते रहने को कहा है।

जो कालेजों में पढ़ा रहे है या जो मैजमेंट में है वे ही इस बारे में जान सकते है।

(12.00बजे)

उपाध्यक्ष महोदय, स्पोर्टस के बारे में भी हमारे स्पोर्टस मंत्री चौधरी जगन नाथ जी ने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि वे खुद स्पोर्टसमैन रहे है। इन्होंने अब खेलों की 33 स्कीमें चला रखी है। इस बारे में जो स्पोर्टस मैन है वे ही अच्छी तरह जान सकते है। जब से इनको यह महकमा मिला है तब से इसमें काफी सुधार इन्होंने किया है। इस महकमें को खेलों में सुधार के लिये पिछले साल 34 लाख रूपये दिये गये थे। खेलों के अन्दर और अधिक सुधार लाने के लिए इस साल 60 लाख रूपये खर्च करने की योजना बनाई गई है। आप स्वयं महसूस कर सकते है कि हमारी स्टेट ने स्पोर्टस के अंदर कितनी तरक्की की है?

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल जी कहीं पर दस बैड्ज का हस्पताल कहीं पर पच्चीस बैड्ज का हस्पताल और कहीं पर तीस बैड्ज का हस्पताल खाले रहे है जबकि इनके समय में कुछ नहीं हो पा रहा था। मेरे अपोजी इन के साथी यह तो कहने लग जाते है कि फलां फलां जगह पर हस्पताल नहीं खोला गया लेकिन यह नहीं बताएंगे कि कहां कहां पर हस्पताल खोल दिए गए है ओर कहां कहां पर और नए हस्पताल खोलने जा रहे है?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेहर सिंह राठी जी का तहदिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इन्होंने अपने समय में बहुत सी नई स्कीम खोली है। इस संबंध में मैं अच्छी तरह से अपने हल्के के बारे में जानता हूँ। जब मैं बाई इलैक्ट्रिकल में जीत कर आया तो चौधरी देवी लाल जी कहते थे कि मेरे को बनाने का श्रेय चौबीसी को जाता है। लेकिन जब वे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने चौबीसी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी कहा करते थे कि— (गोर) (घंटी)

चौधरी सतबीर सिंह मलिक: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। इन्होंने हल्के में यह कसम खाई थी कि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

चौधरी हरस्वरूप बूरा: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इनके साथ अच्छे काम करने के लिए कसम खाई थी न कि हमें साथ रहने के लिये। चौधरी चरण सिंह जी जब रोहतक में आये तो उनके जलसे में बारह हजार के करीब हाजरी थी। परन्तु जब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वायन की तो उस समय मेरे जलसे में करीब आठ हजार की हाजरी थी। इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों ने मेरा कांग्रेस पार्टी में भामिल होने का स्वागत किया क्योंकि यह लोगों की भलाई में था। मैं लोगों की भलाई के काम करने के पक्ष में हूँ न कि इनकी तरह चीकनी धोती बांधने में। (घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं टूरिज्म कार्पोरेट्स के बारे में भी थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगली दफा टूरिज्म कार्पोरेट्स इन नैट प्रॉफिट में आयेगा। उपाध्यक्ष महोदय, बस स्टैंडो पर 50 पैसे का एक चाय का कप मिलता है और वह भी एक प्रकार से जहर की तरह होता है। हम 60 पैसे के अन्दर चाय देते हैं। हमारी 60 पैसे की चाय के अन्दर दो कप बनते हैं (दो) आप वहाँ पर जा कर तो देखें कितनी अच्छी चाय देते हैं। चौधरी गंगा राम जी वहीं पर गए थे। इन्होंने मुझ से कहा कि आप गोहाना के अन्दर भी एक टूरिस्ट कम्प्लैक्स खोल दें। उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा न कहते हुए मैं इन्हीं भावों के साथ राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का पुरजोर समर्थन करता हूँ और अपने अपोजीट्स इन के साथियों से उम्मीद करता हूँ कि वे भी इस अभिभाषण का जरूर समर्थन करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित भावों में पेश किया जाए—

कि इस सत्र में इक्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस, अभिभाषण के लिये राज्यपाल महोदय, के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 9 मार्च, 1981 को सदन में देने की कृपा की है।

श्रीमती सुशमा स्वराज: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में एक सं तोधन का नोटिस दिया था। पहले वह सं तोधन मूव किया जाये। सं तोधन मूव होने के बाद ही बहस आगे सही ढंग से हो सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष: आपने सं तोधन का नोटिस बहुत लेट दिया है। वह अभी एग्जामिन नहीं हो पाया है।

श्रीमती सुशमा स्वराज: उपाध्यक्ष महोदय, जब श्री सुमेरचंद भट्ट जी बोल रहे थे, उस समय मैंने अपना सं तोधन दिया था। अगर वह सं तोधन रखा नहीं जायेगा तो धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे बहस कैसे हो सकेगी? आप स्वयं देख लें कि क्या सं तोधन मूव कराये बिना आप बहस जारी करवा पायेंगे? अगर करवाना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। (तोर)

Mr. Deputy Speaker: It was too late. It could not be considered.

Shrimati Sushma Swaraj: How can you say that it was too late\

रूल 21 में लिखा है:—

“Amendments may be moved to such motion of Thanks in such form as may be considered appropriate by the Speaker.”

श्री उपाध्यक्ष: आपको अपना संशोधन एक दिन पहले मूव करना चाहिए था। आपका नोटिस पहले नहीं आया, बाद में आया है।

श्रीमती सुशमा स्वराज: कल तो राज्यपाल महोदय बोल कर गए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको रूल 21 दिखाना चाहती हूँ। इसमें कहां पर लिखा है कि नोटिस एक दिन पहले आना चाहिए। मैंने रूल 21 के तहत अमेंडमेंट का नोटिस दिया है।
(गोर)

Mr. Deputy Speaker: It was too late.

श्रीमती सुशमा स्वराज: इस में कहां पर लिखा है कि एक दिन पहले दिया जाना चाहिए था या बाद में दिया जाना चाहिए था। कल तो राज्यपाल महोदय बोल कर गए हैं और धन्यवाद प्रस्ताव आज मूव हुआ है। धन्यवाद प्रस्ताव मूव हुए बगैर मैं किस विषय पर नोटिस दूँ। अब जब प्रस्ताव सदन में आ गया तो मैंने यह अपनी अमेंडमेंट दे दी है। मैं क्या कल्पना कर सकती थी कि राज्यपाल महोदय क्या बोल कर जाएंगे। मुझे क्या मालूम था कि धन्यवाद प्रस्ताव क्या है? आप कह रहे हैं कि it was too late.

श्री उपाध्यक्ष: आप जनरल रूल की तरफ ध्यान दे लीजिए मैं आपको बता देता हूँ।

Shri Baldev Tayal: Sir, I just want to draw your kind attention to Chapter V. The title of this Chapter is

Governor's Address and Communications between Governor and Assembly. The general rules do not apply to this Chapter. In this very Chapter under Rule 21, the procedure for moving the amendments has been laid down. Further more, the contention of Shrimati Sushma Swaraj is very correct when of Thanks has already been moved. you will be pleased to note that the motion of Thanks was moved today by Shri Sumer Chand Bhatt and only after moving that motion, an amendment can be moved. Otherwise, the amendment could not have been moved earlier, when there was no motion of Thanks. How can an amendment be there? You see when a thing is not in existence how can that thing be amended into another thing? So my humble submission before you is this that the amendment also be put before the House now.

श्री उपाध्यक्ष: ऐसे है कि बहिन जी ने आज 11.45 पर नोटिस दिया था। वह अभी एग्जामिन नहीं हो पाया है। एग्जामिन होने के बाद कंसिडर होगा और जो भी डिस्मिशन होगा वह बता दिया जायेगा। इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है।

Shri Baldev Tayal: Sir, what is there to consider about it, when there are specific rules? (Interruptions). Sir, again I want to draw your kind attention. You are a lawyer. You have been practising in law courts. You know there are some codified laws. There are some specific rules laod down in this book. The Speaker, Minister or the Members of this august House cannot go beyond these rules. It is not the discretion of the Speaker to allow or disallow where there are specific rules laid down in this book.

Mr. Deputy Speaker: I have not disallowed it. It is being considered.

Shri Baldev Tayal: Sir, may I know what is being considered? (Interruptions).

Mr. Deputy Speaker: The thing to be examined is whether the amendment which is to be moved by Smt. Sushma Swaraj is under the rules or not?

Shri Baldev Tayal: Sir, the House has laid down the rules. (Interruptions) We have quoted Rule 21. (Interruptions). Is there any ambiguity in the rules? (Interruptions.)

Mr. Deputy Speaker: You please read rule 22, which is as under-

“(1) Notwithstanding that a day has been allotted for discussion on the Governor’s Address other business of a formal character may, with the permission of the Speaker, be transacted on such day before the Assembly commences or continues discussion on the Address.

(2) The discussion on the Address may be postponed in favour of a Government Bill or other Government business on a motion being made that the discussion on the Address be adjourned to a subsequent day to be appointed by the Speaker.....”(Interruptions).

Shri Baldev Tayal: This does not apply to this. (Interruptions.) Sir, one thing more I have to submit, which also may be taken into consideration. You have often quoted

the book 'Practice and Procedure of Parliament' by Kaul and Shakhder, which specifically lays down- at page 173-

Amendment to the Motion of Thanks.

"Notices of amendment to the Motion of Thanks received after the President has delivered his Address but before a copy thereof is laid on the table, are treated as valid."

(Interruptions)

However, lists of amendments are circulated to members after the notice of the Motion of Thanks is received in the Secretariat.

श्री उपाध्यक्ष: कापी तो ले ही चुकी है (व्यवधान व भोर) अगर आप चाहती तो पहले ही अमेंडमेंट दे सकती थी।

श्रीमती सुशमा स्वराज: आप जरा इसको पढ़िये। सिचुए इन यह अराईज हो गयी थी कि मो इन आफ थैंक्स मूव नहीं हुआ था यह तो एक कांस्टीच्यू इनल प्वायंट है, इस पर झगड़ा नहीं होना चाहिए। अब सिचुए इन यह अराईज हो गयी मो इन आफ थैंक्स मूव करने से पहले और कापी ले डाउन होने के बाद अगर अमेंडमेंट दी जाए क्या वह वैलिड है या नहीं है। इस बात पर आपकी रूलिंग चाहिए। जनरल प्रोसिजर तो यह है कि मो इन आफ थैंक्स मूव होने के बाद ही नोटिस आफ अमेंडमेंट आना चाहिए। वह तो वैलिड है ही। लेकिन हमने जो नोटिस आफ अमेंडमेंट, मो इन आफ थैंक्स मूव होने के तुरन्त बाद दे दिया था, उसे भी यह कहा गया कि it is too late. डिप्टी

स्पीकर साहब, आप इस रूल की बाद की लाइनों को पढ़िये अगर नोटिस आफ अमेंडमेंट मो इन मूव होने से पहले दिया जाता है तो वह भी वैलिड है। उसकी भी कापियां मो इन आफ थैंक्स मूव होने के बाद ही सरकुलेट की जायेगी। जैसे मैंने पहले कहा कि जनरल प्रोसीजर तो यह है कि मो इन आफ थैंक्स मूव होने के बाद अमेंडमेंट दी जायेगीर लेकिन अगर कहीं पर ऐस सिचुए इन अराईज हो जाये कि मो इन आफ थैंक्स मूव न हुआ हो और कापी अभी ले डाऊन न हुई हो, फिर भी अमेंडमेंट दे दी जाये तो वह भी वैलिड होगी। मैंने तो जनरल प्रोसीजर आपको बता दिया है। यह जो आपने पढ़ा है, यह इसलिये यहां पर लागू नहीं होता वैसे भी इसकी इंटें इन स्पैसिफाई होनी चाहिए कि अमेंडमेंट की कापियां भी मो इन आफ थैंक्स मूव होने के बाद ही सरकुलेट की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष: आप पहले सारे पेज को पढ़ लें।

श्रीमती सुशमा स्वराज: मैं आपको सारा पेज पढ़ने के बाद ही बता रही हूं। देखिए दो मत है। वह वैलिड है। इसमें इंटरप्रेटै इन की बात है वैसे वह भी वैलिड है। और यह भी वैलिड है। This is a minor distinction. This is not only the thing that that is valid but that is also valid. This is the only distinction.

श्री मूल चंद जैन: डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक मेरी समझ में आया है वह यह है कि अमेंडमेंट का नोटिस किस स्टेज

पर दिया जा सकता है? यह नोटिस तो इस स्टेज पर भी दे सकते हैं लेकिन जो असली प्वायंट है वह यह है कि आया आपको और आपके स्टाफ को उसे एग्जामिन कर रहे हैं। लेकिन यह तमाम एग्जामिन नहीं हो सकता। (गौर एवं व्यवधान) प्वायंट यह है कि आपके आफिस और आपको अधिकार है या नहीं? (व्यवधान) अगर कोई ऐसा मोशन हो जिस पर एग्जामिन करने की कोई बात हो, तो आप यह फैसला दे सकते हैं कि एग्जामिन करने के बाद फैसला दूंगा। इसमें भी मेरी राय यही है और आपको कहना भी यह चाहिए कि ज्यों ही एग्जामिन हो जायेगा वैसे ही इनको अपना मोशन मूव करने का अधिकार होगा।

वित्त मंत्री(चौधरी खुरशुद अहमद): बहिन जी, आप रूल 21 को जरा गौर से पढ़ें। (विघ्न) वह आगे पढ़ना नहीं चाहती। डिप्टी स्पीकर साहब, जिस रूल 21 के तहत इन्होंने अपनी अमेंडमेंट दी है, उसी के तहत यह दिया हुआ है कि आपको और आपके आफिस को यह अख्तियार है कि वह इसको देखे कि whether it is proper or not. लेकिन यह नहीं कि motion is given and ifso facto it is taken as in order. So the only thing what the rule requires is that the amendments may be moved to such motion of Thanks in such forms as may be considered appropriate by the Speaker. So whether it is appropriate or not is to be examined by the Vidhan Sabha Secretariat which as stated by the Chair is being done and, therefore, there can not be any objection to it. There is no point in insisting that

it must be decided before the discussion takes place.
(Interruptions).

श्रीमती सुशमा स्वराज: डिप्टी स्पीकर साहब, यह मामला तो बिना वजह ही उलझ रहा है। जो कुछ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर साहब ने कहा है वह बिल्कुल सही है।

श्री उपाध्यक्ष: एग्जामिन होने के बाद अगर अमेंडमेंट एडमिट हो जाती है तो आपको अपचुर्निटी मिलेगी

Shri Mool Chand Jain: If she will be given an opportunity, then the matter ends.

श्री उपाध्यक्ष: मैंने उनको बता दिया है कि अगर एग्जामिन होने के बाद एडमिट हुआ तो उनको टाईम मिलेगा।

श्रीमती सुशमा स्वराज: आप इसको टू लेट की बिना पर रिजैक्ट तो नहीं कर रहे हैं? (तोर एवं व्यवधान)

Mr. Deputy Speaker: No, no. It is not being rejected on that basis. (Interruptions).

Shri Baldev Tayal: Sir, may I again draw your kind attention to page 174 of the book 'Practice and Procedure of Parliament' by Kaul and Shakhder-

“This discussion on the Motion is initiated by the proposer of the Motion, who is followed by the seconder. The member who have tabled amendments are then asked to indicate their intention to move the amendments standing in their names and such of the amendments as are selected by

the members are taken as moved and an announcement to that effect is made by the Speaker. Besides, there is no bar to the Speaker permitting a member to move an amendment at a later stage.....

These are the only two situations. So what the Parliamentary Affairs Minister is saying is imaginary and in his mind only. It is not mentioned in this authoritative book, Sir.

Mr. Deputy Speaker: I have stated that if the amendment is admitted after examination, an opportunity will be given to the hon. Member. मैंने बहिन जी को कह दिया है कि उनको टाईम मिलेगा।

श्री बलदेव तायल: धन्यवाद, सर।

श्री मूल चंद जैन(सम्भालखां): डिप्टी स्पीकर साहब, गवर्नर साहब का भुक्तिया अदा करने के लिये जो मोान मूव हुआ है, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। डिप्टी स्पीकर साहब, ऐसा मालूम होता है कि रूलिंग पार्टी और हम दो दुनियाओं में रहते हैं। हमारी दुनिया अलग है और उनकी दुनिया अलग है। स्टेट में जो कुछ हो रहा है मुझे आता थी कि गवर्नर ऐड्रेस में उसका कुछ तो रिफ्लैक्टान अवय होगा लेकिन ऐसा उसमें नहीं है अभी बारह फरवरी को भिवानी में लाखों आदमियों ने डिमोंसट्रेशन किया था। यहां पर दो मंत्री भिवानी के बैठे हुए हैं। अखबार के रिप्रैजेंटेटिव्स ने उनसे पूछा कि भिवानी में आग लगी हुई है वहां पर आप क्यों नहीं जा रहे हैं? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी गुजारि । है कि ये लोग सुनने की कोर्ि । । करें ।

परिवहन मंत्री(श्री जगन नाथ): आप ऐसा कैसे कहते है कि 12 तारीख को मैं वहां नहीं था?

श्री मूल चंद जैन: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि प्रैस वालों ने इनसे पूछा और जो कुछ जवाब प्रैस में आया वह मैं आपको बताना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि क्या आप हमको पिटवाना चाहते है लेकिन आज तक मिनिस्टर महोदय ने इसको तरदीद नहीं किया है। मैं अब तक यह समझ रहा था कि डैमोक्रेसी में अपोजी ान और रूलिंग पार्टी में बहुत फर्क नहीं होता है। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) स्पीकर साहब, मैं अपने दोस्त श्री सुमेर चंद का आभारी हूं कि उन्होंने मेरी प्र ांसा की। चौधरी हरस्वरूप बूरा ने भी प्र ांसा की और अपील की कि अपोजी ान भी स्टेट में जो निर्माण का काम हो रहा है उसमें सहयोग दे।

स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब को मैं बराबर चिट्ठी लिखता रहता हूं और मुझे ताज्जुब है और मैं हाउस के नोटिस में भी यह बात लाना चाहता हूं कि मेरी चिट्ठी का कभी दो महीने में और कभी तीन महीने में जवाब आता है। हमारी स्टेट में मुखतलिफ कमेटीज गवर्नमेंट लैवल पर बनी रही है। मैं उन कमेटीज की लिस्ट दे सकता हूं जो गवर्नमेंट

लैवल पर बनी है लेकिन उन कमेटीज में अपोजी इन के मैम्बरज को नहीं रखा गया हैं। मैंने चीफ मिनिस्टर को लिखा।

श्री अध्यक्ष: आप कौन सी कमेटीज का जिक कर रहे है?

श्री मूल चंद जैन: स्पीकर साहब, मैं हाउस की कमेटीज का जिक कर रहा हूँ। चूंकि इन्होंने अपील की थी इसलिये मेरा फर्ज था कि मैं अपील को रिस्पोंड करूँ। स्पीकर साहब, एक पहली चिट्ठी मैंने चीफ मिनिस्टर को लिखी उसमें लिखा कि आप गवर्नमेंट की कमेटीज बना रहे है आप उसमें केवल कांग्रेस के आदमी ले रहे है कुछ हमारे आदमियों को भी लें। आप ऐसा क्यों समझते है कि सारी अक्ल कांग्रेसियों में ही है। स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर का जवाब आया कि आइंदा इसका ख्याल रखेंगे मैंने इनको फिर चिट्ठी लिखी कि आप पिछली गलती को भी दुरुस्त करो। स्पीकर साहब, इन्होंने पिछली गलती दुरुस्त क्या करनी थी, उस चिट्ठी के बाद भी गवर्नमेंट ने और कमेटी बनाई उसमें भी अपोजी इन के आदमी नहीं लिए। मैं कहना चाहता हूँ कि आइंदा अगर आप हमारी कोआप्रे इन चाहते है तो इस तरह की चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कल स्पीकर साहब ने बहुत ही भानदार अपील की थी। उसके कुछ हिस्सों से चाहे हम मतभेद रखते हों, लेकिन उन्होंने यह कहा था कि हाउस की डिगनिटी को बनाए रखने में एक नई मिसाल कायम करनी चाहिए। स्पीकर साहब, हम अपोजी इन के आदमी सहयोग देना

चाहते हैं। मगर सरकार के काम जिस तरीके से चल रहे हैं और उन का जो नक़्शा मैंने पेश किया है। उससे पता लगता है कि वह सहयोग नहीं लेना चाहते हैं। इस प्रस्ताव को पढ़ कर पता लगता है कि हमारी स्टेट की जो समस्या है, स्पीकर साहब, हमारी स्टेट की ही समस्या नहीं बल्कि हमारे राष्ट्र की जो समस्या है उसके बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं है। स्पीकर साहब, आज जो हमारे जवान लड़के और लड़कियां हैं क्या वे सिनकी नहीं बन रहे हैं? हमारी सरकार उनके सिनकपन को हटाने के लिए क्या कर रही है? स्कूल कालेजों में नैतिक शिक्षा क्यों नहीं दी जाती? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब भी हम ऐसा प्वायंट उठाते हैं तो चीफ़ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि आप भी तो दो साल मिनिस्टर रहे हैं, आप भी तो छः महीने मिनिस्टर रहे हैं। यह एक गैरजिम्मेदाराना बात है। मैं मानता हूँ कि यह समस्या उस समय भी थी और आज भी है। मैंने पिछले सत्र में भी यह बात कही थी कि यह राष्ट्र की एक गम्भीर समस्या है और इसको अवश्य हल करना चाहिए। स्पीकर साहब मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के पास ही केवल टैलेंट नहीं है बल्कि और लोगों के पास भी टैलेंट है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने तो अपनी कांग्रेस के टैलेंट का भी फायदा नहीं उठाया। अगर आप सारे देश के टैलेंट का फायदा उठा कर भी देश की सभी समस्याएं सुलझा सकें तो भी देश आपका बहुत भुक्तगुजार होगा और आइंदा आने वाली पीढ़ियां आपकी बहुत एहसानमंद होगी।

स्पीकर साहब, पीछे भी मैंने जिक्र किया था कि हमें अपने स्कूलों और कालेजों में मौरल ऐजुकेशन, नैतिक शिक्षा इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। क्या इस एड्रेस में मौरल ऐजुकेशन का कोई जिक्र है? स्पीकर साहब, अढ़ाई वर्ष जनता पार्टी का भासन रहा, मैंने मौरल ऐजुकेशन का प्रश्न उस समय भी उठाया। जून 1979 से जनता पार्टी के नाम से और फिर जनवरी 1980 से कांग्रेस पार्टी के नाम से आप स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटर बन चला रहे हैं। मैंने रिपिटिडली इस प्रश्न को उठाया और उसका जवाब दिया गया कि कमेटी बनाई गई है। जो कैरिकुलम तैयार करेगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। स्पीकर साहब, जनता पार्टी के जमाने से बालिंग तालीम का प्रोग्राम चला आ रहा है लेकिन इस एड्रेस में कहीं भी एडल्ट ऐजुकेशन का कोई जिक्र नहीं है। अगर कहीं हो तो मुझे बताइए। स्पीकर साहब, आज देश में चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक सब यह कह रहे हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली खराब है। हमारी शिक्षा बेरोजगार पैदा करने की एक मशीन है। मैं पूछना चाहता हूँ कि उस बेरोजगार पैदा करने की मशीन को दुरुस्त करने के लिए आपकी सरकार ने क्या किया, आपकी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? क्या मैं इस तरह के एड्रेस का भुक्तिया अदा करूँ? यह कोई अंग्रेज का राज्य तो है नहीं। वे ऐसा करते थे कि देहात में सुधार के नाम पर किसी जगह कुरड़ी को ठीक कर दिया या छोटा मोटा और काम कर दिया। आपने तो समस्याओं से झूझना है। क्या इस एड्रेस में इस बात का जिक्र है कि किस तरह से आप इन समस्याओं से झूझेंगे? स्पीकर

साहब, कहीं भी जिक्र नहीं है कि जो समस्याएं हमारी स्टेट में है, उनको इस तरह से हल करेंगे। बूरा साहब जब बोल रहे थे तो उन्होंने आंकड़ों पे आंकिए कि फलां मद पर पिछले साल पांच करोड़ रूपया खर्च किया अगले वर्ष छः करोड़ रूपया खर्च किया और उससे अगले साल पहले से ज्यादा खर्च करेंगे। वे इस तरह से बात रहे थे जैसे बड़ा भारी मोर्चा मार लिया हो। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इतनी तो कीमते बढ़ रही है और ये कह रहे हैं कि पांच करोड़ रूपये से छः करोड़ रूपये खर्च कर दिया और फिर छः करोड़ रूपया से अधिक खर्च करेंगे। स्पीकर साहब, इसका मतलब यह है कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जो ज्यादा खर्च कर रहे हैं वह कीमते बढ़ने के कारण है। इस तरीके से सोचना गलत है। बेरोजगारों के लिये आपने क्या किया? मैं कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी की समस्या तब तक हल नहीं हो सकती जब तक कि आप गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर अमल नहीं करेंगे। उन्होंने इस देश को एक रास्ता दिया था और कहा था कि बड़े-बड़े कारखानों पर पाबंदी लगाओ। जो चीजें घरों में हमारी मां बहनें बना सकती हैं और जिन चीजों को गांवों में छोटी छोटी मशीनों से बनाया जा सकता है, उन चीजों के लिये बड़े बड़े कारखानों पर पाबंदी लगानी चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस है कि इस दिशा में आज तक इस सरकार ने कुछ नहीं किया। आप कहते हैं कि मार्किटिंग का इंतजाम करेंगे। रूरल इंडस्ट्रीज का मामला तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक मार्किटिंग का इंतजाम नहीं करेंगे। (व्यवधान) गांधी जी के नाम

पर कांग्रेसी वोट लेते रहे। क्या कोई मैम्बर या चीफ मिनिस्टर खड़े होकर यह कह सकता है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। अध्यक्ष महोदय उन्होंने कहा था कि बड़े बड़े कारखानों पर पाबंदी लगेगी तो छोटे उद्योगों को माल की मार्किटिंग आप ही हो जाएगी। स्पीकर साहब, कोई भी मुझे हाउस में कहे कि मैं गांधी जी को गलत कोट कर रहा हूँ। जब तक सरकार गांधी जी के असूलों पर नहीं चलेगी, अपनी नीति को नहीं बदलेगी तब तक यह देना आगे नहीं चल पाएगा और देना की भलाई नहीं हो सकेगी। स्पीकर साहब, मैंने कांग्रेस वालों का मैनीफैस्टों पढ़ा है कि नहीं। उसमें लिखा है कि विरोधी पक्ष इस नीति से प्रिमिटिविजम लाएंगे और प्रीमेटिव सोसायटी बनायेंगे। स्पीकर साहब, आज देना एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है कि हम अकेली खेती बाड़ी पर निर्भर करके गुजारा नहीं कर सकते। आज अगर किसी किसान के पास दस किल्ले जमीन है तो वह आज तो गुजारा कर सकता है लेकिन कल को जब उसका परिवार बढ़ेगा तो एक आदमी के हिस्से एक-दो किल्ला ही आएगा। इसलिये सरकार को चाहिए कि वह देहातों में स्माल स्केल इंडस्ट्रीज लगाए ताकि लोगों का रूझान उस तरफ हो सके। सरकार छोटी छोटी मीनरी देहातों में लगाए जिस तरीके से जापान में काम हो रहा है। हम गरीबों को तभी ऊपर उठा सकेंगे वरना मुझे और कोई रास्ता गरीबी दूर करने का दिखाई नहीं देता है। गवर्नर साहब के ऐड्रेस में इस किस्म का कोई इंगारा नहीं मिलता है कि सरकार ने गरीब लोगों की मदद करने के लिये कोई उपाय किये हैं। अभी सुमेर चंद जी

भट्ट बड़े उछल उछल कर यह कह रहे थे कि कि हो सकता है कि सचमुच में ही कुद काम हुए होंगे इन्होंने आगे कहा कि पहले तो हरिजनों को छन छन कर (परकुलेटर होकर) फायदा मिलता था। अब तो हमने डायरेक्ट फायदा दिया है। स्पीकर साहब, जो फायदे इन्होंने दिये हैं, वे मैं इनको गिना देता हूँ कि इन्होंने हरिजनों को क्या क्या दिया है? गवर्नर साहब ने अपने ऐड्रेस में बताया कि वर्ष 1981-82 के लिये 290-00 करोड़ रुपये की अन्तिम योजना स्वीकृत की गयी है। आगे चलकर गवर्नर साहब ने अपने ऐड्रेस में लिखा है कि कुल योजना परिव्यय का लगभग 12.26 परसेंट यानी 34 करोड़ रुपया गरीब हरिजनों की भलाई के लिये नियत करने का प्रस्ताव है ताकि 50,000 और परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत लाया जा सके। देहाती विकास के अनेक कार्यक्रमों के अन्तर्गत खर्च किये जाने वाले धन का लगभग 66 परसेंट अनुसूचित जातियों के लाभ के लिए होगा। यानि 34 करोड़ रुपया हरिजनों की भलाई के लिये खर्च होगा। स्पीकर साहब, आप को पता है कि आज 80 परसेंट आबादी देहातों में है अगर आप सारा हिसाब लगाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि 290 करोड़ रुपये की योजना में से केवल 52-53 करोड़ रुपया ही देहातों की भलाई के लिये रखा गया है और 2.00 करोड़ रुपये की प्राधिकृत पूंजी से हरियाणा पिछड़े वर्ग कल्याण निगम स्थापित किया गया है। यह निगम राज्य के विभिन्न जिलों में क्षेत्रिय कार्यालय स्थापित करेगा अभी तक इस निगम ने एक भी पिछड़े वर्ग की सहायता नहीं की है। हरिजन कल्याण निगम के द्वारा

5000 आदमियों को कर्जा साल में दिया जायेगा। मैंने पिछले सै ान में भी इस बारे में कहा था कि इस निगम द्वारा जिस हिसाब से हरिजनों को कर्जा दिया जा रहा है अगर इसी रफतार से कर्जा दिया जाता रहा तो जो चार लाख के करीब, हमारे प्रान्त में हरिजन परिवार है, उनको कर्जा देने में कम से कम 800 वर्ष का समय लगेगा।

इसके साथ साथ गवर्नर साहब ने अपने ऐड्रेस में बताया है कि 1978-79 के आंकड़ों के अनुसार गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लगभग 3.21 लाख परिवार अनुसूचित जातियों में है, जिनको हम गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिये विशेष योजनाएं चला रहे हैं। अगर इसी तरह से रफतार चलती रही तो एक लाख परिवारों को बीस सालों में और तीन लाख परिवारों को साठ सालों से ऊपर उठा सकेंगे। फिर भी यह सरकार गरीबों के लिये, गरीब हरिजनों के लिये मगरमच्छ के आंसू बहाती है। पिछले सै ान में भी गवर्नर साहब ने कहा था कि हरिजन चौपालों के लिये हमने एक करोड़ रूपया रखा है लेकिन बजट में केवल 25 लाख ही आया। मैंने उस वक्त भी प्वायंट आउट किया था कि यह इस तरह की डिस्किमेंसी का क्या कारण है, यह डिस्किमेंसी किस तरह से साल्व होगी। उस वक्त लाला बलवंत राय तायल जी वित्त मंत्री थे उन्होंने कहा कि आप हरिजन चौपालों के लिये जितना रूपया मांगोगे हम देंगे। स्पीकर साहब, हुआ क्या? जो 25 लाख रूपया इस काम के लिये रखा गया था उसमे से भी बीस

लाख रूपया सरण्डर होगा (ेम भोम की आवाजें) स्पीकर साहब, मैं वैंलेंज के साथ कहता हूं कि जब चौधरी देवी लाल जी की सरकार थी, उस वक्त इस तरफ खास ध्यान नहीं दिया गया था और हमारी सरकार ने जिलों की एउमिनिसट्रेटिव म िनरीज को यह खास हिदायतें दी थी कि आप मैचिंग ग्रांटस के लिये पंचायतों में जाएं बी0डी0ओज0, तहसीलदारों और एस0डी0एमज0 को इस बारे में हिदायतें दी गयी थी कि आप मैचिंग ग्रांटस के लिये रूपया जमा कराओं और यह जो पैसा सरकार ने हरिजनों की चौपालों के लिये रखा है, इसको खर्च करो। लेकिन इस सरकार ने हमारे मुकाबले में एक उंगली भर भी काम नहीं किया। उसका नतीजा क्या होगा कि हरिजन चौपालों के लिये मुि कल से 25 लाख में से केवल 2-4 लाख रूपया ही खर्च होगा। स्पीकर साहब, हो सकता है कि मेरे इस भाशण के बाद सरकार कोई कदम उठा लें, वरना यह सरकार इस बारे में कोई कदम उठाने की इच्छुक नहीं रही है। मैं आपको बताता हूं कि 22 लाख रूपया अभी भी जिलों में डी0सीज0 के पास यूं का यूं पड़ा हुआ है, जिसका हरिजन भाइयों को कोई लाभ नहीं होगा।

इस के साथ साथ स्पीकर साहब मैं आपको बताता हूं कि आज से आठ महीने पहले जब गंदम किसान के खलिहानों से बाहर आ गयी, उस वक्त उस गंदम का भाव 100, 102, 110 तक ही रही। स्पीकर साहब, आप देखें कि आज किस को गंदम की जरूरत नहीं है। कोई बड़ा आदमी है, कोई बड़ा किसान है,

उसको जरूरत न होगी मगर मार्जिनल किसान या हरिजन और पिछड़े वर्ग, सब को गंदम की आव यकता है। इस सरकार ने हरिजनों और मार्जिनल फारमर्ज को सस्ती गंदम सप्लाई करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया। पिछले दिनों इस बात का कहीं जिक्र आया था कि सरकार आटा क्यों नहीं दे पायी। हमारे एक साथी ने कहा था जिनका मैं यहां पर नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। उन्होंने कहा था कि सरकार इस लिय आटर नहीं दे पायी क्योंकि बिजली इंजीनियर्ज ने हड़ताल कर दी। हम तो स्पीकर साहब, यह कहते हैं कि गरीब हरिजन के तो घर घर में चक्की है, तुम गंदम दो गंदम मार्केट में तो आनी चाहिए, वे लोग तो अपनी अपनी चक्की पर ही अपने घरों में गंदम को पीस सकते हैं जैसाकि उनकी मां बहनें पहले कर रही हैं। एक तरफ तो ये उन गरीबों से महात्मा गांधी के नाम पर वोट मांगते हैं और दूसरी तरफ उनका भाषण कर रहे हैं। क्या इनके पास इस बात का कोई जवाब है? स्पीकर साहब, मैं देहातों में जाने आने का काफी आदि हूं। जब मैं देहातों में जाता हूं तो वहां के लोग मुझ से पूछते हैं कि जैन साहब हमें इन बातों का जवाब दो कि वह गंदम जो आज से आठ महीने पहले किसानों के घरों से 100 से लेकर 117 रूपये पर क्विंटल के हिसाब से उठाई गयी थी, सरकारी गोदामों के अन्दर जाने के बाद उसी गंदम का भाव अब 180, 190, 200 व 220 कैसे हो गया? वे लोग मेरे से इस सवाल का जवाब पूछते हैं। स्पीकर साहब, ऐड्रेस में इस बात का क्लेम किया गया है कि हमने पांच हजार दुकानें खोल दी। स्पीकर

साहब, उनमें क्या हो रहा है? वे इनके कपड़ान के अड्डे है इनके सिवल सप्लाय के कर्मचारी लाखोंपति बन गए तथा उनमें से तो कुछ पौलिटीरियंज भी बन गये है। आज गांव वालों को सीमेंट नहीं मिलता है, मिट्टी का तेल नहीं मिलता है और कंट्रोल्ड क्लोथ नहीं मिलता है। मैं खुरीद भाई से पूछना चाहता हूं कि जो कंट्रोल्ड क्लोथ गवर्नमेंट आफ इंडिया से आता है, वह कहां गया? उस कपड़े की धोती की कीमत 12-13 रुपये है लेकिन आप किसी देहती भाई से पूछो कि क्या किसी को वह धोती मिली है? वह सारा कपड़ा ब्लैक में बिकता है। आपको सीमेंट और मिट्टी का तेल जितना भी चाहिए वह ब्लैक मार्केट में तो मिल सकता है लेकिन कंट्रोल प्राइस पर नहीं मिलेगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कहां है तुम्हारी मीनरी? (विघ्न) स्पीकर साहब, मैं इस नुक्ताचीनी के द्वारा इस सरकार से अपील करता हूं कि अभी इन गरीब भाइयों को एक महीने की और दिक्कत हैं। इन गरीब भाइयों के लिये और जिस वीकर सैकड़ान के लिये आपने इस ऐड्रैस में मगरमच्छ के आंसू बहाने की कोशिश की है, आप उनके लिये कम से कम इतना तो कर दें कि उनको गेहूं सस्ते दाम पर मिल जाए। चीफ मिनिस्टर साहब जब जवाब देंगे तो कहे कि हमने देहातों में गेहूं पहुंचा दिया है। अगली बात मेरी यह है कि इस स्टेट में इतनी कपड़ान है लेकिन इस अभिभाषण में उसका बिल्कुल जिक्र नहीं है। आज ही एक सवाल हाउस में आया था कि 11 करोड़ रुपये बिकी कर कर बकाया है। चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया कि साढ़े चार करोड़

रूपये के बारे में तो कोर्ट से स्टे मिल गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि बाकी के साढ़े छः करोड़ रूपये को रिकवर करने के लिये आपने क्या किया? दूसरी तरफ आप देखें हांसी के एक गरीब किसान ने गोबर गैस प्लांट के लिये तीन हजार रूपये का कर्जा लिया था। उसके पास उस कर्जे को वापिस करने का कोई साधन नहीं था जिस वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया तीन दिन तक वह हवालात में रहा और बाद में वह मर गया। पता नहीं उसको मारा गया हे या भूख की वजह से उसने खुदक मी कर ली। अगर उसने खुदक मी भी की तो उसे ऐसा करने के लिये मजबूर किया गया। (भोम भोम की आवाजें) स्पीकर साहब, आपको याद होगा कि ये गोबर गैस प्लांट जबरन लोगों पर थोपे गये थे। किसी अमरी आदमी का बिजनैस चलाने के लिये लोगों पर ये जबरन थोपें गए थे और ऊपर से अब ऐसा हो रहा है। आज हालत यह है कि सारी संस्थाओं को डि-ग्रेड कर दिया गया है। मुझे एक आध बार किसी काम के लिये चीफ मिनिस्टर साहब के आफिस में जाना पड़ा। मैंने वहां देखा कि रोजगार लेने वालों की लाईन लगी हुई थी। मैं जानना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर के आफिस का रोजगार दिलाने से क्या संबंध है? ये इस बात को एनक्वेजमेंट क्यों दे रहे हैं? यह हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने हिदायत दे रखी हो कि अगर हमारा कोई आदमी आए तो फलां आदमी को टेलीफोन कर दो। इसके बाद स्पीकर साहब, ट्रांसफर्ज की हालत यह है कि किसी भी अफसर को एक जगह टिकने नहीं दिया जाता है। स्पीकर साहब, अभी 16 फरवरी को

कांग्रेस की किसान रैली हुई। आपको पता है कि उसमें किस तरीके से सरकारी मीनरी का दुरुपयोग किया गया और किस तरह से पुलिस कर्मचारियों, तहसीलदारों और पटवारियों की डियूटी लगाई कि वे गांवों में जाकर लोगों को रैली में भेजें। इसके अलावा गवर्नमेंट ने फैक्ट्री ओनर्स को हिदायत कर दी कि फैक्ट्रीज बंद कर दो। फरीदाबाद और सोनीपत की फैक्ट्रीज वालों को कहा गया कि तुमने अपनी फैक्ट्री बंद करनी है। जो इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का प्रधान है उसने एक सर्कुलर जारी किया कि तमाम फैक्ट्रीज बंद करनी है। उनके जो ट्रक या दूसरे व्हीकल्स थे वे रैली में पहुंचाए गए। मैं चाहूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब इस बात का जवाब दें कि क्या 16 फरवरी को हरियाणा में जहां पंजाब से भी काफी ट्रक आते जाते हैं, उस दिन किसी एक भी ट्रक को प्राइवेट सामान ले जाने की इजाजत हुई? इसके बाद स्पीकर साहब, एक बात मैं ला एंड आर्डर के बारे में कहना चाहता हूं। अभी हरियाणा में जी0टी0 रोड पर मूर्थल के नजदीक कारों में जा रहे अलग अलग दो परिवारों को लूटा गया। मेरी कांस्टीच्युएंसी के गांव रिसपुर और लनहेड़ा में डाका पड़ा। फरीदाबाद में जो फायरिंग हुई वह भी इसी गवर्नमेंट के जमाने में हुई। होडल में हरिजन को कैसे मारा गया। थानों में हवालात में कितने आदमी मारे गये। गोहाना की एक लड़की के साथ रेप करके कत्ल किया गया। मैं एक और आचर्य की बात बताना चाहता हूं। ये मेरी कांस्टीच्युएंसी का ही मामला है और इस बारे में मैं पुलिस वालों को भी लिख चुका हूं। मैं अभी पिछले दिनों

उझा गांव में गया था। श्री हरि सिंह नलवा जो राज्य सभा के मैम्बर है वे भी इसी गांव के रहने वाले हैं। उनके बारे में वहां पर लोगों ने जो बातें मुझे बताईं वे सुन कर मैं हैरान रह गया। अभी अभी मैं बापौली गांव में भी गया था और वहां 25 फरवरी को चीफ मिनिस्टर साहब भी गये थे। वहां पर संजय गांधी के नाम से एक पार्क बन रहा था। जिस दिन चीफ मिनिस्टर साहब उस गांव में गये थे उसी रात को एक हरिजन के प्लाट पर नाजायज कब्जा कर लिया गया। जब उसने इस बात का एतराज किया तो उसके लड़कें की पत्नी को पीटा गया। वह बेचारा गांव का आदमी यह कहता है जि जब हम थाने में जाते हैं तो वहां से जवाब मिलता है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह तो नलवा का इलाका है। तो क्या इसको ला एंड आर्डर की अच्छी सिचुए इन कहेंगे? इसके बाद स्पीकर साहब, जहां तक प्रोहिब इन की बात है, भाराब के दरिया बहा दिये गांधी की दुहाई देने वाले मेरे भोरों ने। जहां तक पंचायती राज का सवाल है यह सरकार जिला परिशद नहीं बनाना चाहती। पिछले बजट सै इन में इस बारे में दो मंत्रियों ने ए योरेंस दी थी। उनमें से एक मंत्री राव राम नारायण ता चले गये। ठाकुर बीर सिंह बैठे हैं। पिछले साल इन्होंने मुझे ताना मारा था कि जैन साहब तो क्रेडिट लेना चाहते हैं। ये कहने लगे हम सब कुछ करेंगे जैन साहब जो चहाते हैं इससे भी आगे जाने का हमारा बिल तैया है। वह बिल इनका बिल में बड़ गया। स्पीकर साहब, यह सब कुछ मुझे

अफसोस के साथ कहना पड़ता है और मेरा दिल दुख से भरा हुआ है.....

मुख्य मंत्री(चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, जैन साहब, अब जो मर्जी कह लें लेकिन इनमें बाद में सुनने की भावित होनी चाहिए, ये फिर भाग कर बाहर न जाएं।

श्री मूल चंद जैन: स्पीकर साहब, मुझे पहले कुछ ख्याल था कि यह सरकार देहातों की भलाई करेगी क्योंकि मैं समझता था कि ये भी हमारी तरह देहातों से आयें है और देहातों का ख्याल करेंगे। लेकिन अब मैं कंविसड हूं कि यह एंटी रूरल पीपल सरकार है क्योंकि यह देहात के लोगों पर भरोसा नहीं करती। अगर देहात के लोगों पर भरोसा करती है तो सता का विकेंद्रीकरण यानी डी सैंट्रलाइजे इन आफ पावर करती। सता के विकेंद्रीकरण पर अगर वि वास रखते है तो जिला परिशद बनाओ जिला परिशदें महाराष्ट्र में कायम है और भी कई स्टेटस में कायम है। हमने कल गवर्नर ऐड्रैस के समय वाक आउट किया लेनिक उधर के हमारे दोस्तों ने उसका गिला किया इस ऐड्रैस को पढ़ने के बाद मैं समझता हूं कि अगर हम वाक आउट न करते तो हम अपने फर्ज से कोताही करते। इसलिये इस प्रस्ताव की मैं सख्त से सख्त मुखालफत करता हूं और इन भाब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं।

श्रीमती डा० कमला वर्मा (यमुनानगर): अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्रीय पद्धति के अनुसार कल हरियाणा प्रदे 1 के राज्यपाल महोदय ने वर्तमान सरकार की नीतियों का उल्लेख करते हुए यह सिद्ध कर दिया है कि हरियाणा सरकार ने राज्यपाल महोदय को अपनी नीतियों की इंफर्मे 1न ठीक नहीं दी। बाबू मूल चंद जैन ने अपने भाषण में जो कुछ कहा है उससे यह सिद्ध हो जाता है कि सरकार ने अपनी नीतियों के बारे में राज्यपाल महोदय को जो कुछ लिख कर दिया है, उनमें कितना सत्य है और कितना असत्य है। इस आधार पर मैं राज्यपाल महोदय के भाषण का विरोध करने के लिये खड़ी हुई हूं। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य, चौधरी हरस्वरूप बूरा, पदासीन हुए)

राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण के पृष्ठ 2 पर यह वर्णन किया है कि सरकार ने पिछड़े वर्ग की भलाई के लिये दो करोड़ रूपये की प्राधिकृत पूंजी लगाकर एक निगम की स्थापना की है। मैं पूछना चाहती हूं कि दो करोड़ रूपया खर्च करके निगम तो स्थापित कर दिया लेकिन जो एजुके 1न व ट्रेनिंग सेंटर है उन में पिछड़ी जातियों के लिये रिजर्वे 1न केवल दो परसेंट है और इसके मुकाबले में सर्विसिज के लिये दस परसेंट की रिजर्वे 1न है। एजुके 1न व ट्रेनिंग सेंटर में दो परसेंट की रिजर्वे 1न से ये लोग ि 1क्षा प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे टैक्नीकल ि 1क्षा हो चाहे दूसरी ि 1क्षा हो अगर रिजर्वे 1न की परसेंटेज दो होगी तो वे दस परसेंट नौकरियां कैसे ले सकेंगे?

इनकी पोस्टें खाली रहेगी और जो लाभ इनको होना चाहिए वह नहीं हो सकेगा। इसलिये ऐजुके इन व ट्रेनिंग सेंटर्ज में दो परसेंट रिजर्व इन की बजाय दस परसेंट रिजर्व इन होनी चाहिए ताकि वे दस परसेंट नौकरियां ले सकें।

सभापति महोदय, आवास के लिये सरकार ने बड़े जोर- जोर से बताया श्री सुमेर चंद भट्ट ने भी आवास के बारे में बड़े जोर- जोर से चर्चा की है। मैं यमुनानगर की आवास कालोनी की चर्चा करना चाहती हूँ। यमुनानगर में हाउसिंग बोर्ड ने आवासन दिया था कि वहां पर कालोनी बनायेंगे और लोगों ने चार लाख रूपया पिछले दो वर्ष से बोर्ड को दिया हुआ है। लेकिन अभी तक वहां पर भूमि भी एक्वायर नहीं की गई। लोगों का पैसा ब्लॉकड पड़ा हुआ है। पैसा जमा करने वाले वे लोग थे जो मध्यम श्रेणी से ताल्लुक रखते हैं इसी प्रकार 1970-72 का एक केस सैक्रेटेरिएट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। कोन नहीं जानता कि यमुनानगर एम्प्लूवमेंट ट्रस्ट ने वहां पर सरोजिनी नगर बनाया। सब जानते हैं और इसके लिये 1970 में 26 एकड़ जमीन एक्वायर कर ली गई थी लेकिन सरकार ने अभी तक उस जमीन का पूरा कम्पंसें इन भी नहीं दिया, केस बड़ी देर से पेंडिंग पड़ा हुआ है। 1973 में 185 प्लॉट अलाट किए गए और उसके बाद 1975-76 में 200 और प्लॉट अलाट किए। इस तरह 22 लाख रूपया सरकार ने अब तक कालोनी के लिये खर्च किया और आज तक 35 लाख रूपया लोगों से कि तों के रूप में ले लिया। आप देखें धारा

24-28 के अनुसार प्लॉट व मकान खरीदने की इजाजत तो लोगों को दे दी लेकिन इसके बाद जिस धारा के अंतर्गत इनको पोज़े देना चाहिए था वह अब तक नहीं दिया गया। सन् 76-77 में 79 मकान दो दो कमरों के सैट के अलाट कर दिये गए जिनकी बीस वर्ष में किंताें समाप्त होनी थी। 21 मकान आधे से अधिक तैयार करके अधूरे छोड़ दिये। सरकार ने जो रूपया खर्च किया है। उसके अगैस्ट 26 लाख रूपये का अवार्ड आ गया है जो सरकार ने देना है। इसके अतिरिक्त चार लाख रूपया ठेकेदारों को देना है। कुछ लोग जिनको मकान अलाट हो गए है उनको न नालियों की सुविधा है, न सफाई की सुविधा है और न बिजली की सुविधा है। मध्यम श्रेणी के लोग जिन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर अपने मकान ट्रस्ट से ले लिए है आज तक सरकार उनका फैसला नहीं कर पाई और धारा 42 के अंतर्गत जो स्वीकृति मिलनी चाहिए थी वह नहीं दी गई। फाइल सरकार के पास पड़ी है ड्राफ्ट नोटिफिके ान को सरकार ने स्वीकृति देनी है। ट्रस्ट टूटने से सारी स्कीम ने उस कालोनी के लोगों को दुखी व परे ान किया हुआ है। क्या आप इस सरकार से उम्मीद कर सकते है कि यह गरीबों को रहने के लिए मकान बना कर देगी? जो सरकार लोगों को दिया हुआ आ वासन पूरा हीं कर सकती वह गरीबों को मकान बना कर कैसे देगी? आप इस बात का अंदाजा डिपार्टमेंट के अधिकारियों से पूछ कर लगा सकते है कि लोगों ने इसी कालोनी के कितने रिमाईंडर दिये है।

सभापति महोदय, राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में प्रोडक्शन के बारे में कहा। यमुनानगर एक बड़ा इंडस्ट्रियल कम्प्लैक्स है जिस में मजदूरों की बहुत बड़ी तादाद काम करती है। इसी तरह फरीदाबाद भी इंडस्ट्रियल कम्प्लैक्स है, लेनि मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि यमुनानगर इंडस्ट्रियल कम्प्लैक्स और फरीदाबाद इंडस्ट्रियल कम्प्लैक्स को फ़ैसिलिटीज प्रोवाइड करने में भेदभाव बरता जाता है। मैं जानना चाहती हूँ कि इन में इतना अंतर क्यों है? रैवेन्यू की दृष्टि से अगर देखें तो यमुनानगर से सबसे ज्यादा रैवेन्यू आता है लेकिन क्या यमुनानगर के मुकाबले में फरीदाबाद में उद्योगपतियों से धन की बड़ी बड़ी थैलियां अधिक मिलती है। मैं जानना चाहती हूँ कि यमुनानगर इंडस्ट्रियल कम्प्लैक्स के साथ इतना भेदभाव क्यों बरता जाता है? फरीदाबाद को ज्यादा बिजली क्यों दी जाती है? यमुनानगर इंडस्ट्रियल कम्प्लैक्स को अक्सर तीन-चार घंटे या ज्यादा से ज्यादा पांच घंटे बिजली दी जाती है। बिजली कम मिलने की वजह से बहुत मजदूर बेकार हैं, उनके साथ क्या बीत रही है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त बिजली सप्लाई का कोई समय निर्धारित नहीं है। अगर समय निर्धारित हो तो मजदूरों को काम पर जाने की आदत पड़ी रहती है और वह अपने आप समय पर इंडस्ट्रीज में पहुंच जाते हैं। इस अनियमितता के कारण कई मजदूरों को नुकसान हो गया, किसी की उंगलियां कट गईं और किसी का हाथ कट गया। ऐसे 40 केस पिछले दो मास में यमुनानगर में हुए हैं। जितने भी प्राइवेट

कारखानेदार है वे इतना कम्पन्सै इन मजदूरों को नहीं देते, जितना मिलना चाहिए। इसलिए मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि प्रोडक् इन कहां बढ़ी है? राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि इंडस्ट्रीज के माध्यम से, कृषि क्षेत्र में खेती सिसक रही है। इंडस्ट्री भी सिसक रही हैं। इंडस्ट्रीज के बारे में तो मैंने अभी बताया कि किस प्रकार की हालत सरकार ने पैदा कर दी है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में थर्मल प्लांट्स की बात कही। आप बतायें, कौन सा थर्मल प्लांट आज हरियाणा में ठीक चल रहा है। थर्मल प्लांट को कोयला नहीं मिलता और अगर कोयला मिल भी जाये तो वैगन्ज नहीं मिलती। इस सरकार के आने के बाद हरियाणा में थर्मल प्लांट्स की बड़ी दुर्द गा हुई। आप कितने ही नये थर्मल प्लांट्स या नये पावर हाउसिज की स्कीम बना ले, उससे कोई फायदा नहीं होगा। देखना यह है कि हरियाणा को बिजली मिली कितनी है, छोटे उद्योग धंधों को बिजली से कितना लाभ हुआ है, यह देखने वाली बात है। रावी-ब्यास के पानी के बारे में हरियाणा के लोगों को इतना आ वासन देने के बावजूद भी उनके साथ धोखा किया जा रहा है और हरियाणा की जनता को मजबूरी में जीने के लिए मजबूर किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, जटलाना में साठ मैगावाट के पावर हाउस की सैक् इन हो चुकी है लेकिन आज तक जमीन एक्वायर नहीं की गई। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए स्वीकृत काम भी नहीं किया, यह आपको मानना पड़ेगा।

सभापति महोदय, यह विकलांग वर्श है। मैं सारे हरियाणा की बात नहीं करती, सिर्फ अम्बाला जिले की बात करती हूं। मैं अगर कहे वगैर नहीं रह सकती कि अम्बाला के तीन विकलांगों के केसिज मेरे नोटिस में आये है। उन्होंने एम0 ए0 बी0 एड0 पास की हुई है लेकिन उनको आज तक परमानेंट नौकरी नहीं दी गई। 1970 में उन्होंने एस0 एस0 मास्टर की ट्रेनिंग खत्म कर ली थी। अम्बाला के एक विकलांग है श्री राजेंद्र पाल भाटला, इन्होंने 73 में एम0ए0 बी0एड0 पास की थी लेकिन आज तक उनको चार या छः महीने से ज्यादा नौकरी करने का अवसर नहीं मिला। उनको हमे 11 लीव वेकेसी के अगेंस्ट लगाया जाता रहा है और वह भी दो तीन मील दूर यानी इंटीरियर में जाना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति जो विकलांग है, चल नहीं सकता, उसको इंटीरियर में जब सर्विस मिलती है तो वह कैसे जाएगा, कैसे काम कर सकता है? जब उनका जाने का नाम आता है तो वे बेचारे जाने से इंकार कर जाते है क्योंकि वे वहां तक पहुंच नहीं पाते। इस बारे में अंत में मैं तो यह कहूंगी कि विकलांग वर्श के अंदर भी यह सरकार अम्बाला जिले के तीन विकलांग सर्वश्री राजेंद्र पाल भाटला, भोर सिंह और द्वारका प्रसाद गुप्ता को नौकरी नहीं दे सकी तो विकलांग वर्श कैसा? घोशणाओं से तो जन साधारण को धोखा देने वाली बात है।

(13.00 बजे)

सभापति महोदय, शिक्षा का स्तर हमारे यहां दिन प्रति दिन गिरता जा रहा है। आपको याद होगा कि जनता सरकार ने प्राइवेट कालेजों को 75 प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया था लेकिन उसके लिए भी आज वे परेशान हो रहे हैं। इस बढ़ती हुई महंगाई में जबकि हर चीज की कीमत दिन प्रति दिन बढ़ती चली जा रही है, अगर एक अध्यापक को वेतन न मिले तो वह अपने परिवार को क्या खिलाएगा? (विघ्न) गांधी आर्ट्स कालेज, संभालखा के टीचर्स को दस महीने से वेतन नहीं मिला है, डी०ए०वी० कालेज, हसनगढ़ के टीचर्स को छः महीने से वेतन नहीं मिला है, जनता कालेज, दादरी के टीचर्स को चार महीने से वेतन नहीं मिला है और गुरु नानक खालसा कालेज, करनाल को दस महीने से वेतन नहीं मिला है। अब आप ही बताइए कि दस-दस महीने से अगर टीचर्स को तनखाह न मिले तो वे शिक्षा का स्तर क्या सुधरेगा? जिस टीचर के पेट के अंदर भोजन नहीं जाएगा वह क्या पढ़ायेगा? इस बात का जवाब सरकार को देना चाहिए। सरकार को उनकी मांग का ध्यान करके 95 प्रतिशत ग्रांट देने का विचार क्रियान्वित करना चाहिए।

इसके बाद सभापति महोदय, मैं ला एंड आर्डर के बारे में कुछ जिक्र करना चाहूंगी। आपने भी इस बारे में बड़े जोर-शोर से कहा कि हमारी स्टेट का ला एंड आर्डर ठीक है लेकिन अपने आपको हरिजनों का हिमायती कहने वाली इस सरकार से क्या मैं यह पूछ सकती हूँ कि 17 नवम्बर 1980 को

यमुनानगर में क्या हुआ था? समुनानगर में 17 नवम्बर को गांव तिगड़ी का एक हरिजन घासीराम सब्जी झोटा बुग्गी में लेकर मंडी में आया था। साढ़े आठ बजे वह घर को वापिस हुआ। रादौर रोड़ पर रेलवे फाटक के पास सवा नौ बजे उसने चाय पी। दस बजे पानसरा चुंगी के पास एक दोधी ने उसे देखा लेकिन उसके बाद उसका पता नहीं चला, पंद्रह दिन के बाद उसकी ला 1 मिली पर झोटा और बुग्गी अभी तक नहीं मिली। (विघ्न एवं भाोर)

सभापति महोदय, ला एंड आर्डर की इस स्थिति में कस्टोडियन लैंड पर नाजायज कब्जे हो रहे हैं जबकि लैंडलैस लोगो को जमीन नहीं मिल रही है। जठलाने की एक घटना में हाउस के सामने रखना चाहती हूं। वहां सुंदरराम नाम के एक रिटायर्ड पटवारी ने कस्टोडियन लैंड के आठ-दस प्लाटस पर, जिनकी कीमत लगभग 70 हजार बनती है, कब्जा किया हुआ है। उसने मरे हुए तहसीलदार के झूठे दस्तखत करके इस जमीन को अपने रि तेदार के नाम करवा रखा है। विजिलैंस की इंकवायरी हुई थी और तहसीलदार के दस्तखत झूठे पाए गये थे। लेकिन यह सुंदर दास पटवारी पैसा देकर छुट गया है और इस कस्टोडियन लैंड को उसने अपने कब्जों में रखा हुआ है।

हरियाणा के ला एंड आर्डर के बारे में अभी बाबू मूल चंद जैन जी ने भी काफी कुछ आपके सामने कहा। कौन नहीं जानता कि यहां तो ला एंड आर्डर कुरुक्षेत्र के बच्चों के ऊपर चलता है, जिनका केवल मात्र कसूर यह था कि वे राष्ट्रपति के

भाषण सुनना चाहते थे? उन्हें बड़ी बेदर्दी से पीटा गया, बसों और ट्रेनों से पकड़ पकड़ कर मारा गया। क्या यही इनका ला एंड आर्डर है?

सभापति महोदय, आपने अखबार में पढ़ा होगा कि भाहबाद में पिछले दिनों क्या हुआ? गुरुद्वारा के लिए फंड रेज करने के लिए वहां एक कल्चरल प्रोग्राम रखा गया था। पुलिस के कर्मचारियों ने जब वहां जाकर हल्ला किया तब गांव वालों ने उन्हें वहां से हटाया लेकिन इसी कसूर की बिना पर वहां नौ आदमियों को गिरफ्तार किया गया। एक सरपंच का मुह काला करके तथा जूतों का हार डाल करके जलूस निकाला गया जबकि बाद में एस0 पी0 ने उसे निर्दोश करार दिया। यह कहां का ला एंड आर्डर है? (विघ्न)

मुरथल की घटना भी सभापति महोदय, किसी से छुपी नहीं है। कौन नहीं जानता कि एक व्यापारी को डेढ़ लाख रुपये का सामान वहां किस प्रकार लूट लिया गया? वह व्यक्ति मेरा निजी जानकार है। सभापति महोदय, सरकार जवाब दे क्या यही ला एंड आर्डर है? यहां पर कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। केवल कुर्सी को बचाने के लिए कांग्रेस (आई) की गोद ली हुई यह सरकार बार बार सेंटर में जाकर के सिजदे देने में लगी रहती है। 19 अक्टूबर, 1979 को यमुनानगर में वैस्ट्रन समुना कैनल पर पुल बनने के लिए सैन्कान हो चुका है लेकिन बजट सैन्कान होने के बाद और टैंडर स्वीकृत होने के बाद भी आज

तक वहां काम भुरु नहीं हुआ जबकि अब सन् 81 आ गया है। इसी प्रकार सारे हरियाणा में विकास के काम ठप्प पड़े हैं।

सभापति महोदय, यह गरीब देा है। हरियाणा का नाम अधिक अन्न उत्पादन करने वाले प्रदेशों में दूसरा है लेकिन दुःख की बात है कि आज यहां डिपुओं में आटा नहीं मिलता, गेहूं भी बहुत महंगा मिलता है और मिट्टी का तेल लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्त्रियां और बच्चे प्रातःकाल सात बजे लाईन में खड़े हो जाते हैं लेकिन दोपहर बाद दो बजे डिपो वाला कह देता है कि तेल नहीं है और लोग निराशा होकर वापिस घर आ जाते हैं। हमें जनवरी, फरवरी और मार्च इन तीन महीनों में आटा महंगा होता है। सरकार को इसका पहले ही ध्यान रखना चाहिए। गरीब मजदूर को, जो दिन में केवल 6, 7 या 8 रुपये कमाता है, यदि महीने का केवल दस किलो आटा मिले तो वह कैसे अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। इसके लिए ये बिजली का बहाना करते हैं लेकिन यह गलत बात है क्योंकि मार्केट के अंदर दो रुपये बीस पैसे प्रति किलो आटा खुल आम बिक रहा है। सभापति महोदय, यही नहीं सीमेंट लोगों को नहीं मिलता है, किताबें ब्लैक में मिलती हैं। 6-6 महीनें तक सरकारी पुस्तक भंडार खुलने के बाद भी बच्चों को किताबें नहीं मिलती हैं। कापियां भी ब्लैक में मिलती हैं। इस सरकार को तो सभापति महोदय, अपने कार्य-कलापों के ऊपर लज्जा आनी चाहिए। (विघ्न)

सभापति महोदय, आपको यह सुन कर हैरानी होगी कि हमारे यहां हरियाणा में, जींद के अंदर जय हनुमान ट्रेडिंग के नाम से एक ऐसा ट्रेड खुला हुआ है जिसके अंदर सट्टे का व्यापार चलता है। (गोर)

चौधरी भजन लाल: सभापति महोदय, इन्हें कुछ तो मर्यादा से बोलना चाहिए। (विधन) यह इनके लीडर का हाल है। (गोर)

गृह मंत्री(श्री कन्हैया लाल पोसवाल): चेयरमैन साहब, यह मोस्ट इर-रिसर्पोसिबल रिमार्कस है। इन्हें कार्यवाही से ऐक्सपंज कर दिया जाए।

श्री सभापति: ये रिमार्कस ऐक्सपंज कर दिए जाए।

श्रीमती डा० कमला वर्मा: सभापति महोदय, यह बात सच है। स्वागत करने के बाद जींद के एक मंत्री को पौने तीन लाख रूपये का पर्स दिया गया है। (गोर)

चौधरी उदय सिंह दलाल: एक कार भी दी गई है। (गोर)

चौधरी गंगा राम: मंत्री इस्तीफा दे। (गोर)

श्रीमती डा० कमला वर्मा: सभापति महोदय, भ्रष्टाचार का यहीं अंत नहीं है। मैं कुछ महीने पूर्व की बात आपको बताती हूं। जगाधरी की इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की एक मीटिंग हुई।

उस समय के वित्त मंत्री श्री बलवंत राय तायल जी उपस्थित थे। उन्होंने ऐसोसिएशन को यह आवासन दिया था कि तुम्हारा सेल्ज टैक्स चार प्रतिशत से एक प्रतिशत कर दिया जाएगा। यदि तुम मुझे मुख्य मंत्री जी को देने के लिए दो लाख रूपया दे दो। दो लाख रूपया भूतपूर्व वित्त मंत्री को इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने दिया। अगर उनका टैक्स कम कर दिया जाता तो उनको अफसोस न होता लेकिन वह टैक्स आज तक कम नहीं हुआ और न ही वह पैसा उन्हें वापिस किया गया। पिछले दिनों तायल साहब ने कहा था कि वह पैसा मुख्य मंत्री को दे दिया है। क्या वह पैसा मुख्य मंत्री जी को मिल गया है या नहीं यह बात पब्लिक के सामने आनी चाहिए। (गोर)

चौधरी गंगा राम: मुख्य मंत्री जी इस बात का जवाब दें। (गोर)

चौधरी भजन लाल: चेयरमैन साहब हम इनकी सब बातों का जवाब देंगे, ये सुनने का कष्ट तो करे। (गोर) हर प्वायंट नोट हो रहा है और उसका जवाब दिया जाएगा।

श्रीमती डा० कमला वर्मा: हरियाणा में भ्रष्टाचार दिन प्रति दिन बड़ी तीव्र गति से बढ़ रहा है। आप एक इन्कवायरी कमीशन बैठा दें उससे पता चल जायेगा। आप सभी को मालूम है कि पिछले दिनों मुख्य मंत्री और भूतपूर्व वित्त मंत्री ने एक दूसरी पर खुल्लमखुल्ले ऐलीगेण्डज लगाये। उनके बारे में पता करके

जनता के सामने बताया जाए। इसलिए मेरी गुजारि 1 है कि कमी 1न बैठा कर सही बात का पता लगाया जाये कि हरियाणा में भ्रष्टाचार किस हद तक बढ़ रहा है।

मैं इन भाब्डों के साथ इस अभिभाशण का जोरदार विरोध करती हूं क्योंकि यह जन विरोधी सरकार का तैयार किया हुआ अभिभाशण है। यह सरकार करती कुछ है और कहती कुछ है।

स्वामी आदित्यवे 1(हथीन): आदरणीय सभापति जी, राज्यपाल महोदय को मराठी भाशा की बड़ी जानकारी है। प्रकांड विद्वान होते हुए भी उन्होंने अपना अभिभाशण हिंदी में पढ़ा जिसके लिए मे। उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे साथी श्री सुमेर चंद भट्ट जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका अनुमोदन करते हुए मैं कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मैं समझता था कि यहां पर बड़े सियाने और योग्य मैम्बर बैठे हुए होंगे लेकिन मुझे उनकी बातें सुनकर बड़ी हार्दिक वेदना हुई। (गोर) सभापति महोदय, एक छोटा सा पम्फलेट टेबल पर रख दिया गया। इन्होंने उस पम्फलैट को यहां पर फाड़ा। आखिर इंदिरा गांधी तो हमारे दे 1 की महान नेता है उनके चित्र को इस तरह से नहीं फाड़ना चाहिए था। मैं उनको बताना चाहता हूं कि इसको तो उन्होंने फाड़ दिया लेकिन जो लाखों और करोड़ों लोग इंदिरा गांधी के साथ है

उनके दिलों को तो यह नहीं फाड़ सकते। (गोर) इन्होंने उस चित्र को फाड़ कर अपने छोटेपन का सबूत दिया है।

श्री मूल चंद मंगला: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब ने इस मामले के बारे में कहा है कि इसकी इन्कवायरी की जायेगी तो फिर इस बात पर अब बोलने की क्या आवयकता है? (गोर)

श्रीमती सुशमा स्वराज: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। इन्होंने इंदिरा गांधी जी को महान नेता कहा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब उन्हें मीसा में बंद किया गया था तब भी वे महान नेता थीं?

स्वामी आदित्यवे I: जी हां। महान नेता थी। (गोर) सभापति महोदय, इसी सदन में लोकदल का घोशणापत्र रखा गया था लेकिन किसी भी सदस्य ने कोई एतराज नहीं किया था लेकिन आज इन साथियों की हरकत देख कर बड़ी वेदना हुई। मैं तो यह कहूंगा कि जिस आदमी को हमे गा ठोकरें लगी हों, किसी का अपमान किया हो, वह दूसरे की इज्जत नहीं कर सकता। इसलिए इस प्रकार से चित्र को फाड़ना भाोभा नहीं देता। (गोर) सरकार ने बहुत ही गरिमामय अभिभाशण राज्यपाल महोदय की ओर से रखवाया है। इसके लिए मैं अपनी सरकार और अपने अधिकारियों को बधाई देता हूँ। मैं यह भी कहे बिना नहीं रहूंगा कि आज तक हमारी योजनाओं के लिए इतना रूपया नहीं मिला था जितना

छठी पंचवर्षीय योजना के लिए मिला है। 1800 करोड़ रुपया हरियाणा के लिए मिला है। हमारे प्रदेश का बड़ा सौभाग्य है कि केंद्र की नेशनल डिवैल्पमेंट कौंसिल ने इसे स्वीकार किया है। उड़ीसा जैसे प्रदेश के लिए केवल 2100 करोड़ रुपया रखा है और भी प्रदेश है जिनके लिए हमारे से कम रुपया रखा। हमारे प्रदेश के लिए इतनी अधिक मात्रा में रुपया मिलना यह सब चौधरी भजन लाल जी के विशेष प्रयास का फल है। 1981-82 की वार्षिक योजना के लिए पहले 219 करोड़ रुपया रखा गया। फिर इसको बढ़ा कर 253 करोड़ कर दिया गया और आज उस 253 करोड़ को बढ़ा कर 290 करोड़ कर दिया गया है। इस पैसे से सारे हरियाणा प्रदेश के विकास कार्य किये जायेंगे। (गोर)

सभापति महोदय, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कोई भी काम करो, उसके करने से पूर्व गरीबों की तस्वीर को अवश्य सामने रखो। ठीक उसी के अनुरूप अभिभाषण में किया गया है। इस सारे अभिभाषण में जो कि बीस पृष्ठ के करीब है, 11 अनुच्छेद में गरीबों के उत्थान की बात की गई है। सब से बड़ी बात तो यह है कि आज तक हमें यह भी पता नहीं कि हमारे प्रदेश में कितने परिवार गरीबी की रेखा के नीचे है। हमारी यह सरकार बधाई की पात्र है कि इसने उंगलियों पर गिन लिया कि तीन लाख 21 हजार परिवार गरीबी की रेखा से नीचे है। आगे आने वाली योजना के अंतर्गत सब गरीब परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जायेगा। यह कितना बड़ा कार्य सरकार

करने जा रही है? सभापति महोदय, इन लोगों में तो सुनने की भी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि इस अभिभाषण में सभी विकास की बातें पढ़ी गई थी लेकिन ये उनको भी न सुन सके और हाउस से उठ कर बाहर चले गए। राज्यपाल महोदय सदन में रोजाना तो आते नहीं। वे तो साल में एक बार आते हैं। इन्होंने मर्यादा का भी सबूत नहीं दिया। कम से कम इनको बैठ कर सुनना चाहिए था और आज ये भारतीय संस्कृति के दावेदार बनते हैं। अभी हिंदी के दावेदारों ने सदन में एक मोड़ान मूव किया तो खड़े होकर अंग्रेजी में पढ़ने लग गये। मैं तो हैरान रह गया कि कहां कि हिंदी पढ़ रहे हैं। क्या ये ब्रिटेन की हिंदी पढ़ रहे थे या किसी और देश की हिंदी पढ़ रहे थे। (गोर) ये कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। (गोर) अभी बहिन कमला वर्मा बोल रही थी। मैं उनके विषय में कुछ अधिक नहीं कहना चाहता क्योंकि वे मेरी पूज्य बहिन हैं लेकिन इतना जरूर आप लोगों के नोटिस में लाना चाहता हूं कि.....
.....। (गोर)

श्रीमती डा० कमला वर्मा: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। मैं इसे चैलेन्ज करती हूं अगर ये सिद्ध कर दें तो मैं इस हाउस से अस्तीफा दे दूंगी। अगर ये सिद्ध न कर पाये तो ये दे दें। (गोर)

डा० मंगल सैन: चेयरमैन साहब, मेरा भी प्वायंट आफ आर्डर है। (गोर)

श्री सभापति: डा० साहब, आपके बारे अगर कोई कहेगा तभी तो आप प्वायंट आफ आर्डर रेज करेंगे।

चौधरी भजन लाल: सभापति महोदय, इन्होंने भी अभी इल्जाम लगाये थे, हम बड़ी भांति के साथ सुनते रहे। अब इनको हमारी बात को भी बड़ी भांति के साथ सुनने का कष्ट करना चाहिए।

डा० मंगल सैन: सभापति महोदय..... (10र)

श्री सभापति: डा० साहब, आप बैठिए। (10र)

डा० मंगल सैन: आप मेरी बात तो सुनिये। (10र)

श्री सभापति: आप किस बात पर बोलेंगे?

डा० मंगल सैन: मैं आपकी रूलिंग चाहता हूँ। क्या इस हाउस में इस बात को कहा जा सकता है कि किस आदमी ने हवन कराने के कितने रुपये लिए? (10र)

स्वामी आदित्यवे 1: सभापति महोदय,.....
.....। (10र)

श्री सभापति: आप मैम्बर को बोलने दीजिए। बहिन जी ने चैलेंज कर दिया है। वे तरीका जानती है। (10र)

डा० मंगल सैन: सभापति महोदय, यहां पर सैन योर मो आन आ सकता है। लेकिन जब तक किसी एलीगे आन को

सबस्टॉपिंग एट ने किया जाए, उसके बिना यह बात नहीं की जा सकती यहां पर ऐसा कोई मोशन नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: अगर आप गलत समझते हैं तो एक्सपंज हो जायेगा। खुद बहिन जी चैलेंज कर रही हैं। अगर आप गलत समझते हैं तो बतायें और अगर चैलेंज करते हैं तो बतायें। (गोर)

डा० मंगल सैन: मैं यह कहता हूँ कि वे चैलेंज तो खुद करे लेकिन आप जो प्रोसिजरली अलाऊ कर रहे हैं, यह गलत है।

श्री सभापति: क्या आप डिमांड कर रहे हैं कि इसको एक्सपंज कर दिया जाये?

डा० मंगल सैन: मैं यह भी डिमांड कर रहा हूँ। लेकिन यह प्रोसिजरली गलत है। (गोर)

श्री सभापति: राखी वाली बात एक्सपंज कर दी जाये।

डा० मंगल सैन: सभापति महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूँ। (गोर)

श्री सभापति: वे भाब्द एक्सपंज हो चुके हैं, अब आप बैठिए। जब कोई इन्टर आयेगा तभी तो आप कोई प्वायंट उठायेंगे। आप हाउस की कार्यवाही को चलने दें। (गोर)

डा० मंगल सैन: मेरा सुझाव यह है कि बहिन जी ने चैलेंज किया है इसलिए हाउस की एक कमेटी बना दीजिए।

श्री बलदेव तायल: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर।

श्री सभापति: आपका किस बात पर प्वायंट आफ आर्डर है? हाउस के सामने कोई बात आये तभी तो आप प्वायंट आफ आर्डर उठायेंगे। अब आप बैठिए। (गोर) प्वायंट आफ आर्डर डा० कमला वर्मा ने रेज किया था। अब आप लोग बैठिए। कोई इ पू आये तो आप प्वायंट आफ आर्डर रेज करे। एक प्वायंट आफ आर्डर होता है। प्वायंट आफ आर्डर पर प्वायंट आफ आर्डर नहीं होता। आप बैठिए। (गोर) जब कोई प्वायंट आफ आर्डर उठाने का मौका आयेगा तो उठा लेना। एक प्वायंट आफ आर्डर आया था उसको मैंने ले लिया। आप खुद पढ़े—लिखे आदमी है इसलिए हाउस की कार्यवाही चलने दें। (गोर)

श्री बलदेव तायल: एक इ पू पर 5-6 प्वायंट आफ आर्डर हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं हो सकती।

श्री सभापति: आप रूल को कोट कर दें लेकिन अब आप बैठिए। (गोर)

श्रीमती डा० कमला वर्मा: मैंने चैलेंज किया है कि यह मामला प्रिविलेज कमेटी में जाना चाहिये।

श्री सभापति: यह प्रोपर रास्ता है। आप इस मामले को प्रिविलेज कमेटी में भेजने के लिए नोटिस भेज दीजिए।

स्वामी आदित्यवे 1: सभापति महोदय, बाबू मूल चंद जैन बहुत पुराने सदस्य है उनको तो इस गरिमामय सदन में सही बात कहनी चाहिए थी लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि उन्होंने भी सही बातें नहीं कहीं। राज्यपाल के अभिभाषण के पेज दो, पैरा पांच पर लिखा हुआ है कि 3.21 लाख गरीब परिवार है। उनके उत्थान के लिए, उन्हें आर्थिक दृष्टि से आत्म निर्भर बनाने के लिए स्पै ल कम्पोनैट प्लान चालू की गई जिसके द्वारा उनको विकसित किया जायेगा। लेकिन बाबू मूल चंद जैन जी ने तो ऐसा किया कि जैस उनको दिखायी ही न दिया हो और सारी दुनियां को वही ठीक कर सकते हों।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: आप औरों को भी बोलने दें। (गोर)

श्री सभापति: आप बैठिए।

स्वामी आदित्यवे 1: सभापति महोदय, जब बाबू मूल चंद जैन वित्त मंत्री थे तो इन्होंने जो बजट पे 1 किया था उसमें इन्होंने किसानों पर आबियाना बढ़ाया था और आज ये किसानों के लिए आंसू बहा रहे है। इन्होंने किसानों पर दस परसेंट आबियाना बढ़ा दिया तो यहां बैठे हुए बहुत से माननीय सदस्यों ने बजट की कापियों की धज्जियां उड़ा दी थीं, यानी उनको फाड़ कर फेंक दिया था। उस दिन वे किसानों के बारे में एक भी भाब्द नहीं कह सके थे। सभापति महोदय, अभी भाराब का जिक

किया गया। (गोर) जब मैंने भूख हड़ताल की थी उस समय बाबू मूल चंद जैन जी वित्त मंत्री हुआ करते थे। मैंने कहा था कि हरियाणा के देहातों में भाराब बंद होनी चाहिए तो मूल चंद जैन जी एक भी भाब्द सवेदना के रूप में व्यक्त नहीं कर सके। बाबू मूल चंद जैन तो खुद भाराब पीते हैं और वे ऐसे सम्प्रदाय से संबंधित हैं जो इन्हें इजाजत नहीं देता। इस बारे में वे काफी ठीक आदमी हैं। चौधरी सतबीर सिंह मलिक आज भाराब की बात कहते हैं उन्होंने तो लाटरियां निकाल दी थीं और चौधरी संत कंवर जी बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा था कि सब को एक एक ठेका दे दें।

Dr. Mangal Sein: I want to draw your kind attention to rule 265 of the Rules of Procedure and Conduct of Business which says-

“The Speaker may, if he is satisfied about the urgency of the matter, allow a question of privilege to be raised at any time during the course of a sitting. Such question shall be raised at the earliest opportunity and shall not ordinarily require notice.”

Mr. Chairman: If he is satisfied.

डा० मंगल सैन: इसका मतलब यह है कि वे जो चाहे इल्जाम लगा दें।

श्री सभापति: बैठिये, मैंने उसके बारे में बता दिया था। Rule is very much clear that if the Speaker is satisfied about

the urgency of the matter, he can allow a question of privilege to be raised at any time.

Dr. Managal Sein: Are you satisfied or not.

श्री सभापति: मैं सैटिसफाईड नहीं था इसलिए मैंने मौका नहीं दिया। (गोर)

डा० मंगल सैन: मैंने प्वायंट आफ आर्डर रेज किया है कि नोटिस की भी जरूरत नहीं है। (गोर)

श्री सभापति: मैंने नोटिस के लिए कह दिया है। आप नोटिस देने की तकलीफ कर लें।

डा० मंगल सैन: इस का मतलब यह हुआ कि आप इसको इस समय रेज करने की इजाजत देने की जरूरत नहीं समझते। (गोर)

श्री सभापति: जरूरत है या नहीं है यह बात चेयर ने देखनी है। (गोर) बहिन जी ने चैलेंज किया है और उस चैलेंज को देखते हुए मैंने अपनी सैटिसफैक्ट इन नोटिस लेने में समझी है। वह नोटिस दे दें। (गोर) मलिक साहब, आप किस पर प्वायंट आफ आर्डर करना चाहते हैं?

चौधरी सतवीर सिंह मलिक: मैं बाबा की बात पर प्वायंट आफ आर्डर करना चाहता हूँ। (गोर)

श्री सभापति: देखिए मलिक साहब, आप उस तक अपनी बात सीमित रखिये। लेकिन पर्सनल ऐसप न न करें। टाईम जाया हो रहा है। (गोर)

चौधरी सतवीर सिंह मलिक: मैं आपसे एक्साईज पालिसी की बाबत प्रार्थना करना चाहता हूं। (गोर)

श्री सभापति: मलिक साहब, आप बैठिये। आपको बोलने का मौका मिलेगा। (गोर) मैम्बर साहब को बोलने दीजिए। (गोर)

स्वामी आदित्यवे I: चेयरमैन साहब, मैं कह रहा था.....

.....

श्री सभापति: अब सदन कल, बुधवार, दिनांक 11-3-1981, प्रातः 9.30 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

(13.30 बजे)

(तत्प चात सदन बुधवार, दिनांक 11-3-1981, प्रातः 9.30 बजे तक के लिये स्थगित हुआ)